ISSN-0971-8397

योजना

सितम्बर 2015 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 10

स्मार्ट सिटी: शहरों की बदलती तस्वीर

स्मार्ट शहर: अवधारणाएं व रणनीति
आर बी भगत

विकास के संचालक के रूप में शहर
ईशर अहलूवालिया

स्मार्ट शहर में डिजिटल गवर्नेंस
आर चंद्रशेखर

स्मार्ट शहर: भारतीय संदर्भ
उषा पी. रघुपति

फोकस
राष्ट्रपति भवन: एक स्मार्ट धरोहर टाउनशिप
सुरेश यादव

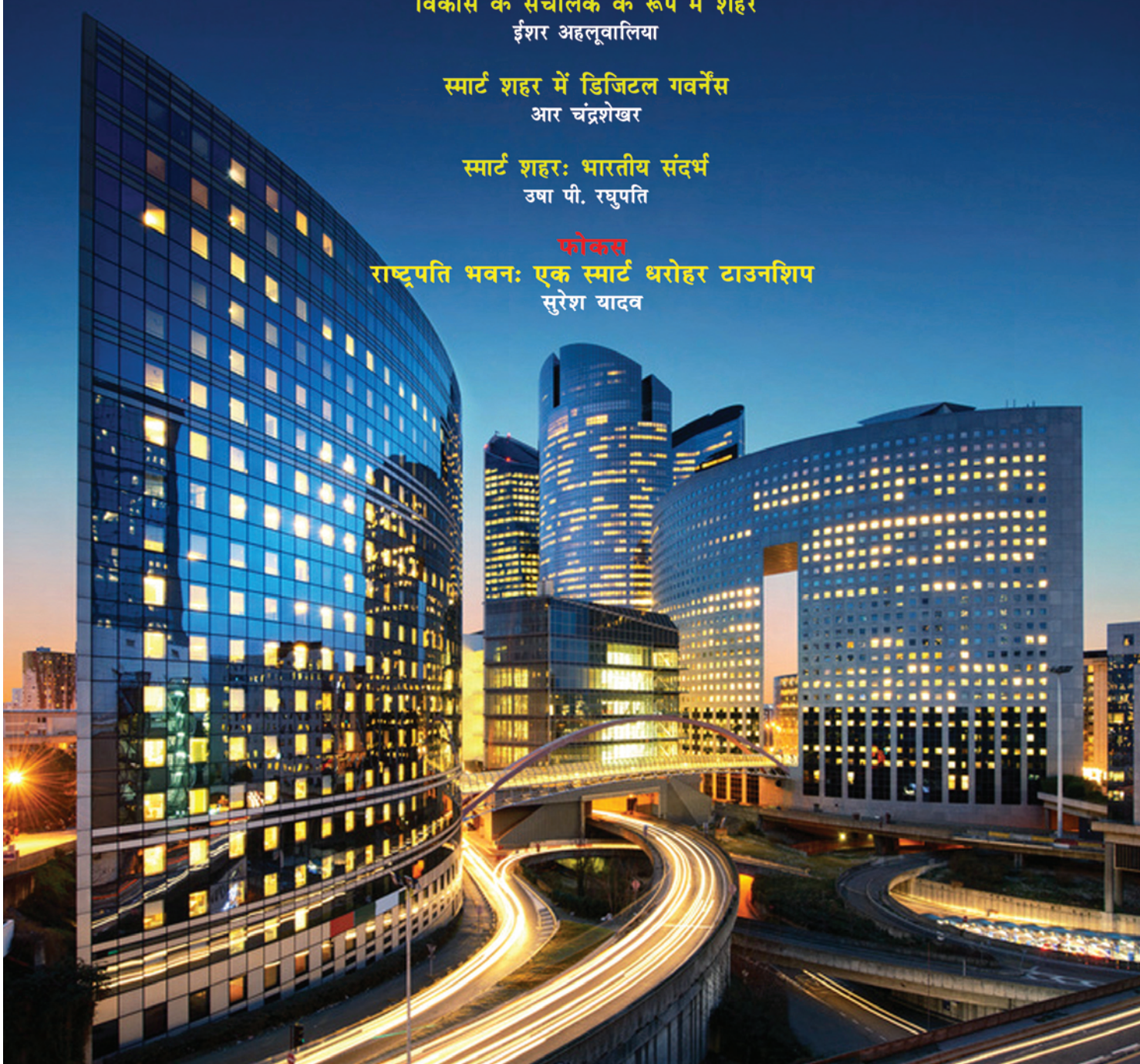

विकास पथ

प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस संबोधन: मुख्य बातें

- भ्रष्टाचार मिटाने और भारत को 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक - विकसित राष्ट्र बनाने के 125 करोड़ भारतीयों की 'टीम इंडिया' के संकल्प को दोहराया।
- प्रशासन के विभिन्न पक्षों से भ्रष्टाचार मिटाने में कोयले, स्पेक्ट्रम और एफएम रेडियो लाइसेंस की नीलामी की भूमिका सामने रखी।
- एलपीजी सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण की पहल योजना, जिससे 15,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
- 'नीम की परत वाला यूरिया' आया, जिसने सब्सिडी वाले यूरिया का गैर कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल खत्म करने में मदद मिली।
- काले धन के विरुद्ध अभियान में महत्वपूर्ण कदम उठाए, अघोषित संपत्ति का विदेशों में जाना रोक दिया।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से 17 करोड़ बैंक खाते खुलने से वित्तीय समावेशन को बड़ा प्रोत्साहन मिला। जन धन खातों में जमा 20,000 करोड़ रुपये 'भारत के गरीबों की अमीरी' के प्रमाण हैं।
- 50,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आरंभ की।
- केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई कल्याण योजनाएं, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। श्रमिक कल्याण के लिए भी योजना आरंभ की गई।
- सभी स्कूलों में शौचालय का वायदा राज्यों के सहयोग से लगभग पूरा हो गया।
- बच्चों को 'स्वच्छ भारत अभियान' का सबसे बड़ा ब्रांड एंबेसडर बताया। इस सपने ने भारत की जनता के प्रति बड़ी दिलचस्पी जगाई है।
- **'स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया'** कार्यक्रम की घोषणा की, जिससे भारत के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा। 1.25 लाख बैंक शाखाओं में से प्रत्येक को कम से कम एक दलित अथवा आदिवासी उद्यमी को और कम से कम एक महिला उद्यमी को प्रोत्साहित करना चाहिए। ❑

पुडुचेरी: पहला स्मार्ट शहर

स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा के एक महीने के भीतर ही पुडुचेरी इस मिशन के लिए नामांकित होने वाला पहला शहर बन गया है। नामांकन सिटी चैलेंज प्रतिस्पर्द्धा के पहले चरण में आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ अग्रसारित किया गया, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश के पांचों शहरी स्थानीय निकायों (पुडुचेरी, औलगरेट, कराइकल, माहे और यनम) के मूल्यांकन का विवरण भी शामिल था।

6.57 लाख की आबादी वाले पुडुचेरी, ने पहले चरण के विभिन्न मूल्यांकन मानदंडों में 100 में से 75 अंक लेते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। इसने घरों में शौचालय की व्यवस्था में 2011 की अपेक्षा 18 प्रतिशत सुधार किया है, 2012 से 2015 के बीच लगातार तीन वर्ष तक आंतरिक राजस्व सृजन में वृद्धि की है और 14 प्रतिशत सुधार किया है, कर्मचारियों को पिछले महीने तक का वेतन दे दिया है, 2012-13 तक के खातों की ऑडिटिंग करा ली है, 2014-15 में कर राजस्व, शुल्कों, यूजर चार्ज, 63 प्रतिशत बजटीय प्राप्तियां किरायों तथा अन्य आंतरिक संसाधनों से हासिल की हैं, 23 प्रतिशत पूंजीगत व्यय आंतरिक संसाधनों से किया है, जलापूर्ति के परिचालन एवं प्रबंधन की 80 प्रतिशत लागत यूजर शुल्क के माध्यम से निकाली है, शिकायत निपटारे की ऑनलाइन प्रणाली स्थापित की है और मासिक ई-न्यूज लेटर प्रकाशित किया है तथा पिछले दो वित्त वर्षों के लिए नगर पालिका के बजटीय व्यय का ब्योरा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया है।

जैसा कि स्मार्ट सिटी मिशन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक है, पुडुचेरी सरकार ने स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव तैयार करने के लिए सलाह देने और उसका समन्वय करने हेतु अंतर विभागीय कार्य बल गठित करने के आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की है। शहरी आबादी, शहरी स्थानीय निकायों की संख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के लिए स्मार्ट सिटी निर्धारित करने के मानदंड के अनुसार और भौगोलिक समानता सुनिश्चित करने के लिए पुडुचेरी को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एक स्थान दिया गया है।

जब से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने नामांकन भेजने के लिए कहा गया है तभी से शहरी विकास मंत्रालय 'सिटी चैलेंज' के पहले चरण की प्रगति के विषय में सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के संपर्क में है।

ग्रामीण विद्युत सुधार

ग्रामीण क्षेत्रों को चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने की योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने 25 जुलाई, 2015 को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) आरंभ की।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सुधार करने के लिए इस योजना के अंतर्गत ये कदम उठाए जाएंगे:

- सभी गांवों का विद्युतीकरण
- किसानों के घरों की विद्युत आपूर्ति को मुख्य आपूर्ति से अलग करना ताकि किसानों के लिए पर्याप्त बिजली सुनिश्चित हो सके
- उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों को मजबूत बनाकर विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बढ़ाना
- मीटर लगाकर विद्युत ह्रास को कम करना

इससे ग्रामीण घरों में चौबीसों घंटे बिजली एवं कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलने की अपेक्षा है। योजना में 76,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं, जिसमें 63,000 करोड़ रुपये का अनुदान भारत सरकार की ओर से है। पहले ही 14,680 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

योजना से सभी गांवों का विद्युतीकरण करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने, लघु एवं कुटीर उद्यमों में विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए द्वार खोलने, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, दूरसंचार एवं अन्य सेवाओं के विस्तार में सहायता मिलेगी। इससे विद्यालयों, पंचायतों, अस्पतालों तथा पुलिस थानों जैसी सेवाओं को बिजली की गारंटी भी मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। ❑

योजना

वर्ष : 59 • अंक 8 • सितंबर 2015 • भाद्रपद-आश्विन, शक संवत 1937 • कुल पृष्ठ : 60

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

उपसंपादक: भुवनेश

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971
ईमेल: yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट: www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
http://www.facebook.com/yojanahindi

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी.के. मीणा

सहायक निदेशक (प्रसार): पद्म सिंह

(प्रसार एवं विज्ञापन)
ईमेल: pdjucir@gmail.com

आवरण: जी. पी. धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

सहायक निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है।

इस अंक में

- **संपादकीय** 7
- स्मार्ट शहर: अवधारणाएं एवं रणनीतियां
  आर. बी. भगत 9
- विकास के संवाहक हैं शहर
  ईशर अहलूवालिया 13
- स्मार्ट शहर: भारतीय संदर्भ
  उषा पी रघुपति 17
- स्मार्ट शहरों में डिजिटल गवर्नेंस
  आर चंद्रशेखर 21
- **फोकस**
  राष्ट्रपति भवन: एक स्मार्ट धरोहर टाउनशिप
  सुरेश यादव 24
- गांव होंगे स्मार्टनेस की असली कुंजी
  संजय श्रीवास्तव 33
- पर्यावरण भी रहे स्मार्ट
  प्रभांसु ओझा 35
- सुरक्षित एवं आपदा मुक्त शहर
  आर के भसीन 39
- शहरी कायाकल्प मिशन: कार्यान्वयन रणनीति
  राकेश रंजन 43
- शहरी नियोजन: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
  पवन कुमार शर्मा 49
- **क्या आप जानते हैं?** 53
- सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी कदम
  आर सी राजामणि 54
- स्मार्ट सिटी: अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण
  शिवानंद द्विवेदी 56

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष: 24367260, 5610)
हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष: 23890205)
701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष: 27570686)
8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030)
'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष: 24917673)
प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुअनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650)
ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383)
फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष: 25537244)
बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2683407)
हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष: 2225455)
अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669)
के. के. बी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष: 2665090)

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

दरें: वार्षिक: ₹ 100 द्विवार्षिक: ₹ 180, त्रिवार्षिक: ₹ 250, विदेशों में वार्षिक दरें: पड़ोसी देश: ₹ 530, यूरोपीय एवं अन्य देश: ₹ 730

आपकी राय

उपयोगी अंक

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नये आयामों की पड़ताल करता हुआ जुलाई अंक लाजवाब रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि कोई देश अपने पड़ोसी देशों के संपर्क में नहीं है, तो उस देश के आर्थिक विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कई देशों की यात्रा कर भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नई ताजगी प्रदान की। भारत में उपलब्ध संसाधनों का समायोजित तरीके से उपयोग कर विकास की नई राह लिखने के लिए यह बेहद जरूरी भी था। अच्छी और उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

छैल बिहारी शर्मा 'इन्द्र'
छाता, उ.प्र.

विश्व एकः हम सबका

अब जबकि हमारा देश भारत विश्व मंच पर अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। समय आ गया है कि स्वयं का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनाने के साथ ही विश्व भर के समस्त देशों को भी योगदान देने की ओर हम सोचें। योजना के जुलाई 2015 अंक में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नये आयाम संबंधी जानकारियां पसंद आईं। भारत का विश्वभर के देशों से जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार है वह किसी से छिपा नहीं है, विकासशील से विकसित देश का सफर पूरा होना ही है। भारत का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए हम सब नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

सुरेश दीवान
अकोली, रायपुर, छत्तीसगढ़

वैकल्पिक चिकित्सा के विभिन्न पहलू

मैं योजना पत्रिका का नियमित पाठक रहा हूं लेकिन आजकल पत्रिका नहीं मिलने की वजह से मैं पत्रिका पढ़ भी नहीं पा रहा हूं और न लिख भी रहा हूं। पत्रिका के लिए 30 किलोमीटर दूर छपरा जाना पड़ता है। तब पत्रिका पढ़ता और लिखता हूं। इस पत्रिका के जून अंक में छपे सभी विद्वानों के लेख काफी सराहनीय हैं। इस पत्रिका के छपे लेख ज्ञानवर्धक, जानकारियों से भरपूर हैं। वैकल्पिक चिकित्सा के कई पहलू हैं जो काफी मददगार हो सकते हैं।

वैकल्पिक चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं में योग, आयुर्वेद, होमियोपैथी काफी महत्वपूर्ण हैं जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक चिकित्सा सरल, सस्ती और सुलभ है। इसके द्वारा कम खर्च में निरोग काया हो जाती है। वैकल्पिक सभी को मालूम नहीं है। मालूम भी है तो लोगों में पहले कुछ नकारात्मक प्रकृति देखी जाती है और जब रोग बढ़ जाता है तब तक काफी देर हो जाती है। इसलिए इसे स्वस्थ शरीर होते हुए भी किया जाए तो बीमारी हमेशा दूर ही रहेगी।

शशि शेखर श्रीवास्तव
डेबढ़ी, मढ़ौरा, सारण (बिहार)

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रोचक प्रस्तुति

योजना का जुलाई अंक 2015 पढ़ा। बेहद रोचक, ज्ञानवर्द्धक था। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए योजना के पूरी टीम सहित सभी लेखकों को कोटिशः धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने देश के हितों को संरक्षित करना, पोषित करना, किसी चुनौती से कम नहीं होता। वह भी तब जब देश की राजनीति जाति, धर्म और क्षेत्र विशेष पर आधारित हो, तो यह काम और भी मुश्किल हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो लेकिन इसका त्वरित लक्ष्य शक्ति अर्जित करना ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी देश को वह आधार प्रदान करते है, जिस पर खड़े होकर कोई देश अपने नैतिक उत्तरदायित्वों का वहन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने देश के लिए स्थान सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री की अमेरिका, फ्रांस, रूस सहित सार्क देशों की यात्रा काफी मायने रखती है। निःसंदेह आज बात, पूंजीवाद, साम्यवाद या गुटनिरपेक्षता की नहीं है। आज के बदलते वैश्विक विषय, आपसी सहयोग, मानवाधिकार, विश्व व्यापार, ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, विज्ञान व प्रौद्योगिकी एवं निवेश है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए।

विभाकर झा, दिल्ली-110092

सफल कूटनीति

जुलाई 2015 अंक में प्रकाशित आलेखों "भारत-अमेरिका संबंधः उभरी साझेदारियां,

'भारत और चीन संबंध- बदलते रिश्ते' ने मुझे विशेष प्रभावित किया।

सरकार के करीब एक वर्ष के बाद उन्नीस विकसित एवं विकासशील देशों की भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा अभी तक काफी सफल रही है और नई उमंग और जोश भारत को देखने को मिल रहा है। सोवियत संघ के विखंडन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री की चीन यात्रा तक विश्व का समीकरण काफी बदल चुका है। जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा शुरू हुई थी तब कुछ बुद्धिजीवियों का तर्क था कि भारत नये ढंग से चीन से दोस्ती करना चाहता है क्योंकि अब तो पूर्व सोवियत संघ रहा ही नहीं जो कभी भारत का घनिष्ठ सहयोगी व मित्र था।

अशोक कुमार ठाकुर
मालीटोल, अदलपुर, दरभंगा (बिहार)

गुणवत्तापूर्ण सामग्री

सर्वप्रथम योजना हिंदी की पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद। जिन चीजों की सामान्यत: सभी लोग प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रशंसा करने के लिए कई बाद शब्द अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। योजना का हमारे लिए क्या अर्थ है– मुद्दों के संबंध में गुणात्मक और प्रासंगिक सूचना का अनूठा सामंजस्य। इसमें बमुश्किल 10-15 आलेख होते हैं लेकिन इसकी सामग्री अन्य पत्रिकाओं की बनिस्पत अधिक श्रेष्ठ है। यह विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर स्नातक तक के लिए लाभप्रद है, चाहे वह तकनीक का विद्यार्थी हो या फिर सामान्य स्नातक हो। पिछले तीन अंकों की सामग्री की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्दों का अभाव है। उम्मीद है योजना सफलता की सभी ऊंचाईयों तक पहुंचेगी और यह हमें अपने वृहत् ज्ञान कोष से आनन्दित करती रहेगी।

विवेक पाण्डेय, बी टेक
बीजीडीआईटी, गाजियाबाद
ईमेल-vivekp834@gmail.com

स्वाधीनता दिवस पर लें संकल्प

15 अगस्त 1947 के पवित्र दिन भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन अभी उसके सामने देश के निर्माण का काम है। यह काम धीरे-धीरे हो रहा है। हालांकि इतने वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी भारत अपने सपने को साकार नहीं कर पाया। इसका कारण वैयक्तिक स्वार्थों की प्रबलता है। दलबंदी के कारण भी काम में विशेष गति नहीं आती। हमारा कर्तव्य है कि देश के उत्थान के लिए इसकी ईमानदारी का परिचय दें। प्रत्येक नागरिक कर्मठता का पाठ सीखे और अपने चरित्र, बल को ऊंचा बनाए।

जनता एवं सरकार दोनों को मिलकर देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना है। युवा देश की रीढ़ की हड्डी के समान है। उन्हें देश का गौरव बनाए रखने के लिए तथा इसे संपन्न एवं शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हम सांप्रदायिकता के विष से सर्वथा दूर रहें। सभी निज संस्कृति के अनुकूल ही रचे राष्ट्र उत्थान।

स्वतंत्रता का मंगल पर्व इस बात का साक्षी है कि स्वतंत्रता एक अमूल्य वस्तु है। अनेक देशभक्तों ने भारत के सिर पर ताज रखने के लिए अपना उत्सर्ग कर दिया है। इस दिन में एकता का पाठ पढ़ना चाहिए और देश की रक्षा का व्रत धारण करना चाहिए।

प्रदीप शर्मा,
कसैया कुशीनगर, उ.प्र.

ज्ञान का सागर

योजना छह महीनों से लगातार पढ़ रहा हूं। पहली बार इसे हमें पढ़ने की सलाह लक्ष्मण भाई ने दी। उनका मैं शुक्रगुजार हूं। यूं कहा जाए तो यह पत्रिका 'ज्ञान का सागर है' जिसमें आप कितना भी सागर से पानी निकाल लें खत्म नहीं होता। इसी तरह ये योजना अपार ज्ञान का भंडार है।

जब से मैंने इसे पढ़ा मैं इसका प्रशंसक हो गया। मैं बेसब्री से इसकी अगली कड़ी का इंतजार करता हूं। धन्यवाद।

दयाल गोपी
हरदौवा, चंद्रपुरा, बोकारो, झारखंड
ईमेल-dayal329251@gmail.com

इलाहाबाद: स्मार्ट सिटी का समाजशास्त्र

नगर की परिभाषा भौतिक आवास जनसंख्या के घनत्व और जीवन की शैली आदि कई आधारों पर की गई। नगर तो वास्तव में एक मानसिक दशा, प्रथाओं एवं परंपराओं, संगठित विचारों तथा भावनाओं का एक समूह है, जो प्रथाओं द्वारा जीवित रहता है तथा जिसका अनुरक्षण परंपराओं द्वारा होता है और जिसका एक विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक चरित्र होता है लेकिन इलाहाबाद पवित्र नगर की श्रेणी में आता है इसलिए संगम नगरी को स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित करने से यथास्थिति को चुनौती देना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है लेकिन केवल स्मार्ट बिल्डिंग, पुल, सीवेज अत्याधुनिक माल में परिवर्तित कर देने से स्मार्ट सिटी हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है।

फिर भी, इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित करने से संगम नगरी एक नये कलेवर के रूप में परिलक्षित होगी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी सिर्फ जल प्रदाता ही नहीं है बल्कि उनके किनारे आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक जीवन पला-बढ़ा है और दुर्भाग्य से गंगा, यमुना अब अपशिष्ट एवं सीवर को ढो रही है। इसलिए गंगा-यमुना को प्रदूषण मुक्त किया जाए। केवल अत्याधुनिक तकनीक प्रयोग करने से ही नहीं, बल्कि वैचारिक परिवर्तन भी जरूरी है। संगम को और स्मार्ट किया जाए और नये-नये वृक्षों को उचित जगहों पर वृक्षारोपण किया जाए। स्नानार्थियों के लिए स्मार्ट रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था की जाए और विदेशी सैलानियों के लिए विशेष ख्याल रखा जाए।

विश्वस्तरीय कुम्भ मेला को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय (पूरब का आक्सफोर्ड) में भीड़ प्रबंधन विभाग की स्थापना की जाए। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में त्वरित निस्तारण हेतु अधुनातन पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। प्रयाग संगीत समिति को डीम्ड वि.वि. का दर्जा प्राप्त हो। संगम नगरी में रेडलाईट एरिया और रैग पिकर्स, कूड़ा-बीनने वालों के लिए स्मार्ट पुनर्वास और उनके बच्चों को शिक्षा, रोजगार, तकनीक प्रशिक्षण और लड़कियों, महिलाओं को स्वरोजगार उन्मुख बनाया जाए जिससे वे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। स्वस्थ और मजबूत समाज के लिए ये तत्व जरूरी हैं।

ए.के. पांडेय
चांदपुर सलोरी, इलाहाबाद
ईमेल: akhileshkumarpandey10@rediffmail.com

विभिन्न राज्यों से जुड़े

हिंदी माध्यम के IAS टॉपर

क्या कहते हैं इस पत्रिका के बारे में...

निशांत जैन (उत्तर प्रदेश)

"दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' स्वयं में एक अनूठी और बहुआयामी पत्रिका है। मैंने खुद इस पत्रिका का लाभ उठाया है।

सिविल सेवा परीक्षा पर ही पूरी तरह केन्द्रित यह पत्रिका कई मायनों में विशिष्ट है। इंटरव्यू खंड, निबंध खंड, एथिक्स आदि पर विशेष ध्यान देना इस पत्रिका को बाकी पत्रिकाओं से अलग बनाता है। समसामयिक घटनाओं का सिविल सेवा परीक्षा के नज़रिए से विश्लेषण और फिर उनकी बिन्दुवार प्रस्तुति बेहद उपयोगी और प्रासंगिक है।

'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' आपकी सफलता में सार्थक भूमिका निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।"

प्रदीप कुमार (हरियाणा)

"दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' एक मानक पत्रिका है। पिछले दो अंकों में तो इसने 'गागर में सागर' भर दिया है। वस्तुतः बाज़ार में उपलब्ध स्तरहीन सामग्री ने अभ्यर्थियों को दिशाभ्रमित ही किया है। ऐसे में 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' ने विद्यार्थियों की राह आसान कर दी है।"

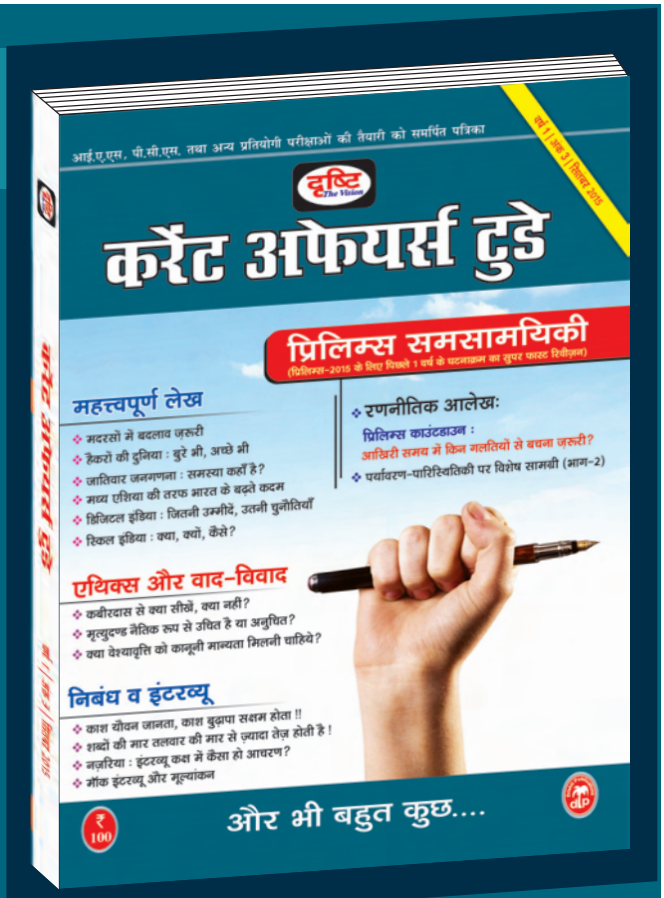

"हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि पत्रिका कौन सी पढ़ी जाए? इसके लिए सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, प्रामाणिक और सारगर्भित स्रोत दृष्टि 'करेंट अफेयर्स टुडे' के माध्यम से मिलता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच से तैयारी के लिए हिंदी माध्यम में ऐसी किसी पत्रिका का अभाव था जो प्रिलिम्स, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। विकास दिव्यकीर्ति सर के मार्गदर्शन में यह पत्रिका निश्चित ही इन सभी मानकों पर खरी उतरती है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी गूगल ट्रांसलेटेड मैटीरियल पढ़ने की बजाय यह पत्रिका पढ़ें जो पूर्णतः मौलिक व अनुभवी टीम की मेहनत का परिणाम है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए यह पत्रिका निश्चित रूप से वरदान साबित होगी। शुभकामनाएँ।"

राजेन्द्र पेंसिया (राजस्थान)

दृष्टि The Vision

आई.ए.एस, पी.सी.एस. तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित पत्रिका

"यह पत्रिका (दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे) हिन्दी माध्यम में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करने की एक गंभीर कोशिश है। इसके सभी खंडों का गंभीर अध्ययन तैयारी को संपूर्णता प्रदान करता है। पत्रिका के 'समसामयिक मुद्दों पर संभावित प्रश्नोत्तर' खंड से मुझे मुख्य परीक्षा की तैयारी में विशेष मदद मिली थी।"

मनीष कुमार (बिहार)

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9 Ph.: 011-47532596, (+91)8130392354,56,57,58,59

E-mail:info@drishtiias.com, drishtiacademy@gmail.com * Website: www.drishtiias.com

YH-130A/2015

संपादकीय

स्मार्ट भारत की ओर

पिछले कुछ वर्षों में यह प्रश्न हर किसी की कल्पना का केंद्र बन गया है कि हम स्मार्ट जीवन कैसे जी सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या और तेजी से होते शहरीकरण ने लोगों को बड़े पैमाने पर गांवों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के लिए विवश कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा, परिवहन, जल, आवास एवं सार्वजनिक स्थानों पर बड़ा दबाव पड़ा है। नीति निर्माता इन समस्याओं को हल करने के लिए रास्ते तथा साधन तलाशने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। *स्मार्ट* शहरों जैसे उपायों की अधिक से अधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है, जो एक ओर तो सक्षम एवं संवहनीय होंगे और दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक कल्याण के कारण भी बनेंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती रही है और वैश्विक स्तर पर प्रशंसा प्राप्त कर रही है। विश्लेषक बताते हैं कि उदारीकरण तथा अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ ही व्यवस्थित नियोजन तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में निहित शक्ति ने ऐसी विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त किया है लेकिन इसी के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ना आसान बात नहीं है। बढ़ती आर्थिक सक्रियता और शहरीकरण का हमेशा चोली दामन का साथ रहा है। शहरों में आर्थिक गतिविधियों की तीव्र गति के कारण बेहतर रोजगार एवं आजीविका की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। हमारे कई शहर किसी मूल योजना के बगैर अनियोजित विकास के प्रतिकूल प्रभावों से जूझ रहे हैं। दुख की बात है कि अधिकतर शहरों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है तथा सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवाओं के लिए गुंजाइश बहुत कम है। शहरी अमीरों और गरीबों के बीच तेजी से बढ़ती खाई भी गंभीर चिंता का विषय है।

यह सच है कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किंतु फिलहाल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का दो तिहाई हिस्सा शहरी क्षेत्र से आता है। यह तथ्य कि शहर भारत के आर्थिक विकास के संचालक हैं, हमारे शहरों में अत्याधुनिक ढांचागत सुविधाओं तथा सेवा आपूर्ति प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। स्मार्ट सिटी मिशन स्वच्छ जल की पर्याप्त आपूर्ति, सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन, प्रभावी शहरी परिवहन एवं सार्वजनिक परिवहन, मजबूत आईटी संपर्क, गरीबों के लिए किफायती आवास जैसी प्रमुख ढांचागत सेवाओं के इंतजाम पर जोर देता है। देश भर में 100 स्मार्ट शहर बनाने का सरकार का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेशी वृद्धि पर आधारित चतुर एवं सतत विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य पर केंद्रित है। यह मिशन 2015-16 से 2019-2020 के बीच पांच वर्ष में 100 शहरों को दायरे में लेगा। समावेशी प्रकृति के ऐसे स्मार्ट शहर सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक आईटी उपकरणों का प्रयोग करते हुए शहरी गरीबों तथा वंचित वर्गों के लिए रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे।

अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए पूरक का कार्य करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन एवं अमृत पर क्रमशः 48,000 करोड़ रुपये और 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।

एक अन्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार झुग्गीवासियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं कम आय वाले वर्गों से आने वाले लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ किफायती मकानों के निर्माण पर अगले सात वर्ष में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। आजीविका की कठोर वास्तविकता से जूझ रहे लाखों झुग्गीवासियों एवं शहरी गरीबों के लिए यह वरदान सरीखा होगा।

सूचना एवं डिजिटल प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए अत्याधुनिक ढांचागत सुविधाएं एवं प्रभावी सेवा प्रणाली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ स्मार्ट सिटीज मिशन सामाजिक एवं आर्थिक विभाजन पाटने में योगदान करेगा। साथ ही अन्य देशों के स्मार्ट शहरों की नकल करने के बजाय भारत को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी रणनीतियां तैयार करनी होंगी। प्रौद्योगिकी विशेषकर आईटी क्षेत्र में महारत तथा दक्ष कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता स्मार्ट सिटीज परियोजना के क्रियान्वयन में भारत के लिए लाभप्रद हैं। जनता के सही रवैये, प्रभावी प्रशासन एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन से ही भारत स्मार्ट जीवन के युग में प्रवेश करने तथा अपने नागरिकों के लिए अधिक स्मार्ट दुनिया बनाने की आशा कर सकता है। ❑

दृष्टि The Vision

Most trusted & renowned institute among IAS aspirants

IAS- 2014 में हिन्दी माध्यम में सर्वोच्च स्थान पर चयनित

निशांत जैन
Rank-13

सिविल सेवा परीक्षा में अपनी सफलता के लिए मैं डॉ॰ विकास दिव्यकीर्ति के प्रति विशेष तौर पर आभारी हूँ। परीक्षा के तीनों चरणों, प्रारम्भिक, मुख्य और साक्षात्कार में दिव्यकीर्ति सर और 'दृष्टि The Vision' ने मेरा बहुत सहयोग किया। विकास सर केवल मेरे शिक्षक ही नहीं, अग्रज और मार्गदर्शक की भूमिका में भी रहे हैं। उनकी संतुलित एप्रोच और सहज शैली परीक्षार्थियों के लिए वरदान ही है। सामान्य अध्ययन, निबन्ध, साक्षात्कार और हिन्दी साहित्य के लिए दृष्टि संस्थान और विकास सर के मार्गदर्शन का कोई सानी नहीं है। कंटेंट और एप्रोच में निरन्तर विकास और इनोवेशन दृष्टि की खासियत है। मैंने किसी अन्य संस्थान से कक्षा नहीं की है।
धन्यवाद विकास सर, शिवेश जी और दृष्टि!
निशान्त जैन
04-07-15

सामान्य अध्ययन
निःशुल्क परिचर्चा
2 Sept.
3 PM

इतिहास
द्वारा- अखिल मूर्ति
निःशुल्क परिचर्चा
6 Sept., 8 AM

भूगोल
द्वारा- कुमार गौरव
निःशुल्क परिचर्चा
8 Sept., 8 AM

Test Series (Mains)- 2015 (Both in English & Hindi Mediums)

Quality Assessment And Enrichment Programme.

- Proper synthesis of both current and traditional areas as per latest trend.
- Module-wise tests to make preparation more effective.
- Test Discussion will be conducted by Dr. Vikas and team Drishti.
- Well structured and precise model answers.
- Answer scripts will be evaluated by subject-experts and selected candidates with detailed MICRO and MACRO analysis.
- Doubt clearing session for each student individually with expert team.
- All India level ranking to assess performance for each test.
- Online and Postal facilities available.

Starts from: 12th September, 2015

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9 Ph.: 011-47532596, (+91)8130392354,56,57,58,59
E-mail:info@drishtiias.com, drishtiacademy@gmail.com * Website: www.drishtiias.com

YH-130/2015

स्मार्ट शहर: अवधारणाएं एवं रणनीतियां

आर. बी. भगत

स्मार्ट शहर डिजिटल विभाजन को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि शहर के भीतर एवं शहर तथा गांवों के बीच विभाजन समाप्त करने के लिए हैं। स्मार्ट शहर के विचार को सूचना एवं डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से शहरी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने एवं पर्याप्त तथा प्रभावी सेवा आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों की सफलता का निर्णय भविष्य में यह देखकर होगा कि इन्होंने लोगों के जीवन को कितना बदला और हमारे समाज में बढ़ रही असमानता को कितना कम किया

मानव सभ्यता को शहरों ने आगे बढ़ाया है, जो सत्ता, संस्कृति, व्यापार के ठिकाने तथा उत्पादन के केंद्र रहे हैं। इतिहासकार सिंधु घाटी की सभ्यता को शहरी सभ्यता मानते हैं। बाद के काल में भारत में कई बड़े शहरी केंद्र हुए, जिनमें प्राचीन काल में पाटलिपुत्र (पटना), वैशाली, कौशांबी तथा उज्जैन एवं मध्यकाल में आगरा तथा शाहजहांनाबाद (दिल्ली) प्रमुख हैं। भारत की शहरी सभ्यता की बात करें तो सूची बहुत लंबी है। (रामचंद्रन 1995, शर्मा 2005, चंपकालक्ष्मी 2006)

स्मार्ट सिटी के विचार को समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि शहर कैसे होते हैं। शहर घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, जिनमें अलग-अलग व्यवसाय तथा कौशल एवं जातीय तथा सामाजिक संरचना वाले लोग एक साथ रहते हैं। वास्तव में विविधता और भिन्नता हमेशा से ही शहरों की पहचान रही हैं, जिनसे नए विचारों को बढ़ावा मिला है किंतु समावेश, निष्पक्षता तथा न्याय संबंधी चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। शहर अलग-थलग भी नहीं होते हैं बल्कि शहरी क्रम में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिनसे शहरी प्रणाली का विकास होता है। शहरी क्रम के निचले स्तर (छोटे शहर एवं नगर) ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक करीब से जुड़े होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन बड़े शहरों से छोटे शहरों तक प्रत्येक स्तर पर होता है। इस दृष्टिकोण से शहर आर्थिक वृद्धि के केंद्र ही नहीं होते हैं बल्कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों समेत सभी प्रकार की आबादी को विकास के फल भी देते हैं। इसके अलावा शहर अपनी सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि सभी शहरों और कस्बों में आवागमन एवं आदान-प्रदान का कारण भी बनते हैं। वे सूचना, पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही तथा मजदूरों के आवागमन के माध्यम से भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चूंकि अतीत में विभिन्न शहर आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत रहे हैं, इसलिए मानव इतिहास के अपने-अपने युग में वे स्मार्ट रहे हैं। किंतु स्मार्ट सिटी की वर्तमान बारीकियों को वैश्वीकरण की शक्तियों और सूचना प्रौद्योगिकी के विराट विस्तार के वर्तमान संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिनसे हमारे शहरों की सूरत तय हो रही है और जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव रहा है।

स्मार्ट सिटी का नमूना 80 के दशक के उत्तरार्द्ध में शहरी संदर्भों को समझने के साधन के रूप में सामने आया और उसके बाद से वे विभिन्न संदर्भों में तेजी से विकसित होते गए (एंथोपुलस तथा वकाली 2012)। टाउनसेंड (2014) के अनुसार 'स्मार्ट सिटी वे स्थान हैं, जहां नई और पुरानी समस्याएं दूर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को जोड़ दिया जाता है। रोड़े, कांच और इस्पात से बने पुराने शहर के नीचे अब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयरों का बड़ा जाल छिपा है। दूसरी ओर नया शहर पहले बने हुए शहरों का बेहतर और डिजिटल रूप है, जो शहरों के एक नए युग को आरंभ कर रहा है' - हम इसे स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण है, जो पूरे स्मार्ट सिटी की ओर नहीं बल्कि उसके एक भाग की ओर देखने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए यह कहता है कि स्मार्ट सिटी का अर्थ जो भी हो, उसमें प्रत्येक स्थान एकसमान स्मार्ट नहीं

लेखक, आव्रजन और शहरी अध्ययन विभाग, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं। युनेस्को-यूनीसेफ भारत आव्रजन कार्यक्रमों में योगदान के साथ नीतिगत मुद्दों पर गठित कई सरकारी समितियों में रहे हैं। इसके अलावा शहरीकरण, आव्रजन, स्वास्थ्य, पर्यावरण और विकास के क्षेत्र में कई शोधपत्र और पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ईमेल: rbbhagat@iips.net

होगा अर्थात् कुछ स्थान, लोग और गतिविधियां दूसरों से बेहतर होंगी (शेल्टन, जूक और वाइग 2015)। वैश्विक आईटी कंपनी आईबीएम को लगता है कि '21वीं शताब्दी में नागरिकों तथा व्यापारों को आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के शहर एक दूसरे से होड़ करेंगे। शहर का आकर्षण इस पर निर्भर करेगा कि वह विकास के अवसरों को बढ़ावा देने, आर्थिक मूल्य प्रदान करने तथा प्रतिस्पर्द्धा में अलग स्थान दिलाने वाली बुनियादी सेवाएं देने में कितना सक्षम है। व्यावसायिक एवं आवासीय उद्देश्य से आने वाले लोग विवेकशील होते हैं और वे ऐसे शहरों की तलाश करते हैं, जो अधिक प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। वे अधिक स्मार्ट सिटी तलाश रहे हैं।' (आईबीएम 2012)।

स्मार्ट सिटी की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है किंतु मूल प्रश्न यह है कि हम कैसी स्मार्ट सिटी चाहते हैं (ऐंजलिडू 2014, टाउनसेंड 2014)। हम कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी वे होती हैं, जहां स्मार्ट अर्थात् चतुर लोग रहते हैं।

स्मार्ट सिटी की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है किंतु मूल प्रश्न यह है कि हम कैसी स्मार्ट सिटी चाहते हैं (ऐंजलिडू 2014, टाउनसेंड 2014)। हम कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी वे होती हैं, जहां स्मार्ट अर्थात् चतुर लोग रहते हैं। चतुर लोगों को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। एक, जो बुद्धिमान एवं समृद्ध किंतु व्यक्तिवादी, उपभोक्तावादी तथा अलग-थलग रहने वाले होते हैं और दूसरे वे होते हैं, जो निचले तबके से मिलने, उसकी सहायता करने और उसका जीवन बदलने में सक्रिय होते हैं। इसी तरह स्मार्ट सिटी कोई अलग-थलग अथवा चारदीवारी में बंद शहर नहीं है बल्कि ऐसा शहर है, जो अपने निवासियों से जुड़कर उनका जीवन बदल देता है। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि शहर लोगों का कायाकल्प करते हैं और लोग शहरों का निर्माण करते हैं। हमें यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि अपने शहरों का निर्माण करने के लिए हम प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार करते हैं और गरीबों तथा हाशिये पर रहने वाले लोगों के लिए इसके क्या परिणाम होते हैं (अल्बिनो एवं अन्य, 2015)। इसके अलावा भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है, इसलिए लोगों का भाग्य इस पर बहुत निर्भर करेगा कि हम अपने शहरों का निर्माण किस प्रकार करते हैं। साथ ही सरकार का हस्तक्षेप हमारे शहरों की परिकल्पना तथा निर्माण में सहायक हो सकता है। पिछले एक दशक में सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों को इसी के आलोक में देखा जाना चाहिए।

स्मार्ट सिटीज मिशन

2005 में जेएनएनयूआरएम (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन) आरंभ हुआ, जिसे एक दशक बाद 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन एवं अमृत (अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) जैसे कार्यक्रमों में बदल दिया गया। जेएनएनयूआरएम पहले की शहरी नीतियों एवं कार्यक्रमों से काफी अलग था क्योंकि इसमें भारत के आर्थिक विकास में शहरों की महत्ता इस दृष्टि से मानी गई थी कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग दो-तिहाई शहरी क्षेत्रों से ही आता है (भगत 2011)। स्मार्ट सिटीज मिशन एवं अमृत जैसी नई शहरी विकास रणनीतियां जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आरंभ की गईं शहरी विकास नीतियों का ही नया एवं गहन प्रारूप हैं। कई लोगों ने शहरों के भीतर तथा क्षेत्रों के बीच तीव्र सामाजिक-आर्थिक असमानता के कारण जेएनएनयूआरएम को विभेदकारी बताकर इसकी आलोचना की थी। विकास तथा स्थायित्व के साथ समावेशन शहरी विकास के किसी भी कार्यक्रम के लिए चुनौती रहा है।

स्मार्ट सिटीज मिशन 2015-16 से 2019-20 के बीच 100 से अधिक शहरों को अपने दायरे में लेगा। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए स्मार्ट सिटीज की अवधारणा तथा रणनीतियां विकसित होती रहेंगी। मिशन में स्मार्ट सिटी की परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन इसका लक्ष्य उस शहर की क्षमता बढ़ाना है, जो स्मार्ट सुविधाओं के माध्यम से स्मार्ट बनना चाहता है। स्मार्ट सुविधाओं की लंबी सूची में से कुछ हैं ई-प्रशासन तथा इलेक्ट्रॉनिक सेवा आपूर्ति, वीडियो के माध्यम से अपराध की निगरानी, जलापूर्ति प्रबंधन के लिए स्मार्ट मीटर, स्मार्ट पार्किंग तथा यातायात का चतुराई भरा प्रबंधन। स्मार्ट सुविधाएं देने से शहर बुनियादी ढांचा तथा सेवाएं सुधारने के लिए सूचना, प्रौद्योगिकी एवं जानकारी का प्रयोग कर सकेंगे। इससे रेट्रोफिटिंग (शहर में सुधार) एवं पुनर्विकास के माध्यम से क्षेत्र विशेष के विकास का प्रयास भी होगा। इसके अतिरिक्त बढ़ती शहरी आबादी को समेटने के लिए शहरों के आसपास नए क्षेत्र (शहरों का विस्तार) भी विकसित किए जाएंगे। यह माना जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के विकास की रणनीतियों से पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन होगा और गरीबों का ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि स्मार्ट शहर समावेशी होंगे।

स्मार्ट सिटीज मिशन का क्रियान्वयन विशेष उद्देश्य उपक्रम (एसपीवी) की सहायता से होगा, जिसका नेतृत्व पूर्णकालिक मुख्य कार्य अधिकारी (सीईओ) करेंगे। इसमें केंद्र, राज्य सरकारों एवं स्थानीय प्रशासनों द्वारा मनोनीत व्यक्ति शामिल होंगे। यह एसपीवी कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शहर के स्तर पर लिमिटेड कंपनी होगी। सभी 100 स्मार्ट शहरों के लिए सलाह देने एवं विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल बिठाने के लिए शहर के स्तर पर स्मार्ट सिटी परामर्शी मंच का गठन किया जाएगा और इसमें जिलाधिकारी, सांसद, विधायक, महापौर, एसपीवी के सीईओ, स्थानीय युवा एवं नागरिक तथा तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। स्मार्ट सिटीज मिशन में प्रशासन तथा सुधारों में बुद्धिमान लोगों के सक्रिय सहभाग की आवश्यकता होगी। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विशेषकर मोबाइल आधारित सुविधाओं का अधिक प्रयोग कर एसपीवी बुद्धिमान लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करेगी। केंद्र सरकार आरंभ में 194 करोड़ रुपये का अनुदान देगी और इतना ही अनुदान राज्य सरकार से भी प्राप्त होगा। स्मार्ट शहर के लिए आगे का अनुदान उसके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। कुल 100 स्मार्ट शहरों का चयन स्मार्ट सिटी प्रस्ताव आमंत्रित कर प्रतियोगिता के आधार पर होगा। स्मार्ट शहर के विकास के विभिन्न चरणों में बड़ी संख्या में सलाहकार फर्मों तथा अन्य एजेंसियों का सहयोग लिया जाएगा। आगे चलकर ये शहर अपनी मुख्य आर्थिक गतिविधियों जैसे स्थानीय व्यंजन,

स्मार्ट सिटीज मिशन में प्रशासन तथा सुधारों में बुद्धिमान लोगों के सक्रिय सहभाग की आवश्यकता होगी। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विशेषकर मोबाइल आधारित सुविधाओं का अधिक प्रयोग कर एसपीवी बुद्धिमान लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करेगी।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कला एवं शिल्प, संस्कृति, खेल के सामान, फर्नीचर, होजरी, टेक्सटाइल आदि के आधार पर ब्रांड और पहचान हासिल कर लेंगे। इस प्रकार स्मार्ट शहर उत्पादन एवं प्रभावी प्रशासन के केंद्र ही नहीं होंगे बल्कि खपत के भी केंद्र होंगे। उस स्थिति में ये आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधार सकते हैं।

अमृत को स्मार्ट सिटी मिशन के पूरक के रूप में आरंभ किया गया है, जिसके दायरे में 1 लाख अथवा अधिक जनसंख्या वाले 500 शहर आएंगे। अमृत का कार्यक्षेत्र जलापूर्ति, कचरे का प्रबधंन, जल की समुचित निकासी, शहरी परिवहन एवं हरियाली भरे स्थानों एवं पार्कों का विकास करना है, जिसके लिए क्षमता निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य शहरी स्थानीय निकाय करेंगे। ऐसा माना गया है कि अमृत के

अमृत को स्मार्ट सिटी मिशन के पूरक के रूप में आरंभ किया गया है, जिसके दायरे में 1 लाख अथवा अधिक जनसंख्या वाले 500 शहर आएंगे। अमृत का कार्यक्षेत्र जलापूर्ति, कचरे का प्रबधंन, जल की समुचित निकासी, शहरी परिवहन एवं हरियाली भरे स्थानों एवं पार्कों का विकास करना है।

अंतर्गत वित्तीय सहयोग के लिए संभावित स्मार्ट शहरों को वरीयता दी जाएगी। केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य कार्यक्रमों से तालमेल बिठाते हुए राज्य की वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाएगी। योजना में राज्य का योगदान परियोजना की कुल लागत के 20 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। वार्षिक कार्य योजना बनाने के बाद राज्य स्तर की क्रियान्वयन योजनाएं बनाई जाएंगी। अमृत के अंतर्गत जलापूर्ति बढ़ाने के लिए एक अनूठा सुझाव यह है कि लंबी दूरी से जल लाने के बजाय जल की रिसाइक्लिंग की जाए और दोबारा उसका प्रयोग किया जाए। ये दो कार्यक्रम शहरी कायाकल्प में भी एक दूसरे के पूरक होंगे। अमृत परियोजना आधारित प्रणाली पर चलता है, लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन क्षेत्र आधारित रणनीति पर काम करेगा। दोनों कार्यक्रम राज्य, शहरी स्थानीय निकायों एवं निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने का यत्न करते हैं और केंद्र सरकार निर्णायक भूमिका निभाएगी (www. smartcities.gov.in; www.amrut.gov.in)।

चुनौतियां एवं परिणाम

भारत की वर्तमान शहरी व्यवस्था की विशेषता यह है कि इसमें 7935 शहर हैं तथा तीन महानगर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई हैं, जिनका ब्रिटिश शासन के दौरान विकास हुआ। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। उनके बाद दूसरे स्थान पर बेंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे जैसे बड़े शहर हैं। इन आठ शहरों की परस्पर निर्भरता तथा पारस्परिक संबंध एवं उनके क्षेत्रीय वर्चस्व एवं शहरी गलियारों में भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदल देने की क्षमता है। किंतु ये शहर स्वयं ही यह करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए शहरी विकास की रणनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। क्षेत्रीय असमानता, शहरी-ग्रामीण विभाजन एवं शहर के भीतर विषमता भारत के शहरी कायाकल्प एवं आर्थिक प्रगति में बड़े बाधक हैं। वर्तमान केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन एवं अमृत की परिकल्पनाओं तथा रणनीतियों को इसी आलोक में देखा जाना चाहिए। मध्य, पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत के कम शहरीकरण वाले क्षेत्रों में कई स्मार्ट शहरों का प्रस्ताव दिया जा रहा है। अमृत भी 4041 विधिक शहरों में से 500 को पहले चरण में अपने दायरे में लेना चाहता है। किंतु बड़ी संख्या में (3894) जनगणना शहर हैं, जो दोनों में से किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते। जनगणना शहरों की कमान प्राय: ग्राम पंचायत के हाथ में होती है, जिनके पास संसाधनों एवं संस्थागत क्षमता की तो कमी होती है किंतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच सेतु का कार्य करने की संभावना होती है। जनगणना शहरों को भी शहरी विकास रणनीति में शामिल करने से ग्रामीण विकास के लिए शहरीकरण की संभावना भी सामने आएगी।

स्मार्ट सिटीज मिशन की क्षमता और अमृत एवं हाउसिंग फॉर ऑल के साथ उसके तालमेल से कई लाभ हो सकते हैं किंतु गरीबों एवं झुग्गी बस्तियों के हितों की रक्षा की आवश्यकता है, जिनकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 6.5 करोड़ है। ये कार्यक्रम न तो प्रशासन के स्तर पर और न ही क्रियान्वयन के स्तर पर अलग-अलग होने चाहिए अन्यथा इनमें समावेशन समाप्त हो जाएगा। जैसी कि परिकल्पना की गई है, स्मार्ट शहर डिजिटल विभाजन को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि शहर के भीतर एवं शहर तथा गांवों

स्मार्ट सिटीज मिशन की क्षमता और अमृत एवं हाउसिंग फॉर ऑल के साथ उसके तालमेल से कई लाभ हो सकते हैं किंतु गरीबों एवं झुग्गी बस्तियों के हितों की रक्षा की आवश्यकता है, जिनकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 6.5 करोड़ है।

के बीच विभाजन समाप्त करने के लिए हैं। स्मार्ट शहर के विचार को सूचना एवं डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से शहरी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने एवं पर्याप्त तथा प्रभावी सेवा आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों की सफलता का निर्णय भविष्य में यह देखकर होगा कि इन्होंने लोगों के जीवन को कितना बदला और हमारे समाज में बढ़ रही असमानता को कितना कम किया।

संदर्भ:

अल्बिनो, वी., यू. बेरार्डी तथा आर. एम. डैंजेलिको (2015): ''स्मार्ट सिटीज: डेफिनिशंस, डाइमेंशंस, परफॉर्मेंस एंड इनीशिएटिव्स'', *जर्नल ऑफ अर्बन टेक्नोलॉजी*, 22(1): 3-21 http://dx.doi.org/10.1080/10630732.2014.942092.

ऐंजलिडू, एम. (2014): ''स्मार्ट सिटी पॉलिसीज: ए स्पेशियल अप्रोच'', *सिटीज*, 41, एस3-एस11, doi: 10.1016/j.cities.2014.06.007.

एंथोपुलस, एल. जी. तथा ए. वकाली (2012): ''अर्बन प्लानिंग एंड रेसिप्रोसिटीज'' http://www.researchgate.net/publication/230851445_Urban_Planning_and_Smart_Cities_Interrelations_and_Reciprocities.

भगत, आर. बी. (2011): ''इमर्जिंग पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया'', इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 46(34): 10-12?

चंपकालक्ष्मी, आर. (2006): *ट्रेड, आइडियोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली

आईबीएम 2012: ''हाउ टु ट्रांसफॉर्म ए सिटी: लेसंस फ्रॉम आईबीएम स्मार्टर सिटीज चैलेंज'', आईबीएम स्मार्टर सिटीज व्हाइट पेपर, http://asmarterplanet.com/files/2012/11/Smarter-CitiesWhitePaper_031412b.pdf.

रामचंद्रन, आर (1995): *अर्बनाइजेशन एंड अर्बन सिस्टम इन इंडिया*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली: 22-74

शर्मा, आर. एस. (2005): *इंडियाज एंशियंट पास्ट*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली

भोल्टन, टी. एम. जुक एवं ए. वाइग (2015): ''द 'एक्चुअली इक्जिस्टिंग स्मार्ट सिटीज', *कैंब्रिज जर्नल ऑफ रीजंस, इकनॉमी एंड सोसाइटी*, 8: 13-25

टाउनसेंड, एंथनी (2014): *स्मार्ट सिटीज*, डब्ल्यू. डब्ल्यू. नॉर्टन एंड कंपनी इंक, न्यूयॉर्क

ICS सामान्य अध्ययन

empowering nation

Institute for Civil Services

भारत के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक

एक साथ एक मंच पर

श्री अशोक सिंह राजव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा एथिक्स	**श्री के. सिद्धार्थ** भूगोल, आपदा प्रबंधन तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	**डॉ. अभिषेक** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान व पर्यावरण विज्ञान
डॉ.एस.एस.पाण्डेय आंतरिक सुरक्षा, भारतीय समाज एवं एथिक्स	**श्री रजनीश राज** भारत एवं विश्व इतिहास, कला एवं संस्कृति	**श्री अतुल लोहिया** राजव्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली एवं एथिक्स
श्री रामेश्वर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास	**श्री कुमार गौरव** भूगोल तथा सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	**श्री धर्मेन्द्र** भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय

....With Mr. Prashant Sharma (Programme Director)

नया बैच प्रारंभ

निःशुल्क कार्यशाला

3 SEPTEMBER

3:00 PM

Venue: Vardhman Plaza (Basement), Nehru Vihar

H. Office; 870, 1st Floor, (Infront of Batra Cinema) Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Ph.: 011-45094922, 8750908866-55-77-22-00

Visit us: www.icsias.com | E-mail : icsias2014@gmail.com

YH-141/2015

विकास के संवाहक हैं शहर

ईशर अहलूवालिया

हम स्मार्ट सिटीज को परिभाषित करें तो एक ऐसा शहर जहां के बाशिंदों को बेहतर शासन प्रणाली चाहिए और बेहतर प्रशासन या उच्च तकनीक के जरिए सरकार पारदर्शी और जवाबदेह बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं मुहैया कराएगी। तब स्मार्ट सिटीज का काम उच्च तकनीक वाले बुनियादी योजना के जरिए संस्थागत सुधार को बढ़ावा देना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे संघीय शासन में शहरों पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव के बावजूद हालात आज से बेहतर रहेंगे लेकिन हमारे शहरों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए हमें उस राजनीतिक माहौल में सुधार करने की जरूरत है जिसमें हमारे शहर काम करते हैं

भारतीय शहरों में जन सुविधाओं की बहुत कमी है। इसका असर न सिर्फ कुल जनसंख्या के 33 फीसदी या देश की शहरी आबादी के जीवन स्तर पर पड़ता है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज, स्थायी और समग्र विकास के लिए जरूरी निवेश का माहौल भी प्रभावित होता है। पिछले कुछ समय से भारतीय शहरों के अमीर और मध्यम वर्ग सार्वजनिक सेवाओं में कमी की समस्या से निपटने के लिए निजी बाज़ार आधारित उपायों की मदद ले रहे हैं वहीं, अपने गुजर-बसर के लिए गरीबों को भी मजबूरन बाज़ार पर निर्भर रहना पड़ रहा है। फिलहाल भारतीय शहरों और कस्बों में 42 करोड़ लोग रहते हैं और इनमें से सिर्फ आधे लोगों को ही पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं ठीक से मिल पा रही हैं। अनुमान है कि 2031 तक शहरों की जनसंख्या बढ़कर 60 करोड़ हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी को जन सुविधाएं मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है और इसकी अनदेखी करके हम खुद को जोखिम में डाल रहे हैं। इसके अलावा अगर शहरों को तेज आर्थिक विकास के लिए निवेश जुटाना है तो शहरों में जीवन की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर सुधार करना होगा।

भारत में विकास के मौजूदा चरण में शहरों को विकास का इंजन बनाने की जरूरत है। शहरों के आसपास औद्योगिक विकास की जरूरत है ताकि सेवाओं को समर्थन मिल सके और यह सिर्फ शहरों में ही मुमकिन है। ग्रामीण इलाकों की किस्मत भी शहरीकरण की गुणवत्ता से जुड़ी हुई है क्योंकि खेती में प्रति व्यक्ति आय तभी बढ़ सकती है जब लोग कृषि से निकलकर उद्योग और सेवा क्षेत्रों में 'ज्यादा उत्पादकता' वाला काम करेंगे। यह बदलाव नवीनीकरण और उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराने की शहरों की क्षमता पर निर्भर करता है, जिससे रोजगार के मौके बनते हैं। यह खासतौर पर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की कुल आबादी में काम करने लायक लोगों का हिस्सा बढ़ रहा है और 2040 तक यह और भी ज्यादा हो जाएगा। यहां तक कि उसके बाद भी इसमें बहुत मामूली गिरावट आने की उम्मीद है।

मई 2014 के आम चुनावों के बाद एक नई सरकार आई। नई सरकार की घोषित प्राथमिकता विकास को फिर से पटरी पर लाना है। दशक 2001-2011 के दौरान औसत सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर सालाना 7.7 फीसदी थी जो 2011-14 के बीच घटकर 6 फीसदी पर आ गई। अनुमान है कि 2014-15 में यह बढ़कर सालाना 7.2 फीसदी हो सकती है और आगे आने वाले वर्षों में इसमें और तेजी आ सकती है। उद्योग और सेवा क्षेत्रों में तेजी आने से ही सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की वृद्धि दर सालाना 8 से 10 फीसदी होगी। तकनीक, कृषि और जल प्रबंधन में बड़े पैमाने पर निवेश के बावजूद कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर सालाना 4-4.5 फीसदी तक सीमित रहेगी।

अर्थव्यवस्थाएं एक ढांचागत बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। लिहाजा उत्पादन और रोजगार में उद्योग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। दरअसल भारत की जीडीपी में शहरी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है और 2031 तक यह मौजूदा 66 फीसदी से बढ़कर 75 फीसदी तक पहुंच सकती है। ऐसे में चुनौती

लेखिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की भारतीय परिषद (आईसीआरआईईआर) की अध्यक्ष हैं। वहां वह भारत के शहरीकरण की चुनौतियों से संबंधित शोध तथा क्षमता विकास कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही हैं। वह 2008-11 तक शहरी अवसंरचना एवं सेवाओं से संबंधित उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष भी रहीं। ईमेल: isherahluwalia@gmail.com

एक ऐसा शहरी माहौल मुहैया कराने की है जो नवीनीकरण को बढ़ावा और रोजगार के मौकों को विस्तार दे। इस आलेख के पहले भाग में विकास के मौजूदा चरण में प्रगति के इंजन के तौर पर शहरों की बड़ी अहमियत के बारे में बताया गया है और भारतीय शहरों में जन सुविधाओं की बदतर स्थिति पर रोशनी डाली गई है। दूसरे भाग में शहरों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के अनुमान और इसे दुरुस्त करने के लिए रकम जुटाने के तरीके पर बात की गई है। इसमें दलील दी गई है कि निजी क्षेत्र से रकम जुटाने और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से सेवा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए संस्थागत सुधार अहम हैं। इसके तीसरे हिस्से में स्वच्छ भारत, एएमआरयूटी, सभी के लिए आवास और स्मार्ट सिटीज जैसे नए राष्ट्रीय अभियानों का जायजा लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) से सबक लेते हुए सरकार ने नए सरकारी अभियान शुरू किए हैं।

भारत के मौजूदा विकास और ढांचागत बदलाव के इस दौर में विकास के लिहाज से शहरों की अहम भूमिका है। औद्योगिक विकास सिर्फ दुनिया भर में कारोबार फैलाने से नहीं हो सकता। शहरों के आस पास उद्योग शुरू करने के लिए उद्योग में निवेश और शहरों में सेवा क्षेत्र का विकास जरूरी है।

विकास के इंजन हैं शहर

भारत के मौजूदा विकास और ढांचागत बदलाव के इस दौर में विकास के लिहाज से शहरों की अहम भूमिका है। औद्योगिक विकास सिर्फ दुनिया भर में कारोबार फैलाने से नहीं हो सकता। शहरों के आस पास उद्योग शुरू करने के लिए उद्योग में निवेश और शहरों में सेवा क्षेत्र का विकास जरूरी है। इस तरह की अर्थव्यवस्था में बाज़ार की ताकतें और सरकार, दोनों की अहम भूमिका होती है। अगर यह नाकाम होता है तो निवेशकों के हाथ शहरों के आस पास औद्योगिक विकास के बजाय संसाधनों का दुरुपयोग और पर्यावरण का नुकसान आएगा। इसके साथ ही शहरी जीवन स्तर में गिरावट के लिए वे खुद जिमेदार होंगे। भारतीय शहर जो पिछले 25 साल से विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं उनमें बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई आदि हैं। ये सभी शहर अनियोजित शहरी विकास का खामियाजा भुगत रहे हैं। शहरों में सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, पानी, सफाई और सस्ते घरों के साथ दूसरी सेवाएं बहुत कम हैं, जिससे निजी सुविधाएं घटी हैं और इन शहरों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा झुग्गियों में रहने को मजबूर है।

भारतीय शहरों में सेवाओं की मौजूदा स्थिति ही शहरों के विकास की अगुवाई करने की राह में अड़चन है। स्वच्छ जल की कमी, दूषित जल के प्रशोधन या ट्रीटमेंट की अनदेखी के कारण प्रदूषित जल, बारिश के पानी का सही प्रबंधन न होने के कारण जल जमाव और बाढ़, ट्रैफिक जाम से वायु प्रदूषण और ईंधन की गैर वाजिब कीमतें भारतीय शहरों के लिए आम चुनौतियां हैं। उदाहरण के तौर पर शहरों में सिर्फ 60 फीसदी लोगों के घरों में ही पीने का साफ पानी आता है। गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों की सुविधा सिर्फ 33 फीसदी लोगों को ही मिल पाती है। शहरी इलाकों से जितना गंदा पानी निकलता है उनमें 20 फीसदी से भी कम प्रशोधित किया जाता है। नगरपालिका के ठोस कूड़े की बात करें तो, 2013-14 में हर दिन 1,42,566 मीट्रिक टन कूड़ा जमा हो रहा था। इसमें से 82 फीसदी को ही उठाया गया और सिर्फ 29 फीसदी को जैविक खाद के तौर पर परिष्कृत किया गया। इन सबका लोगों की सेहत और शहरों की निवेश जुटाने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है।

भारत को अपने मौजूदा शहरों में नया जोश भरने के साथ नए शहर भी बनाने की जरूरत है। परिवहन और विकास को बढ़ावा देने वाली दूसरी सभी योजनाओं के साथ नए शहरों को योजनागत ढंग से बनाने की जरूरत है लेकिन असली चुनौती मौजूदा 8000 शहरों की समस्याओं को दूर करना है। कुल 80 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े 6 शहरों की बात करें तो जैसे-जैसे शहरों का विस्तार होता गया आस पास के गांव कस्बों में बदल गए। शहर के मुख्य इलाकों के साथ आस पास के इलाके भी बढ़ रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है ताकि इन सभी मेट्रो शहरों में जन सुविधाओं का दायरा बढ़े। जमीन के इस्तेमाल की एक एकीकृत योजना बनाने और बेहतर सार्वजनिक परिवहन की जरूरत है ताकि एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने में आसानी हो लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती बड़े शहरों के संचालन के लिए प्रभावी संस्थागत ढांचा तैयार करना है।

अहमदाबाद, सूरत, पुणे और नागपुर जैसे शहरों पर गौर करें तो यहां भी बड़े शहरों की तरह सीमाओं का विस्तार हो रहा है। इन शहरों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है ताकि इन शहरों की चुनौतियों का आकार और अनुपात बड़े शहरों की चुनौतियों के बराबर न हो जाए। इन शहरों में चुनौती जमीन के इस्तेमाल की एकीकृत योजना बनाने, परिवहन पर फोकस करने, सेवाओं में सुधार और सस्ते घर मुहैया कराने की है। महाराष्ट्र और गुजरात सबसे तेजी से बढ़ने वाले और ज्यादा शहरीकरण वाले राज्य हैं। यहां की सरकारों को राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना होगा और योजना बनाने वाली संस्थाओं को मजबूत बनाने पर काम करना होगा। इसके साथ ही जरूरी सेवाएं मुहैया करानी होगी ताकि तेजी से बढ़ते हुए इन शहरों को आस-पास के औद्योगिक विकास का फायदा मिल सके। कुछ इसी तरह की जरूरत दूसरे राज्यों मसलन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कई दूसरे राज्यों के तेजी से बढ़ने वाले शहरों की भी है। कमजोर आर्थिक आधार, गरीबी और जरूरतमंदों तक सुविधाओं के न पहुंचने के कारण सार्वजनिक नीतियों को खासतौर पर देश भर के राज्यों के छोटे शहरी केंद्रों पर भी ध्यान देना होगा।

भारत को अपने मौजूदा शहरों में नया जोश भरने के साथ नए शहर भी बनाने की जरूरत है। परिवहन और विकास को बढ़ावा देने वाली दूसरी सभी योजनाओं के साथ नए शहरों को योजनागत ढंग से बनाने की जरूरत है लेकिन असली चुनौती मौजूदा 8000 शहरों की समस्याओं को दूर करना है।

भारत में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विकास का फोकस मुख्य तौर पर ग्रामीण विकास पर है। यहां तक कि भारत की जनगणना में बताया गया है कि 2001 से 2011 के बीच कस्बों की संख्या में 2500 से ज्यादा इजाफा हुआ जबकि संवैधानिक स्थानीय सरकारों (संबंधित राज्य सरकार

द्वारा अधिसूचित) के मुताबिक इस दौरान सिर्फ 242 कस्बे बढ़े। गांवों की स्थानीय सरकारें 'शहरीकरण' से इसलिए दूर भागती हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि शहरीकरण के दायरे में आते ही ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत जो फंड उन्हें मिलता है वह बंद हो जाएगा। इसके साथ ही उन पर शहरीकरण से जुड़े नियम लागू होने लगेंगे।

यहां तक कि जहां शहरी स्थानीय निकाय मौजूद हैं उन्हें कार्यों के हस्तांतरण, फंड्स और अधिकारियों की नियुक्ति के जरिए सक्षम बनाने की जरूरत है। वर्ष 1992 में 74वें संविधान संशोधन में औपचारिक रूप से शहरी स्थानीय निकायों को सरकार के तीसरे स्तर की मान्यता दी गई। इन निकायों को पानी, ठोस कूड़ा के प्रबंधन, दूषित जल के परिष्करण, बरसात के पानी की निकासी जैसे कामकाज देखने का जिम्मा दिया गया है। हालांकि राज्य सरकारों ने कुछ हद तक

गांवों की स्थानीय सरकारें 'शहरीकरण' से इसलिए दूर भागती हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि शहरीकरण के दायरे में आते ही ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत जो फंड उन्हें मिलता है वह बंद हो जाएगा। इसके साथ ही उन पर शहरीकरण से जुड़े नियम लागू होने लगेंगे।

काम काज की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों को दी है लेकिन वित्तीय तौर पर उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। स्थानीय सरकारों को फंड जुटाने की भी स्वायत्ता खासतौर पर प्रॉपर्टी टैक्स और यूजेज चार्ज लेने का अधिकार देना चाहिए। अधिकारियों के तबादले की बात करें तो शहरों के नगर निगम कर्मचारियों के मामले में बहुत कम काम हुआ है। नगर निगम कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और इनकी नियुक्ति स्थानीय निकाय ही कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकारों के कर्मचारी शहरों में पोस्टिंग का विरोध करते हैं। बहुत कम राज्यों में नगर निगम का कैडर है। स्थानीय निकायों को अधिकार न मिलने के कारण भारत के शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों के रामबाण इलाज के तौर पर सीधे निर्वाचित मेयर या ऐसे दूसरे वैश्विक तरीकों के बारे में बात करना ठीक नहीं है।

शहरी अवसंरचना: निवेश और फंड

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की चेयरपर्सन के तौर पर लेखिका ने यह अनुमान लगाया था कि 2009-10 की कीमतों के हिसाब से शहरों की बुनियादी सुविधाओं के लिए 39.2 लाख करोड़ रुपये की कमी है। यह 2014-15 के 54.3 लाख करोड़ के बराबर है जबकि इसमें जमीन की लागत शामिल नहीं की गई है। इस अनुमान में 2012 से 2031 तक उन सभी शहरी आबादी को सुविधाएं देना शामिल है जिन्हें पहले से सेवाएं नहीं मिल रही थीं। इसके अलावा इसमें इस दौरान बढ़ने वाली नई आबादी भी शामिल है। इस अनुमान के साथ सालाना जीडीपी 8 फीसदी माना गया है। साथ ही यह भी माना गया था कि लोगों को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में तय मानक के मुताबिक ही सेवाएं मुहैया की जाएंगी। कुल फंड का करीब 56 फीसदी हिस्सा शहरों की सड़कों पर और 17.7 फीसदी परिवहन और यातायात को बेहतर बनाने वाली बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। पानी और साफ सफाई के लिए कुल रकम का 25 फीसदी निवेश करने की जरूरत है। राज्य सरकारें 74वें संशोधन को अपनाने में कोताही कर रही हैं क्योंकि वे शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय अधिकार नहीं देना चाहती हैं।

इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में स्थानीय निकायों को वित्तीय अधिकार हैं। शहरी स्थानीय सरकारों के लिए अनुदान सहायता और फॉर्मूला आधारित स्थानांतरण बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर तो यही होगा कि जीएसटी के तहत राज्य सरकारों को जो आमदनी होगी उसका पहले से तय एक हिस्सा शहरी स्थानीय सरकारों को जाए। इसके साथ ही शहरी स्थानीय निकायों को टैक्स लगाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार शहरी स्थानीय निकायों की आमदनी का एक अहम जरिया हो सकता है। साथ ही यूजर चार्ज लगाने और वसूलने का अधिकार देने से शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। एक नगर निगम नियामक बनाने से शहरी सेवाओं के मूल्य निर्धारण में व्यावसायिकता आएगी।

भूमि की कीमत एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अभी तक अनदेखी की गई और जिससे शहरी स्थानीय निकायों को अच्छी आमदनी हो सकती है। इनमें कंवर्जन शुल्क, विकास शुल्क, सुधार की फीस जैसे भूमि आधारित वित्तीय स्रोत शामिल हैं। इसके साथ ही समग्र योजना के दिशा निर्देशों के तहत फ्लोर स्पेस इंडेक्स के मूल्य निर्धारण से भी सरकारों को आमदनी होगी। शहरों में बुनियादी सुविधाओं की फंडिंग के लिए शहरी स्थानीय सरकारों की बाह्य स्रोतों से फंड जुटाने की क्षमता उनके रेवेन्यू मॉडल तैयार करने की काबिलियत पर निर्भर करती है। इसमें वे पूंजी बाज़ार से जुटाए लोन का भुगतान कर सकते हैं। पीपीपी परियोजनाओं में निजी साझेदार के निवेश पर रिटर्न बना सकते हैं। यह मुमकिन है। उदाहरण के तौर पर सेवाओं के बदले पर्याप्त यूजर चार्ज या बेटरमेंट फीस के जरिए जमीन की कीमत में बढ़ोतरी याध और पीपीपी परियोजनाओं के तहत निजी साझेदारों को रियायती दरों पर व्यवसायिक भूमि विकसित करने की अनुमति

इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में स्थानीय निकायों को वित्तीय अधिकार हैं। शहरी स्थानीय सरकारों के लिए अनुदान सहायता और फॉर्मूला आधारित स्थानांतरण बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर तो यही होगा कि जीएसटी के तहत राज्य सरकारों को जो आमदनी होगी उसका पहले से तय एक हिस्सा शहरी स्थानीय सरकारों को जाए।

देना। सुधारों के जरिए वित्तीय स्थिति मजबूत करने और सेवाओं में सुधार से शहरी स्थानीय निकायों की कर्ज जुटाने की क्षमता में सुधार होगा। संस्थानों को मजबूत बनाकर बेहतर संचालन से सेवाओं में सुधार होने के साथ निजी क्षेत्र से रकम जुटाने में भी आसानी होगी।

शहरी विकास के लिए राष्ट्रीय अभियान

2005 में आखिरकार भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शहरी क्षेत्र की अहमियत समझने का संकेत देते हुए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एवं एनयूआरएम) शुरू किया, जिसका मकसद शहरों की आर्थिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना और उन्हें बेहतर बनाने के साथ शहरी गरीबों को सस्ते घर और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है।

यह अभियान दिसंबर 2005 से मार्च 2014 तक चला। अपने संघीय ढांचे की वजह से केंद्र सरकार की जेएनएनयूआरएम जैसे तमाम अभियान राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों, जिन्हें अपने इलाके में काम करने का अधिकार है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सिर्फ उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग आवर सिटीज किताब में (हार्परकोलिंस 2014) में लेखिका ने कई केस स्टडी का जिक्र यह दिखाने के लिए किया है कि कैसे कुछ क्षेत्रों के भारतीय शहरों में छोटी अवधि में भी सेवाएं मुहैया कराने की स्थिति में सुधार हुआ है। यह तभी मुमकिन हुआ जब राज्य सरकारों ने शहरों की स्थानीय सरकारों को सुधार और नवीनीकरण का माहौल मुहैया कराया। जहां-जहां परियोजनाओं की योजना बनाने, लागू करने और उनके प्रबंधन की क्षमता थी वहां शहरों की वित्तीय स्थिति दूसरी जगहों से ज्यादा मजबूत हुई। अध्ययन में पाए गए ये संकेत भारत सरकार द्वारा घोषित शहरी विकास से जुड़े नए राष्ट्रीय अभियानों के लिए काफी अहम हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत शहर लॉन्च किया गया था। इस अभियान का मकसद जनता में जागरूकता फैलाकर, खुले में शौच और मैला ढोने की प्रथा बंद करवाना, शौचालयों के निर्माण और तमाम तरह के कचरा उठाना और उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना है।

इन अभियानों की कामयाबी बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि लोगों की आदतों में किस हद तक बदलाव आता है। व्यवहार मनोविज्ञान की मदद से आम लोगों को साफ-सफाई के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हालांकि, जल का अभाव इसमें एक अड़चन है। अगर पानी नहीं रहेगा तो शौचालय किसी काम के नहीं हैं।

सभी वैधानिक कस्बों को दायरे में लाने के लिए अनुमानित रुपये 62,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। भारत सरकार ने इसमें 15,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया है और बाकी रकम का इंतजाम राज्यों के बजट/शहरी स्थानीय निकायों, यूजर शुल्क, जमीन से जुड़े शुल्क बढ़ाकर और निजी क्षेत्र के योगदान से होगा। बुनियादी सुविधाएं और संस्थाएं जरूरी हैं लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं। इन अभियानों की कामयाबी बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि लोगों की आदतों में किस हद तक बदलाव आता है। व्यवहार मनोविज्ञान की मदद से आम लोगों को साफ-सफाई के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हालांकि, जल का अभाव इसमें एक अड़चन है। अगर पानी नहीं रहेगा तो शौचालय किसी काम के नहीं हैं।

जून 2015 में भारत सरकार ने तीन बड़े राष्ट्रीय अभियानों का ऐलान किया। इनमें बदलाव और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत), 2022 तक सबके लिए आवास और स्मार्ट सिटीज मिशन शामिल हैं। एएमआरयूटी ने जेएनएनयूआरएम की जगह ली है। इसके दायरे में 500 शहर आते हैं और इसका फोकस पानी, नालियों, जल निकासी, परिवहन और हरियाली पर है। इन स्कीमों के लिए सरकार फंड दे रही है। पांच साल की अवधि में इसके लिए 50,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जेएनएनयूआरएम की तरह फंड का आवंटन सुधार से जुड़ा होगा। दुर्भाग्य की बात है कि नगरनिगम का ठोस कूड़ा एएमआरयूटी के दायरे में नहीं है। हालांकि, यह सफाई के लिहाज से काफी महत्वूपर्ण है। एएमआरयूटी की सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों में सुधार लागू करना है जहां जेएनएनयूआरएम नाकाम हो गई थी। ज्यादातर शहरों की स्थानीय सरकारें सुधार की सीमा तक पार नहीं कर पाईं कि एक भरोसेमंद रेवेन्यू मॉडल बन सके। इन्हें पीपीपी के जरिए फंड जुटाने या नगरनिगम बॉन्ड मार्केट्स तक पहुंचने में बहुत कामयाबी नहीं मिली है।

सबके लिए घर योजना के तहत 2022 तक शहरों में 2 करोड़ घर बनाने का टारगेट है। केपीएमजी के अनुमान के मुताबिक, 2022 तक 11 करोड़ घरों की मांग होगी। ऐसे में सरकार के इस अभियान से आबादी के सिर्फ एक हिस्से को ही सुविधाएं मिल पाएंगी और ये आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लोग होंगे। अनुमान है कि घरों के निर्माण के लिए सरकार प्रति घर 1.5 लाख रुपये के साथ बैंक लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी भी देगी। इस योजना की कामयाबी कई बातों पर निर्भर करेगी। जैसे इसके लिए राज्य सरकारें कितनी जमीन मुहैया कराती हैं, केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से पर्याप्त रकम का प्रावधान, सरकारी गारंटी न मिलने पर भी बैंकों द्वारा लोन मुहैया कराना और राज्य सरकारों की तरफ से जरूरी शहरी बुनियादी ढांचा मुहैया कराना शामिल है। इस पर ध्यान देना जरूरी है कि किराए के घर, जिससे निचले तबके की जरूरत पूरी होती है, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इस कमी को भी पूरा करना चाहिए।

स्मार्ट सिटीज मिशन बहुत महत्वाकांक्षी अभियान है, जिससे शहरों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन मिलेगा और चुनिंदा 100 शहरों में साफ और सतत माहौल मुहैया होगा। यह दुनिया भर में चल रहे 'स्मार्ट सिटीज' के ट्रेंड के मुताबिक ही है लेकिन स्मार्ट सिटीज की कोई तय परिभाषा नहीं है। भारत सरकार अगले पांच साल में 100 स्मार्ट सिटीज के लिए 48,000 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए इन 100 शहरों का चयन सरकार करेगी।

इन स्कीमों की फंडिंग और लक्ष्य में कोई तालमेल नहीं है। इस मिशन के तहत मौजूदा शहरों के कुछ इलाकों में पुनर्विकास किया जा सकता है और साथ ही नए स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे। इन शहरों में बेहतरीन परिवहन व्यवस्था मुहैया कराना भी इसका मकसद है।

सबके लिए घर योजना के तहत 2022 तक शहरों में 2 करोड़ घर बनाने का टारगेट है। केपीएमजी के अनुमान के मुताबिक, 2022 तक 11 करोड़ घरों की मांग होगी। ऐसे में सरकार के इस अभियान से आबादी के सिर्फ एक हिस्से को ही सुविधाएं मिल पाएंगी और ये आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लोग होंगे।

एएमआरयूटी से उलट स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए एक अलग सेज (स्पेशल पर्पज व्हीकल) बनाया जाएगा। एएमआरयूटी के संचालन का जिम्मा शहरी स्थानीय सरकारों की है। अगर हम स्मार्ट सिटीज को परिभाषित करें तो एक ऐसा शहर जहां के बाशिंदों को बेहतर शासन प्रणाली चाहिए और बेहतर प्रशासन या उच्च तकनीक के जरिए सरकार पारदर्शी और जवाबदेह बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं मुहैया कराएगी। तब स्मार्ट सिटीज का काम उच्च तकनीक वाले बुनियादी योजना के जरिए संस्थागत सुधार को बढ़ावा देना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे संघीय शासन में शहरों पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव के बावजूद हालात आज से बेहतर रहेंगे लेकिन हमारे शहरों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए हमें उस राजनीतिक माहौल में सुधार करने की जरूरत है जिसमें हमारे शहर काम करते हैं। ❑

स्मार्ट शहरः भारतीय संदर्भ

उषा पी रघुपति

भारत अन्य देशों की तरफ प्रेरणा के लिए देख सकता है लेकिन इसे अपने शहरों को तकनीकी रूप से उच्चतर और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने देश के हिसाब से समाधान ढूंढने चाहिए। विकासशील स्मार्ट सिटीज के लिए टिकाऊ विकास और टिकाऊ समाधान आखिरी लक्ष्य होने चाहिए। जब तक हम प्रशासन में सुधार और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम दुनिया के स्मार्ट सिटीज की तरह अपने देश के शहरों को बनाने का स्वप्न पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हम स्मार्ट सिटीज बनाने में कामयाब हो जाएं लेकिन हमें प्रशासन में सुधार लाना ही होगा ताकि हमारे ये खूबसूरत शहर फिर से पुराने ढर्रे पर न लौट जाएं

भारत ने इस बात को अब स्वीकार कर लिया है कि शहरी भारत की विकास दर ग्रामीण भारत की विकास दर से वास्तविक अर्थों में ज्यादा है। सन् 2001-2011 के दशक में शहरी भारत ने अपनी आबादी में 9.1 करोड़ लोगों को जोड़ा जबकि ग्रामीण भारत ने उसी अवधि में 9 करोड़ लोगों को जोड़ा। देश में शहरों के विकास के लिए चलाई गई योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण विकास योजना (जेएनएनयूआरएम) से पहले शहरी क्षेत्र के विकास के लिए जो धन राशि आबंटित की जाती थी, वो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में महत्वहीन थी। जेएनएनयूआरएम ने इस दिशा के चिंतन में एक व्यापक परिवर्तन लाया। इसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि शहरी भारत देश के आर्थिक विकास और तरक्की में एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभाता है।

भारत के शहर देश की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं और देश के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम दो तिहाई का योगदान देते हैं। जब तक शहरों में अच्छी गुणवत्ता की बुनियादी सुविधाएं, सक्षम बुनियादी ढांचे और सेवाएं नहीं दी जाएंगी, भारत की अर्थव्यवस्था अपनी महात्वाकांक्षी 8 फीसदी की विकास दर नहीं हासिल कर पाएगी।

2011 के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक भारत में 4041 विधिक शहर हैं और 3894 जनगणना शहर हैं (वे इलाके जो भारत की जनगणना की परिभाषा के मुताबिक शहरी घोषित किए गए हैं)। भारत की शहरी आबादी का लगभग 70 फीसदी ऐसे शहरों या शहरी बसावटों में रहता है जिनकी आबादी एक लाख या उससे ऊपर है। जहां इनमें से ज्यादातर शहर तेज रफ्तार से बढ रहे हैं वहां भारत के महानगर (जिनकी आबादी 50 लाख या ज्यादा है) विकास की रफ्तार के दवाब में चरमरा रहे हैं। जो शहर खासकर बहुत तेजी से बढ रहे हैं उनको बढ़िया तरीके से नियोजित करने की जरूरत है, उनको बेहतर समाधन की जरूरत है। वर्तमान में भारत के शहरी इलाकों में बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे बुनियादी ढांचों की कमी, आधारभूत सेवाएं, गरीबी, झुग्गी-झोपड़ियां, अपर्याप्त आवासीय सुविधाएं, परिवहन के साधन, घनी बसावट और हर तरह के प्रदूषण इत्यादि। साथ ही वहां पर्यावरण में बदलाव से उत्पन्न समस्याएं और बढती जा रही प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाएं भी शामिल हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान और सुशासन की आवश्यकता है।

भारत के ज्यादातर शहरों का मास्टर प्लान नहीं बना है और इसीलिए वहां अनियोजित शहरीकरण हो रहा है जो ज्यादा चिंता का विषय है। खासकर बुनियादी ढांचों और सेवाओं को प्रदान करने के संदर्भ में तो बहुत चिंता का विषय है। शहरों के ज्यादातर हाशिए के इलाके तो लगभग 'प्रशासन रहित' इलाके हैं क्योंकि न तो वे शहरी इलाके हैं और न ही ग्रामीण। जैसे-जैसे शहरों का फैलाव होता है तो ये हाशिए के इलाके भी शहर मे शामिल हो जाते हैं जो ज्यादातर अनियोजित होते हैं। इसीलिए एक गहन योजनाकृत विकास की आवश्यतकता है जो शहरों के विकास को नियमित कर सके, क्योंकि बाद में शहर को नियोजित करना या पुनर्विकास करना बहुत कठिन कवायद होती है।

वर्तमान सरकार की मुख्य योजनाएं जिसमें 100 स्मार्ट शहर, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन

लेखिका राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान (एनआईयूए) में प्रोफेसर हैं। नगर नियोजन में उन्हें 34 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। वह शहरी अवसंरचना, शहरी सेवाएं, शहरी पर्यावरण, शहरी गरीबी और शहरी हरित विकास आदि विषयों पर काम कर चुकी हैं। फिलहाल वह पूरे भारत में शहरी जलवायु परिवर्तन संतुलन तथा स्थानीय नगर शासन इकाईयों के अधिकारियों के क्षमता विकास के विषय पर काम कर रही हैं। ईमेलः uraghupathi@niua.org

एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन (अमृत), नेशनल हैरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अग्यूमेंटेशन योजना (हृदय), स्वच्छ भारत अभियान और हाउसिंग फॉर ऑल का उद्देश्य शहरों को रहने योग्य, समावेशी, गतिशील, तकनीकी रूप से उच्चतर और आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक किसी स्मार्ट सिटी के मूल बुनियादी तत्वों में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल होंगी:

- पर्याप्त जलापूर्ति
- सुनिश्चित बिजली आपूर्ति
- स्वच्छता (ठोस कचरा प्रबंधन सहित)
- सक्षम शहरी परिवहन और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था
- सस्ते आवास, खासकर, गरीबों के लिए
- शानदार आईटी संचार और डिजिटलाइजेशन
- सुशासन, खासकर, ई-प्रशासन और नागरिक भागीदारी
- संवहनीय पर्यावरण व्यवस्था
- नागरिकों की सुरक्षा, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा
- स्वास्थ्य और शिक्षा

स्मार्ट सिटी मिशन में इलाकेवार तरीके से विकास के रणनीतिक तत्व हैं-शहर का सुधार (पुराने इलाकों का अनुकूल विकास), पुनर्जीवन (पुनर्विकास) और नगरीय प्रसार (हरित क्षेत्र विकास) और संपूर्ण नगरीय विकास जिसमें बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान को लागू किया जाएगा और शहर के बड़े हिस्सों को इसकी जद में लिया जाएगा। (स्मार्ट सिटी रणनीति- भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट से)

स्मार्ट सिटी उन विचारों की संकल्पना करता है जिसके मुताबिक एक शहर सुचारु रूप से चलता है और उसकी हर गतिविधि अपने नियत तरीके से होती है। ये वैसे शहर होते हैं जहां आधारभूत सुविधाओं तक सबकी पहुंच होती है, सक्षमतापूर्वक सेवाओं को पहुंचाया जाता है, स्वच्छता होती है, बढिया परिवहन प्रणाली होती है, साइकिल के लिए अलग से रास्ता होता है, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता होता है, हरियाली होती है, जलाशय होते हैं, हरित मकान, हरित ऊर्जा, ई-प्रशासन, डिजिटल तकनीक का प्रयोग, सक्षम सूचना और संचार के तंत्र आदि-आदि होते हैं। हमें अपने शहरों को बदलने के लिए इन सारे मोर्चों पर काम करना होगा। स्मार्ट सिटीज में भविष्य का दृष्टिकोण भी होना चाहिए कि आनेवाले दिनों में शहर कैसे होंगे और उनके भविष्य में फैलाव के उपाय भी होने चाहिए।

भारत के संदर्भ में स्मार्ट सिटी को अग्रलिखित बातों को सम्मिलित करना चाहिए: तकनीक, वित्तीय व्यवस्था, आंकड़ों तक पहुंच, ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यावरण परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं का समाधान व उसकी रोकथाम, आपदा प्रबंधन, सुधार, प्रशासन और नागरिक।

तकनीक: शहरों के प्रबंधन में डिजिटल तकनीक कल्पनाशील तरीके से सक्षम समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं चाहे वो परिवहन हो (यातायात और परिवहन), शहरी योजना या बुनियादी ढाचों का निर्माण और सेवाएं जैसे कि जलापूर्ति, नाली की व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन इत्यादि। स्मार्ट सिटी को सड़कों पर भीड़भाड़ कम करनी चाहिए और वायु प्रदूषण को भी। साथ ही उसे बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। सेंसर का इस्तेमाल और वास्तविक समय में आंकड़ों को प्रदान करने से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि सेवाएं कैसे काम करती हैं और लोग उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। घरों में पानी और बिजली के लिए डिजिटल मीटर लगाने से लोग खुद भी अपने उपभोग की दर को देख सकेंगे और संसाधनों का अपव्यय रोक पाएंगे। सूचना और संचार तकनीक को सामाजिक क्षेत्र का भी ध्यान रखना चाहिए और समावेशी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर उसका ऐसा उपयोग हो कि कल्पनाशील तरीके से हम सेवाओं को बुजुर्गों, विकलांगों, गरीबों और समाज के अशिक्षित वर्गों तक पहुंचा सकें।

स्मार्ट सिटी मिशन में इलाकेवार तरीके से विकास के रणनीतिक तत्व हैं-शहर का सुधार (पुराने इलाकों का अनुकूल विकास), पुनर्जीवन (पुनर्विकास) और नगरीय प्रसार (हरित क्षेत्र विकास) और संपूर्ण नगरीय विकास जिसमें बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान को लागू किया जाएगा और शहर के बड़े हिस्सों को इसकी जद में लिया जाएगा।

वित्त: देश में ढेर सारे सेवा प्रदाता हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए वित्त की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे शहरों में नगरीय प्रशासन वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। यहां तक कि आधारभूत सेवाएं और वेतन भी नहीं दे पा रहे। इसीलिए स्मार्ट सिटीज को सरकार में उच्चतर स्तर से, वित्तीय संस्थाओं, निजी क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से वित्त पोषण हासिल करना होगा। सरकार और निजी क्षेत्रों को इसमें निवेश करना होगा और दीर्घावधि रखरखाव के लिए उपभोक्ताओं से पैसा लेना होगा।

आंकड़ों तक पहुंच: स्मार्ट शहरों को बुनियादी ढांचों और सेवा की सूचनाओं में खुलापन लाना होगा, खासकर उन सूनचाओं के लिए जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं। इसके लिए हरेक शहर में स्तरीय और मानकीकृत सूचना सेवा के रखरखाव की जरूरत होगी। तकनीक की मदद से सूचनाओं की क्राउड सोर्सिंग (तकनीक के माध्यम से अलग-अलग तरह की सूचनाओं का एक ही जगह जमावड़ा) भी की जा सकती है जो सामान्य परिस्थितियों में हासिल करना कठिन कार्य होगा। ये वास्तविक समय में हासिल होने वाले आंकड़े भी होंगे। सूचनाओं तक पहुंच से सेवा प्रदाता और उपभोक्ता सशक्त होंगे। इससे आम जनता का जीवन स्तर सुधरने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा: हरित और स्वच्छ ऊर्जा (नवीकृत), स्मार्ट ग्रिड, आधुनिक हरित इमारतें जो ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन के इस्तेमाल और संरक्षण को उच्चस्तर तक कर सकती हैं, ये सारी बातें किसी भी स्मार्ट सिटी में होनी ही चाहिए। इससे पर्यावरण की क्षति को भी रोका जा सकेगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम किया जा सकेगा जिस पर भारत ने वैश्विक वार्ताओं में सहमति दर्ज की है।

पर्यावरण: स्मार्ट सिटी में हरित इलाके जो जैव-विविधता को प्रोत्साहित करते हों, हरित इलाके (जैसे पार्क, जंगल आदि) जो कार्बन सिंक के रूप में काम करें, नागरिकों के लिए खुली जगहें कि वे आपस में बातचीत कर सकें, स्वच्छ हवा, जलाशयों का निर्माण और उनका संरक्षण जिसमें बारिश का पानी जमा हो सके, भूजल को रिचार्ज किया जा सके या जो तीव्र बरसात के समय उसको सोखने का काम कर सके, इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए।

पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सुरक्षा: स्मार्ट सिटीज ऐसे हों जो पर्यावरण के अनुकूल हों, उसमें हो रहे बदलावों का सामाधन पेश कर

सकें और बचाव के उपाय कर सकें। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट सिटी की योजना बनाते समय ही हमें ऐसे उपायों की योजना बनानी होगी। मिसाल के तौर पर जल क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण, इस्तेमाल किए गए पानी का पुनर्चक्रण, जलापूर्ति के विभिन्न स्रोतों की पहचान, जलवाही चट्टानों को रिचार्ज करना और जल संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देना आदि कार्य शामिल हैं। इससे उन शहरों को जल की समस्या से जूझने में मदद मिल सकेगी जो पर्यावरण में आ रहे बदलावों की वजह से हो सकते हैं। दूसरी मिसाल है ऊर्जा के एक ही स्रोत पर निर्भरता को कम करना। जैसे छोटी-छोटी छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना आदि-आदि।

आपदा और जोखिम प्रबंधन: अक्सर ही कई तरह की आपदाएं शहरों को चोटिल करती रहती हैं और जैसा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर आशंकाएं हैं, इसमें बढोत्तरी ही होगी। इसीलिए स्मार्ट सिटीज को आपदा प्रबंधन को लेकर पहले से तैयार रहने की जरूरत पड़ेगी। उन आपदाओं में बाढ, भूकंप, आगजनी और भूस्खलन कुछ भी हो सकते हैं। उन आपदाओं के समय ही किसी स्मार्ट सिटी की परीक्षाएं ली जाएंगी। स्मार्ट सिटी की योजना बनाते समय इस बिंदु का ध्यान रखना होगा।

भारतीय शहरों में परिवर्तन लाने में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि संस्थाओं और व्यक्तियों का परिवर्तन के प्रति अनुकूलित होने और उसे प्रबंधित करने की उपयुक्त सक्षमता नहीं है। नए तरीके से काम करने और नई तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए हमें नए कौशल और ज्ञान की जरूरत पड़ेगी।

सुधार: शहरी भारत को न केवल उन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है जिसकी वकालत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में की गई है बल्कि अगली पीढ़ी के सुधारों को भी करने की आवश्यकता है जो जेएनएनयूआरएम के अगले चरण के लिए रखे गए हैं। बुनियादी ढांचों और सेवाओं के रखरखाव और परिवर्तनों को संवहनीय रूप से लागू करने के लिए उन सुधारों को लागू करना ही होगा।

सुशासन: किसी शहर को बढिया तरीके से प्रबंधित करने के किए सुशासन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विकसित और विकासशील दुनिया का मूल अंतर सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि सुशासन है। नियम, विनियम और उनका क्रियान्वयन इस बात में अहम भूमिका निभाते हैं कि कोई शहर कैसे काम करता है। भारत में हरेक क्षेत्र में बहुत ही बढिया नियम-कायदे हैं लेकिन बहुत खराब क्रियान्वयन का रिकॉर्ड है। स्मार्ट सिटीज में मजबूत प्रशासन की आवश्यकता होगी जिसमें तकनीक का इस्तेमाल अपरिहार्य होगा। स्थानीय स्तर पर हमारे शासन की इकाइयों को एक दूसरे के साथ तालमेल और सहयोग की भावना से काम करना होगा, न कि पृथक-पृथक अपने अंदाज में जैसा कि ज्यादातर मामलों में आजकल हो रहा है। प्रशासन को सुधारने के लिए एजेंसियों और सरकारी विभागों में सूचनाओं का आदान-प्रदान करना होगा। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुने हुए नेता ही आखिरकार प्रशासन की रूपरेखा तय करते हैं। स्मार्ट सिटीज में पारदर्शी और जिम्मेदार सरकार की आवश्यकता होगी। शहरों के बढ़िया प्रबंधन के लिए प्रशासन में क्षैतिज और लंबवत एकीकरण व तालमेल जरूरी है।

भारतीय शहरों में परिवर्तन लाने में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि संस्थाओं और व्यक्तियों का परिवर्तन के प्रति अनुकूलित होने और उसे प्रबंधित करने की उपयुक्त सक्षमता नहीं है। नए तरीके से काम करने और नई तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए हमें नए कौशल और ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। प्रशासन में तभी सुधार आ पाएगा जब इस तरह के ज्ञान और कौशल को नियमित रूप से और सदा चलते रहने वाले क्रियाकलाप के तौर पर लिया जाए।

नागरिक: किसी भी शहर के कामयाब प्रबंधन में नागरिकों की भूमिका केंद्रीय होती है। प्रशासन को हरेक क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उपाय करने चाहिए। स्मार्ट सिटीज में ऐसे प्रशासनिक ढांचे होने चाहिए जो नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दे सके। इससे ऐसा होगा कि लोग शहरों के प्रति अपना लगाव दिखाएंगे और इसके नीति निर्माण में भागीदारी कर सकेंगे। साथ ही नागरिकों को भी बुनियादी ढांचे और सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए पहल की जानी चाहिए। नागरिकों के व्यवहार और उनकी प्रतिक्रिया को बदलने के लिए स्मार्ट सिटीज में उच्च तकनीक समाधान प्रस्तुत करना होगा और इसके लिए सूचना, शिक्षा और संचार की जरूरत पड़ेगी। कानून और विनियमन के द्वारा भी इन व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है।

नागरिकों को सशक्त बनाने में वैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो उपयोगी और उपयुक्त हों। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और किओस्क के माध्यम से स्मार्ट सिटीज को अपने नागरिकों तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम करना चाहिए।

भारत, भौगोलिक, सांस्कृतिक और विकास के स्तर के संदर्भ में एक विशाल देश है। किसी भी स्मार्ट सिटी की योजना बनाते समय देश की विविधता का ख्याल रखा जाना चाहिए। सबके लिए एक ही जैसी योजना से इच्छित नतीजे हासिल नहीं हो पाएंगे। हमें अपनी योजनाओं को बनाते समय देसी ज्ञान और समाधानों को भी महत्व देने की आवश्यकता है।

किसी भी शहर के कामयाब प्रबंधन में नागरिकों की भूमिका केंद्रीय होती है। प्रशासन को हरेक क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उपाय करने चाहिए। स्मार्ट सिटीज में ऐसे प्रशासनिक ढांचे होने चाहिए जो नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दे सके।

स्मार्ट सिटीज के विकास में भारत की ललक को देखते हुए सिंगापुर, वियेना (ऑस्ट्रिया), सोंग्डो (कोरिया), बार्सीलोना (स्पेन) आदि शहरों के उदाहरण दिए जाते हैं। हालांकि भारत अन्य देशों की तरफ प्रेरणा के लिए देख सकता है लेकिन इसे अपने शहरों को तकनीकी रूप से उच्चतर और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने देश के हिसाब से समाधान ढूंढने चाहिए। विकासशील स्मार्ट सिटीज के लिए संवहनीय विकास और संवहनीय समाधान आखिरी लक्ष्य होने चाहिए। जब तक हम प्रशासन में सुधार और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम दुनिया के स्मार्ट सिटीज की तरह अपने देश के शहरों को बनाने का स्वप्न पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हम स्मार्ट सिटीज बनाने में कामयाब हो जाएं लेकिन हमें प्रशासन में सुधार लाना ही होगा ताकि हमारे ये खूबसूरत शहर फिर से पुराने ढर्रे पर न लौट जाएं। हमें हर व्यक्ति को परिवर्तन के लिए तैयार करना होगा। ❑

हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

Give the best ★ Take the best

निर्माण IAS

सफलता का पर्याय कमल देव (K.D.)

गुणवत्ता, विश्वसनीयता व सफलता हेतु प्रतिबद्ध

सामान्य अध्ययन

13 AUG. 9:00 AM

वैकल्पिक विषय

इतिहास

भूगोल

......with all updated and upgraded notes

"निर्माण ने पुनः सिद्ध किया कि यह अन्य संस्थानों से बेहतर है"

DELHI

996 First Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh) Delhi-09

PH.: 011-47058219, 9990765484, 9911568165З, 9871968820

ALLAHABAD

IInd Floor, Vinayak Complex, Behind Big Bazar, Civil Line, Allahabad, U.P. **PH: 09984474888**

GWALIOR

2/3 Aziz Complex, New Khera Pati Colony, Phool Bagh Gwalior (M.P.), **PH: 09753002277**

Website: www.nirmanias.com

E-mail: nirmanias07@gmail.com

8800475353

nirman.ias

पत्रचार कार्यक्रम उपलब्ध (011-47058219)

YH-144/2015

स्मार्ट शहरों में डिजिटल गवर्नेंस

आर चंद्रशेखर

स्मार्ट शहरों के परिदृश्य के अंतर्गत आने वाले कुछ कदमों का प्राथमिकीकरण स्मार्ट शहरों संभावित की आवश्यकताओं के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अगला कदम होगा निवेश को आकर्षित करना और उन मुख्य भौतिक और आईटी संरचनाओं को स्पष्ट रूप से कुछ सटीकता के संग बताना, जिनकी आवश्यकता होंगी

एक अनुमान के अनुसार 2050 तक विकासशील जगत के चौंसठ प्रतिशत लोग शहरों में रहेंगे तो वहीं विकसित देशों में यह आंकड़ा 86 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। त्वरित शहरीकरण ने शहरों की ओर ध्यान आकर्षित किया है और उन्हें स्मार्ट बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

स्मार्ट शहरों के परिदृश्य के अंतर्गत आने वाले कुछ कदमों का प्राथमिकीकरण स्मार्ट शहरों संभावित की आवश्यकताओं के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अगला कदम होगा निवेश को आकर्षित करना और उन मुख्य भौतिक और आईटी संरचनाओं को स्पष्ट रूप से कुछ सटीकता के संग बताना, जिनकी आवश्यकता होंगी।

शहरी प्रशासन: असंख्य चुनौतियां

सार्वजनिक और निजी संस्थाएं नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में सहयोग करती है। ये सेवाएं विविध प्रकार की हो सकती हैं और अक्सर हितधारकों के संग जटिल संबंधों में ही अंत होती हैं जो सहयोग और सुशासन की आवश्यकता को बताती है। जैव प्रणाली को अगर बताया जा सके तो इसका निर्माण निम्न के समन्वय से होता है: शहरी प्रशासन, परिचालन और रख रखाव, सार्वजनिक संरचना संपत्ति प्रबंधन, एकीकृत परिचालन और नागरिक सेवाओं से। जहां पर डिजिटल कार्य हो सकता है वहां पर मानव से कार्य कराना अकुशलता, अकुशल प्रयोग और रिसाव का कारण हो सकता है। चलिए हम कुछ समय लेते हैं और देखते हैं कि कैसे तकनीक के माध्यम से इन शहरों के शासन को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है और उन्हें एकदम विश्वस्तरीय शहर बनाया जा सकता है।

आम नजरिए से देखने पर शहरी शासन में संस्थागत भूमिकाओं का दोहराव व विखंडन, क्षमता का अभाव, वित्त अवरोध, सीमित स्वायत्ता, और नागरिकों के संग कमजोर संपर्क ही दिखाई देगा। यूएलबी और अन्य विभागों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल क्षमता निर्माण में सहायता कर सकता है। इसी प्रकार कार्यबल प्रबंधन को भी संसाधनों के आदर्श अनुप्रयोगों की सहायता से अधिक कुशलता के संग किया जा सकता है। ऑटोमेटिड व्यापार प्रक्रियाओं को मानव हस्तक्षेपों को कम से कम करने के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त नागरिक केंद्रित ऑनलाइन पोर्टल सरकार की मदद नागरिकों के संग जुड़ने के लिए और उनके विचार व प्रतिक्रिया को जानने के लिए कर सकते हैं।

परिचालन और रखरखाव के प्रति दृष्टिकोण अधिकतर अनौपचारिक होता है जहां पर सेवा प्रदाता का प्रदर्शन स्पष्ट नहीं होता है और जिसे गैर एकीकृत शहर प्रबंधन दृष्टिकोण के रूप में चिन्हित किया जाता है व मानव श्रम की कमी की गंभीर समस्या और भी गंभीर हो जाती है। संक्षेप में मुद्दों की प्रतिक्रियात्मक अवस्था, जिससे बचा जा सकता है। शहर के प्रदर्शन का लेखा-जोखा अपने नागरिकों को सेवा डिलिवरी की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाने और प्रदर्शन पर नजर रखने का अवसर प्रदान करता है। एकीकृत कमान और परिचालन केंद्र की मदद के संग कई विभागों में कार्य में पारदर्शिता में वृद्धि की जा सकती है। संभाव्यता विश्लेषण रखरखाव प्रणाली को बेहतर तरीके

लेखक आईटी-बीपीओ इंडस्ट्री की प्रमुख व्यापार संस्था एनएएसएससीओएम (नैस्कॉम) के प्रमुख हैं। वह संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के टेलीकॉम आयोग के अध्यक्ष भी रहे। दूरसंचार सचिव के तौर पर उन्होंने लाइसेंसिंग स्पैक्ट्रम प्रबंधन, राष्ट्रीय ब्राडबैंड प्लान तथा राष्ट्रीय टेलीकॉम पॉलिसी से संबंधित कई नीतियों में योगदान किया। उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2007-08 का लोक प्रबंधन का उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जा चुका है। ईमेल: president@nasscom.in

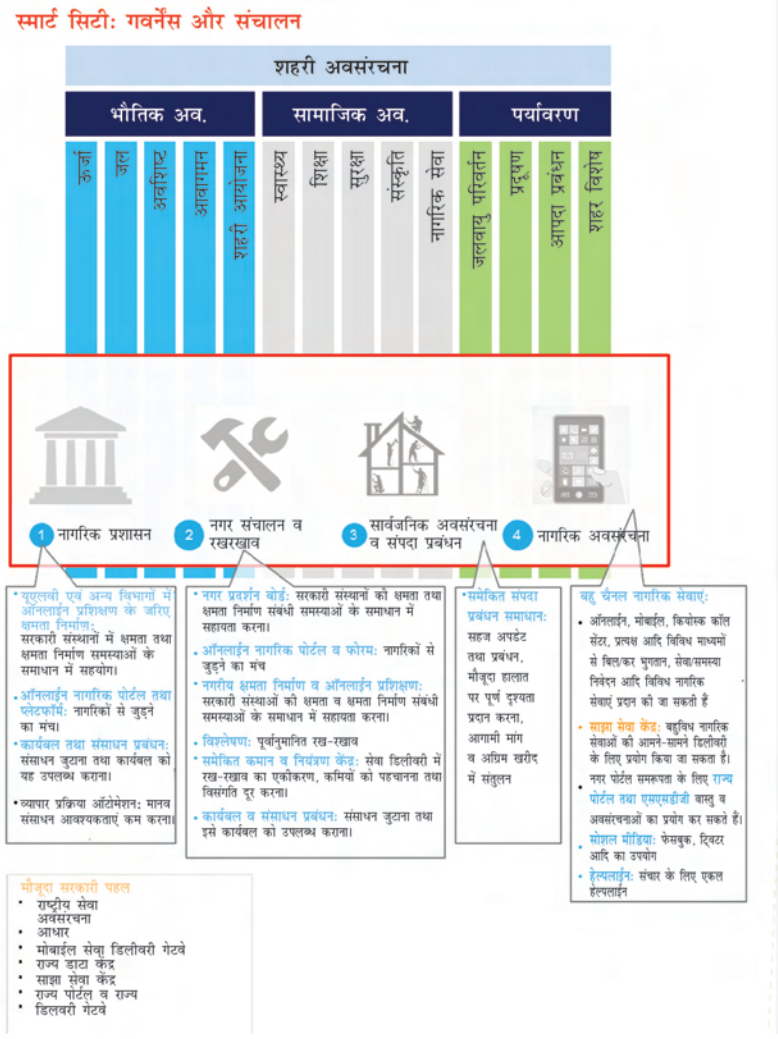

से समझने में सहायता कर सकता है जो अंततः बेहतर प्रदर्शन ही प्रदान करेगा।

सार्वजनिक संरचना और परिसंपत्तियों के प्रभावी नियोजन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अक्सर इंवेंट्री भी पुरानी होती है और रिकॉर्ड भी व्यक्तियों के द्वारा ही रखे जाते हैं जिससे एक विस्तृत परिसंपत्ति प्रबंधन रणनीति की कमी की ओर ही ले जाता है। एकीकृत परिसंपत्ति प्रबंधन समाधान परिसंपत्ति रख रखाव प्रक्रियाओं को बेहतर करके और परिसंपत्तियों, और रख रखाव सहित उसके प्रयोग पर दृश्यता प्रदान कर परिचालन लागतों को कम करता है।

बहु चैनल नागरिक इंटरफेस जैसे मोबाइल, वेब, फेस टू फेस, किओस्क और सोशल मीडिया कई प्रकार की नागरिक सेवाएं प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं जैसे बिल, कर के भुगतान के लिए, ऑनलाइन प्रमाणपत्र लेने के लिए और शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए। सोशल मीडिया इस संबंध में एक बहुत ही शक्तिशाली द्विपक्षीय संवाद चैनल बन कर उभरा है।

लाभदायक आईसीटी उपकरण व समाधान

- **व्यापार प्रक्रिया ऑटोमेशन:** एक पूर्णतः एकीकृत और नीति संचालित ऑटोमेटेड व्यापार प्रक्रियाओं के सेट के लिए व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन के प्रयोग से व्यापार प्रक्रियाओं को रीइंजीनियर करना, आदर्श रूप से प्रयोग करना और ऑटोमेट करना जो कुशलता में वृद्धि करती हैं और सेवा वितरण लागतों में कमी करती है।
- **बहु-चैनल नागरिक सेवाएं:** नागरिक सेवाओं जैसे बिल, कर के भुगताान के लिए, ऑनलाइन प्रमाणपत्र लेने के लिए और शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए आदि के लिए बहु चैनल नागरिक इंटरफेस (मोबाइल, वेब, फेस टू फेस, किओस्क और सोशल मीडिया)।
- **शहर प्रदर्शन डैशबोर्ड:** शहर की उप प्रणालियों के प्रदर्शन की निगरानी डिजिटल तकनीकों के प्रयोग से शहरी प्रशासन, प्रभावी प्रदर्शन और सक्रिय आपदा प्रबंधन के लिए करता है।
- **एकीकृत पूंजी प्रबंधन समाधान:** सभी शासन संरचना परिसंपत्तियों का एकीकृत परिसंपत्ति प्रबंधन, जिसमें संबंधित आंकड़े, प्रक्रियाएं, सूचना प्रणालियां और प्रबंधन योग्य परिचालनों व उच्च स्थायित्व वाला शासन सम्मिलित होता है।
- **एकीकृत कमान और परिचालन केंद्र:** प्रभावी एकीकृत कमांड और परिचालन केंद्र वास्तविक समय में शहरी सेवाओं की निगरानी करता है। खराब होने की अवधि को कम करने के लिए रख रखाव प्रभावोत्पादकता को बेहतर करने के लिए रख रखाव गतिविधियों को बेहतर करता है।
- **बहु चैनल नागरिक संवाद:** बहु चैनल उपभोक्ता इंटरफेस (सर्विस डेस्क/संपर्क केंद्र/नागरिक सेवा पोर्टल) कई चैनलों जैसे आमने सामने, वेब, मोबाइल, किओस्क आदि जैसे बहु चैनलों के माध्यम से नागरिकों के अनुरोध/समस्याओं को रिकॉर्ड करने में सहायता करता है।
- **कार्यबल और संसाधन प्रबंधन:** कार्यबल संलग्नता और संसाधन प्रबंधन को बेहतर करने के लिए कार्यबल व संसाधन प्रबंधन समाधानों को बेहतर करता है। कार्य क्रियान्वयन और प्रभावी प्रदर्शन उपकरणों के लिए नियोजन, पूर्वानुमान व शेड्यूलिंग, शिफ्ट प्रबंधन, मोबाइल अनुप्रयोगों जैसे कार्यबल प्रबंधन समाधानों की मदद से कार्यबल को बेहतर ढंग से प्रयोग करता है।

नैशनल सर्विस डिलिवरी इंफ्रास्ट्रक्चर:

यह मानक आधारित आंतरिक परिचालन क्षमता को हासिल करने के लिए मूल संरचना के रूप में कार्य करता है। परिणामस्वरूप यह एक सरकारी स्वामित्व के केंद्रीय गेटवे का निर्माण करने के लिए विकसित होगा। यह कई ई शासन अनुप्रयोगों के बीच में संदेश देने और आंतरिक परिचालन क्षमता को सुरक्षित करेगा, बैकएंड विभागों/सेवाओं प्रदाताओं को फ्रंट एंड सर्विस एक्सेस प्रदाताओं को अलग करेगा और भुगतान गेटवे सेवाओं, मोबाइल

(शेषांश पृष्ठ 28 पर)

IAS
GS World
GSI
PCS
सामान्य अध्ययन के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वसनीय संस्थान
Ashok Singh
Manikant Singh
Prof. Pushpesh Pant
Prof. Majid Hussain
Abhay Kumar
R. Kumar
Rajesh Mishra
Deepak Kumar
V. K. Trivedi
Pankaj Mishra
Subodh Mishra
Niraj Singh
Managing Director
Divyasen Singh
Co-ordinator
Delhi Centre
सामान्य अध्ययन
हिन्दी माध्यम
3 Sept.
9:00 am
IAS-2015
मुख्य परीक्षा 'क्रैश कोर्स'
10 Sept.
6:30 pm
General Studies
English Medium
5 Sept.
6:30 pm
Allahabad Centre
11 Sept. 5:00 pm
हिन्दी/Eng. Med.
21 Sept.
8:30 am & 5:30 pm
Lucknow Centre
हिन्दी/Eng. Med.
IAS - 2015 मुख्य परीक्षा क्रैश कोर्स
1 Sept.
5:30 pm
705, 2nd Floor, Main Road,
Mukherjee Nagar, Delhi - 9
PH. 011-27658013, 7042772062/63
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
PH. 0532-2266079, 8726027579
A-7, Sector-J, Near Puraniya
Chauraha, Aliganj, Lucknow
PH. 0522-4003197, 8756450894

YH-140/2015

राष्ट्रपति भवन: एक स्मार्ट धरोहर टाउनशिप

सुरेश यादव

स्मार्ट सिटी की अवधारणा मुख्यत: किसी ऐसे शहरी प्रतिष्ठान का उल्लेख करती है, जो नागरिकों के साथ ज्यादा कारगर और प्रभावी ढंग से पेश आने के लिए शहरी सेवाओं की गुणवत्ता और कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए डिजिटल टैक्नॉलजी का इस्तेमाल करती है। इसमें परिवहन और यातायात प्रबंधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य की देखभाल, पानी और कचरा प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। विकास के पथ पर आगे बढ़ने के उद्देश्य से, राष्ट्रपति भवन को 'स्मार्ट सिटी' में परिवर्तित करने के विचार ने जन्म लिया, क्योंकि यह महसूस किया गया है कि ऐसा राष्ट्रपति भवन में किया जा सकता है

राष्ट्रपति भवन की भव्य इमारत दुनिया में अपने किस्म की विशालतम इमारतों में से एक है। यह एक विशाल प्रासाद है, जिसका वास्तुशिल्प विस्मयकारी है। ब्रिटिश वास्तुकार, सर एडविन ल्युट्येन्स ने इसे डिजायन किया था और यह भारतीय एवं पाश्चात्य वास्तुशैलियों का मिश्रण है। शुरुआत में इसका निर्माण भारत में ब्रिटिश वायसराय के निवास स्थान के रूप किया गया था और उन दिनों इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। हालांकि 26 जनवरी 1950 को इसका नाम राष्ट्रपति भवन रख दिया गया: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान।

यह भवन 330 एकड़ संपदा में स्थित है और यह पांच एकड़ के दायरे में फैला है। इसका भव्य ढांचा एच आकार वाला एक भवन है जिसकी चौड़ाई 195 मीटर और गहराई 165 मीटर है। इसमें 340 कमरे और ढाई किलोमीटर लंबे गलियारे हैं। इसमें 227 खंबों और 37 फव्वारों सहित चार मंजिलें हैं। राष्ट्रपति भवन का मध्य गुंबद सांची के महान स्तूप से प्रेरित है। राष्ट्रपति भवन के खंबों पर भारतीय मंदिरों की घंटियां हैं, जो हिंदु, बौद्ध और जैन परंपराओं की मिली-जुली संस्कृति का द्योतक हैं। राष्ट्रपति भवन का सामने वाला हिस्सा अग्रप्रांगण कहलाता है, जिसमें स्तंभों की 200 मीटर लंबी कतार है। अग्रप्रांगण वाला रास्ता पोर्टिको तक जाता है, जहां वास्तुविद्या की महान रचना अशोक स्तंभ का बुल कैपिटल मौजूद है। अग्रभाग के बीचोंबीच जयपुर स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर स्टार ऑफ इंडिया है। यह भवन 3000 से ज्यादा लोगों का कार्यालय है, जो राष्ट्रपति भवन में काम करते हैं और 8000 से ज्यादा लोग इसके रिहायशी परिसर में, अर्थात राष्ट्रपति संपदा में निवास करते हैं।

राष्ट्रपति भवन का स्वागत कक्ष एक विशाल हॉल है, जो आगंतुकों को इस धरोहर भवन के शानदार स्थलों के देखने के लिए प्रवेश पास प्रदान करता है। स्वागत कक्ष के माध्यम से लोगों को निम्नलिखित दृश्य देखने का अवसर मिलता है :

- **मारबल हॉल:** इसमें ब्रिटिश काल की मूर्तियों और कलाकृतियों के साथ-साथ वायसरायों और ब्रिटिश शाही घराने के सदस्यों के दुर्लभ चित्र हैं।
- **दरबार हॉल:** इस विशाल हॉल में जैसलमेर का भव्य पीला संगमरमर लगा है और अद्भुत झाड़फानूस के साथ ही साथ गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 15 अगस्त 1947 को दरबार हॉल में ही नयी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था।
- **पुस्तकालय:** ज्ञान का विशाल गुंबद, जिसमें 1800 से 1947 तक प्रकाशित 2000 से ज्यादा दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है।
- **अशोक हॉल:** इसे मूलत: वायसरायों के नृत्य कक्ष के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में यहां राष्ट्रपति भवन के रस्मी समारोह आयोजित होते हैं। यह हॉल अपनी छत पर फतेह अली शाह की विस्मयकारी चित्रकारी के कारण विख्यात है।
- **मुगल उद्यान:** इसे राष्ट्रपति भवन की आत्मा समझा जाता है। यह 15 एकड़ में फैला है और इसमें 120 से ज्यादा किस्म के पेड़-पौधे हैं। मुगल उद्यान तीन हिस्सों

लेखक राष्ट्रपति भवन कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी हैं। ईमेल: osdtopresident@rb.nic.in

में बंटा है- : 1) आयताकार उद्यान 2) लॉन्ग उद्यान 3) वृताकार उद्यान

राष्ट्रपति भवन: राष्ट्रपति का विज़न

भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति भवन की परिकल्पना सशक्त उपनिवेशी व्यवस्था के पदक्रम की महज वैभवशाली झलक के रूप में नहीं करते, बल्कि एक ऐसी संस्था के रूप में करते हैं, जो इसकी संरचना और कामकाज को जाहिर करे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के साथ-साथ राष्ट्रपति संपदा में बेहतर सुख-सुविधाएं एवं साधन महैया करने की दिशा में सक्रिय पहल की है।

सूचना तक आसान और उचित पहुंच को बढ़ावा देने और देश के नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में जनता को उचित ढंग से प्रभावशाली सेवाएं मुहैया कराने के लक्ष्य के साथ विविध ई-गवर्नेंस पहलों को स्वीकार किया जाना शामिल है। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति की प्रभावशाली वैबसाइट बनाना, ऑनलाइन ई-कांफ्रेंस प्रबंधन प्रणाली, आंगुतक प्रणाली का ई-प्रबंधन, आरएफआईडी और सुरक्षा के लिए स्मार्ट कार्ड टैक्नॉलजी, वाईफाई सेवा और कई अन्य कदम शामिल हैं।

स्मार्ट सिटी टैक्नॉलजी की दिशा में यात्रा

स्मार्ट सिटी की अवधारणा मुख्यत: किसी ऐसे शहरी प्रतिष्ठान का उल्लेख करती है, जो नागरिकों के साथ ज्यादा कारगर और प्रभावी ढंग से पेश आने के लिए शहरी सेवाओं की गुणवत्ता और कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए डिजिटल टैक्नॉलजी का इस्तेमाल करती है। इसमें परिवहन और यातायात प्रबंधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य की देखभाल, पानी और कचरा प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। विकास के पथ पर आगे बढ़ने के उद्देश्य से, राष्ट्रपति भवन को 'स्मार्ट सिटी' में परिवर्तित करने के विचार ने जन्म लिया, क्योंकि यह महसूस किया गया है कि ऐसा राष्ट्रपति भवन में किया जा सकता है। इस पहल को अंगीकार करने से राष्ट्रपति भवन एवं राष्ट्रपति संपदा, भारत की सबसे पहली स्मार्ट सिटी होंगे। 330 एकड़ वाले धरोहर स्थल को आईसीटी द्वारा नियंत्रित भली-भांति कार्य करने वाली और आत्मनिर्भर टाउनशिप में परिवर्तित करने के लिए सभी आवश्यक मापदंडों की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रपति भवन में स्मार्ट सिटी की रूपरेखा में व्यापक तौर पर चार प्रमुख मापदंडों की पहचान की गई। ये थे:

राष्ट्रपति भवन: स्मार्ट सिटी पहल के प्रमुख क्षेत्र

ई-सेवाएं: शहरी सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए डिजिटल टैक्नॉलजी का इस्तेमाल करना।

सहनिर्माण: निवासियों को सार्वजनिक सेवाओं के निर्माण में भागीदार बनाने हेतु प्रौद्योगिक अवसरों का सृजन

ई-लोकतंत्र: लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली सार्वजनिक नीतियों और सार्वजनिक कार्रवाइयों को आकार देने में सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिक का इस्तेमाल सम्मिलित करना

पारदर्शिता: जनता को सूचना की आसान उपलब्धता और पहुंच के लिए डिजिटल प्रौद्योगिक का इस्तेमाल सम्मिलित करना

स्मार्ट सिटी पहल: प्रमुख क्षेत्र

राष्ट्रपति भवन में 2012 के बाद से प्रशासनिक कार्यकुशलता, संसाधनों का सर्वोत्तम प्रबंधन और पर्यावरण के अनुकूल (कागजरहित) तरीके से नागरिकों को व्यापक संतोष प्रदान करने के लक्ष्य के साथ ई-गवर्नेंस के लिए विविध कदम उठाए गए हैं। ये कदम व्यापक रूपरेखा अर्थात स्मार्ट सिटी मॉडल की शुरुआत भर हैं। राष्ट्रपति भवन में शुरू की गई कुछ बुनियादी आईसीटी पहल निम्नलिखित हैं:

क) भारत के राष्ट्रपति का वैब-आधारित प्लेटफॉर्म: भारत के राष्ट्रपति की एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो राष्ट्रपति भवन का विवरण देने के साथ-साथ वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में सभी प्रकार की उपयुक्त जानकारी उपयोगिता-सुलभ एवं संवादात्मक रूप से प्रदान करती है। यह वेबसाइट राष्ट्रपति भवन के विभिन्न ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के खूबसूरत विवरण के अलावा फोटो गैलरी और श्रव्य-दृश्य पुस्तकालय तक पहुंच भी प्रदान करती है। राष्ट्रपति की वेबसाइट को फेसबुक,

स्मार्ट सिटी के रूप में राष्ट्रपति भवन

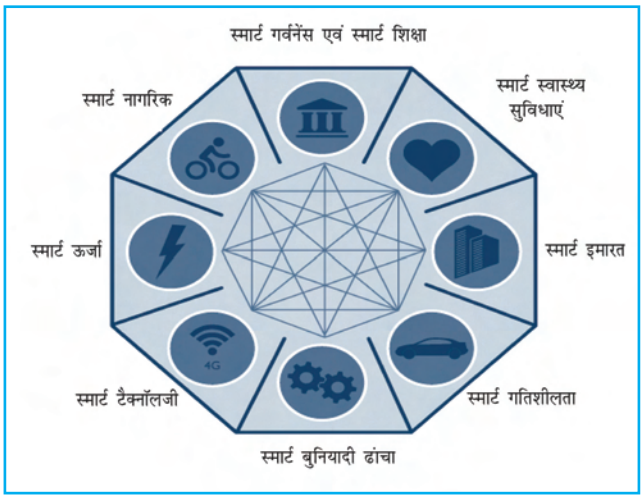

राष्ट्रपति भवन की बेवसाइट www.presidentofindia.nic.in का होम पेज

ट्विटर और यूट्यूब जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी जोड़ा गया है। इस प्लेटफॉर्म को एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स सहित विविध आईसीटी उपकरणों के साथ संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ख) ऑनलाइन ई-कांफ्रेंस प्रबंधन प्रणाली: यह एक प्रभावशाली एवं उपयोगिता-सुलभ वैब-आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के कुलपतियों/निदेशकों के राष्ट्रपति भवन में सालाना सम्मेलन के आयोजन के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कुलपतियों/निदेशकों को अपने-अपने केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के बारे में लक्ष्यों, उपलब्धियों और प्रगति रिपोर्ट्स आदि जैसी सूचना साझा करने के लिए लॉग-इन एक्सेस उपलब्ध कराता है, जिनका इस्तेमाल भविष्य में होने वाले सालाना सम्मेलनों की कार्यसूचियां, विचार-विमर्श, प्रतिभागियों और पैनल के सदस्यों के लिए संदर्भ के रूप में किया जा सकता है।

ग) आगंतुक प्रणाली का ई-प्रबंधन (ई-एमवीएस): यह वेब-आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे लोगों को राष्ट्रपति भवन देखने का अनुरोध दाखिल करने के लिए आसान पहुंच उपलब्ध कराने के वास्ते डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स पर काम करते हुए जीटूसी और सीटूजी रिलेशंस को सशक्त बनाने के लिए प्रभावी, पारदर्शक और उपयोगी सेवा की पेशकश करती है। यह प्रणाली एसएमएस और ई-मेल अधिसूचनाएं (नोटिफिकेशन्स) प्रदान करने के लिए समाविष्ट की गई है और किसी भी समय किसी भी आईसीटी उपकरण के माध्यम से इस तक पहुंच बनाई जा सकती है।

घ) ई-आमंत्रण प्रबंधन प्रणाली (ई-आईएमएस): यह एक वेब-आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे राष्ट्रपति भवन

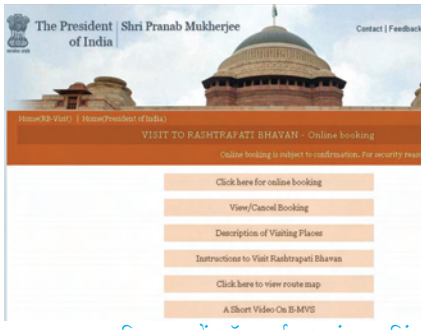

राष्ट्रपति भवन में ऑन लाईन आगंतुक बुकिंग

में आयोजित होने वाले विविध शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं रस्मी आयोजनों का डिजिटल आमंत्रण तैयार करने के वास्ते डिज़ाइन किया

ऑनलाइन ई-कांफ्रेंस प्रबंधन प्रणाली का होम पेज

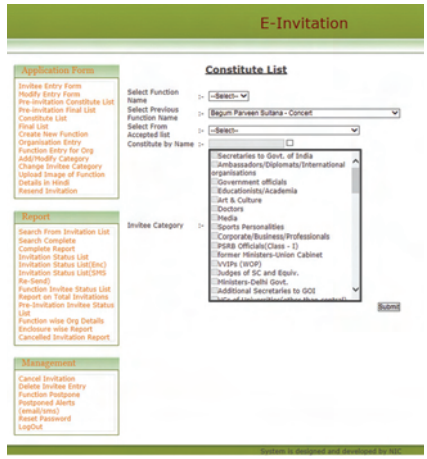

वेब आधारित प्लेटफार्म के जरिए ई-आमंत्रण भेजना

गया है। यह प्रणाली एसएमएस और ई-मेल अधिसूचनाएं (नोटिफिकेशन्स) और साथ ही साथ डिजिटल माध्यमों के जरिए स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए भी समाविष्ट की गई है। यह प्रणाली पूरे एनसीआर के क्षेत्रों में अनुरोध भेजने के लाभ की भी पेशकश करती है। यह बेहद किफायती प्रणाली है और इसमें बड़ी तादाद में आमंत्रण भेजने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की सेवाएं उपयोग में लाने की भी आवश्यकता नहीं रहती।

ङ) राष्ट्रपति ई-संदेश प्रणाली (ई-पीएमएस): यह एक वेब-आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे नागरिकों के साथ पेपरलेस एनवॉयरमेंट में यानी कागज़ का इस्तेमाल किए बिना, संवाद कायम कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह लोगों को डिजिटल माध्यमों से, महत्वपूर्ण अवसरों पर भारत के राष्ट्रपति का संदेश प्राप्त करने का अनुरोध दाखिल करने की व्यवस्था प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति का संदेश डिजिटल प्रारूप (पीडीएफ फॉर्मेट) में, ई-मेल के जरिए लोगों के साथ साझा किया जाता है और दाखिल किए गए अनुरोध के संबंध में अधिसूचनाएं (नोटिफिकेशन्स) एसएमएस अलर्ट्स के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। यह प्रणाली उपयोगिता-सुलभ एवं संवादात्मक और साथ ही साथ त्वरित एवं दक्ष रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

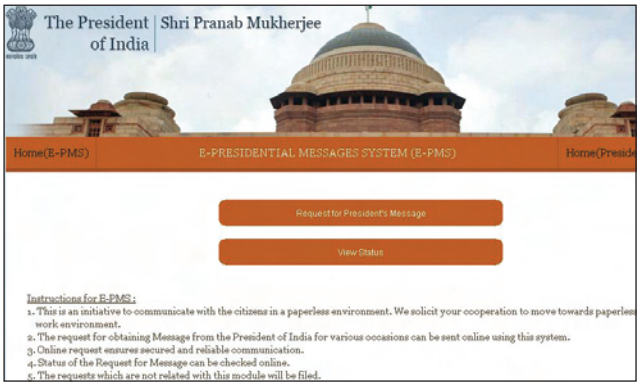

ई-राष्ट्रपति संदेश प्रणाली का होम पेज

ई-राष्ट्रपति समारोह प्रणाली (ई-पीएफएस): यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे नागरिकों को राष्ट्रपति को किसी शैक्षणिक, सांस्कृतिक और रस्मी समारोह में उपस्थित होकर उसकी शोभा में चार-चांद लगाने का अनुरोध करने के लिए आसान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली बिना अतिरिक्त सामग्री अथवा कर्मियों का उपयोग किए, बड़ी तादाद में मिलने वाले विविध अनुरोधों की सुगमता से व्यवस्था करने का लाभ उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली ई-मेल और एसएमएस अलर्ट्स के जरिए अधिसूचनाएं (नोटिफिकेशन्स) उपलब्ध कराने के लिए समाविष्ट की गई है। यह प्रणाली बेहद किफायती है और व्यापक पहुंच प्रस्तुत करती है।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त वर्णित डिजिटल प्रणालियां अन्य उपयोगी एवं प्रभावी प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत भी की गई है, जो स्मार्ट सिटी की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। उदाहरण के लिए, सभी विज़िटर्स पास, साथ ही साथ सभी अतिथियों के डिजिटल आमंत्रण, उनके समस्त व्यक्तिगत विवरणों से युक्त बारकोड टैक्नॉलजी के साथ एकीकृत कर दिए गए हैं, जिन तक सुरक्षाकर्मी बारकोड स्कैनर के माध्यम से आसानी से पहुंच बना सकते हैं, जो आसानी से सत्यापन के लिए फोटो फीचर्स युक्त होते हैं। बारकोड प्रणाली पार्किंग की सुविधाओं के साथ साथ यातायात के सुघड़ प्रबंधन का अवसर भी उपलब्ध कराती है।

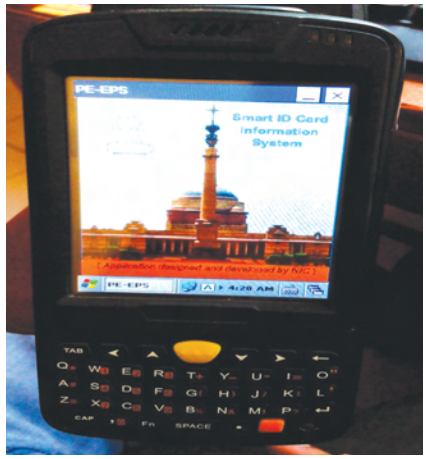

राष्ट्रपति की संपदा के निवासियों को जारी स्मार्ट कार्ड को रीड करने के लिए आरएफआईडी स्कैनर

रेडियो-फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) टैक्नॉलजी को राष्ट्रपति के सभी उपहारों साथ ही साथ धरोहर परिसंपत्तियों एवं कलाकृतियों के प्रबंधन के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन निगरानी सूचना प्रणाली (एएमटीआईएस) के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। आरएफआईडी टैक्नॉलजी को इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति संपदा के सभी निवासियों को जारी किए गए स्मार्ट आईडी काड्र्स के साथ जोड़ा गया है, ताकि सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता किए बगैर, उन लोगों का प्रवेश सुरक्षित तरीके एवं सुगमता से संभव हो सके। इसके अलावा, आरएफआईडी टैक्नॉलजी का इस्तेमाल ऐसे सभी व्यक्तियों की सुगम पहुंच और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है, जो राष्ट्रपति संपदा के निवासी तो नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन कामगार पास प्रणाली (आरबीडब्ल्यूपीएस) के अंतर्गत कुछ खास तकनीकी कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें राष्ट्रपति भवन आने की आवश्यकता पड़ती है।

राष्ट्रपति ई-कार्यक्रम प्रणाली का होमपेज

बार-कोडेड ई-आमंत्रण का नमूना

राष्ट्रपति भवन कामगार पास प्रणाली

राष्ट्रपति भवन के विभिन्न विभाग ई-कार्यालय का उपयोग कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा बनाया गया एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ज्यादा प्रभावशाली और पारदर्शितापूर्ण अंतर एवं अंत: सरकारी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करते हुए गवर्नेंस में सहायता प्रदान करता है। यह विभिन्न सरकारी कार्यालयों को सरल, उत्तरदायित्वपूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं पारदर्शक ढंग से कार्य करने की पेशकश करता है। यह एक मुक्त संरचना है, इसलिए यह विभिन्न सरकारी विभागों में दोबारा इस्तेमाल करने योग्य अनुकूल प्रतिरूप ढांचे की पेशकश करती है। ई-कार्यालय प्लेटफॉर्म ई-फाइल प्रबंधन प्रणाली, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, अवकाश प्रबंधन प्रणाली अथवा व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन प्रणाली जैसी विविध विशेषताओं की पेशकश करता है, जिन्हें विभाग की जरूरत के अनुरूप बनाया जा सकता है। सुरक्षित संचार में सुगमता के लिए ऑनलाइन आगंतुक अनुरोध सूचना प्रणाली

राष्ट्रपति भवन कामगार पास प्रणाली का सत्यापन फॉर्म

को राष्ट्रपति सचिवालय में ई-कार्यालय के साथ जोड़ा गया है।

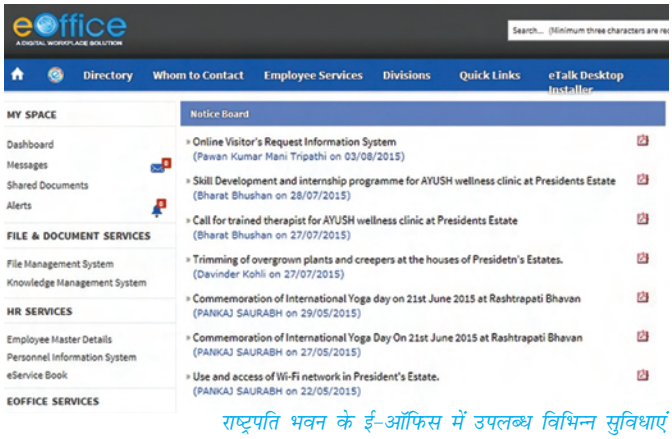

राष्ट्रपति भवन के ई-ऑफिस में उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं

ई-कार्यालय: विविध विशेषताएं

ऑनलाइन आगंतुक अनुरोध सूचना प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को टेलीफोन के जरिए संवाद के बदले, डिजिटल माध्यम से अग्रिम सूचना उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली अधिकारियों से उनके पंजीकृत मोबाइल उपकरणों के माध्यम से भी अनुरोध स्वीकार करने में सक्षम है। यह प्रणाली सुरक्षा से समझौता किए बगैर त्वरित एवं प्रभावशाली सेवाओं की पेशकश करती है।

ऑनलाइन आगंतुक अनुरोध सूचना प्रणाली

राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत सभी प्रमुख विभाग एक्सप्रेस वाईफाई सेवाओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस पहल का संपूर्ण राष्ट्रपति संपदा में विस्तार किया गया है। इसमें मुख्य रूप से निवासियों को वॉयरलेस इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि वे शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, मनोरंजन, बैंकिंग आदि के संबंधित सूचना तक पहुंच बना सके। इसके अलावा, राष्ट्रपति भवन के सभी अधिकारियों एवं निवासियों को राष्ट्रपति भवन स्मार्ट चेंज कॉर्ड जारी किए गए हैं, जो राष्ट्रपति संपदा के भीतर मुहैया कराई जाने वाली समस्त सेवाओं का लेन-देन कैशलेस माध्यम से कराने और साथ ही साथ पर्यावरण के अनुकूल सफर और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति भवन तक साइकिलों के जरिए पहुंच की पेशकश करते हैं।

राष्ट्रपति संपदा के अधिकारियों एवं निवासियों को जारी राष्ट्रपति भवन स्मार्ट चेंज कॉर्ड

राष्ट्रपति संपदा में वाईफाई सुविधा

राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति संपदा के निवासियों के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल की सुविधा की भी पेशकश करता है। इसका लक्ष्य कक्षा-12 के छात्रों को कंप्यूटर का हुनर एवं

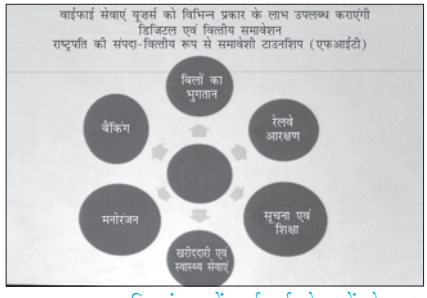

राष्ट्रपति संपदा में वाईफाई सेवाओं से लाभ

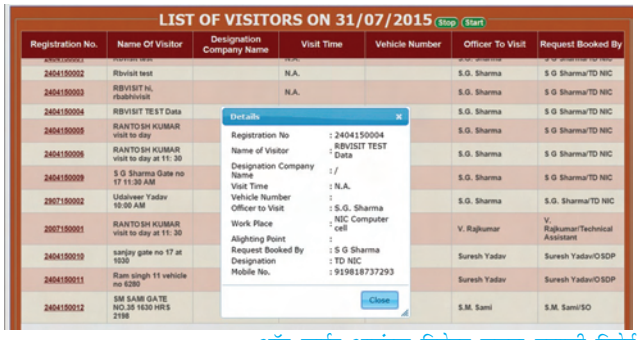

ऑन-लाईन आगंतुक निवेदन सूचना-प्रणाली रिपोर्ट

ज्ञान प्रदान करने के लिए इंटेल इंडिया के सहयोग के जरिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय को डिजिटल ज्ञान केंद्र में परिवर्तित करना था। यह पहल परिवर्तनशील शैक्षिक पद्धतियां लाई है, जिन्होंने बच्चों को

पर्यावरण के अनुकूल सफर और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए तैयार राष्ट्रपति भवन साइकिलें

राष्ट्र निर्माण के लिए ज्ञान का सृजन करने में समर्थ बनाने में सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, इंटेल ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी अहम भूमिका निभायी है, ताकि उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रभावी इस्तेमाल में सक्षम बनाया जा सके। इंटेल ने शिक्षण साथ ही साथ स्कूल में इलैक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले बोर्ड्स की शुरुआत करने के उद्देश्य से टैब्लेट्स उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी सहायता प्रदान करने की भी पेशकश की है।

राष्ट्रपति भवन की स्मार्ट सिटी प्रायोगिक परियोजना आईबीएम इंडिया के सहयोग से शुरू की गई है। इस परियोजना में टाउनशिप, उसकी प्रमुख परिसंपत्तियों और उपयोगिता नेटवर्क्स की जीआईएस मैपिंग शामिल है। इसमें डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से निरंतरता और संचालन संबंधी कार्यदक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा, जल, सुरक्षा और कचरा प्रबंधन जैसे विभिन्न वर्टिकल क्षेत्रों का एकीकरण होगा। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति में पहले से ही, विद्युत ऊर्जा वितरण की निगरानी डिजिटल इलैक्ट्रिकल मीटरों के माध्यम से की जाती है।

बिजली और पानी आदि जैसे अतिरिक्त संसाधनों की खपत को मोबाइल आधारित डाटा कलैक्शन सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जाएगा, जो रोजाना की खपत के स्वरूप जैसा विवरण साथ ही साथ उसका बिल भी उपलब्ध कराएगा। आईबीएम ने क्षेत्र में मैपिंग

डॉ. राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय में ज्ञान केंद्र

छात्र राष्ट्रपति के समक्ष कंप्यूटर और अन्य आईसीटी उपकरणों को ऑपरेट करने संबंधी अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए

का कार्य शुरू कर दिया है और यह विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। इस परियोजना का कार्यान्वयन डिजिटल साधनों के माध्यम से परिसंपत्तियों के बेहतर और कारगर प्रबंधन के लिए समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत में सहायता करेगा।

लाभ

राष्ट्रपति भवन में शुरू की गई स्मार्ट सिटी की पहल को त्वरित और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए विविध प्रकार की सरल, लेकिन नवीन ई-गवर्नेंस प्रणालियां संचालित किए जाने की वजह से सकारात्मक फीडबैक मिलना प्रारंभ हो चुका है। स्मार्ट सिटी पहल के तहत उपलब्ध कराए जाने/बढ़ावा दिए जाने वाले प्रमुख लाभ हैं :

- राष्ट्रपति भवन के विविध विभागों और जनता के बीच प्रत्यक्ष एवं पारदर्शक तरीके से किया जाने वाला कागज़ रहित संचार
- टाउनशिप का समग्र प्रभावी प्रबंधन
- डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से विकास के प्रति सतत दृष्टिकोण
- संसाधनों के सर्वोत्तम प्रबंधन के साथ प्रशासनिक कार्यकुशलता में समग्र वृद्धि
- लोगों का नागरिकों से सक्रिय नागरिकों के रूप में रूपान्तरण तथा नागरिकों की संतुष्टि का आकलन
- राजस्व प्रबंधन का अनुकूलन
- निचले और शीर्ष प्रबंधन के बीच एकीकरण
- समावेशी भागीदारी एवं निवास
- निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अत्याधिक कानूनों में ढील और संचालन में व्यापक लचीलेपन के माध्यम से नागरिकों की अनुकूल सेवाओं तक पहुंच। ❑

(पृष्ठ 22 का शेषांश)

गेटवे सेवाओं आदि जैसे विभागीय अनुप्रयोगों के लिए एक साझा सेवा केंद्र होगा।

आधार

यूआईडीएआई/आधार ऑन लाइन प्रमाणीकरण का एक मजबूत सेवा प्रदान करता है जहां संस्थाएं अपने पहले से ही केंद्रीय डेटा बेस में उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ नागरिकों की जनसांख्यकीय और बायोमैट्रिक सूचना की तुलना कर सकती हैं। यूआईएडीएआई/आधार नकली/दोहरी प्रविष्टियों से बचने के लिए सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है।

मोबाइल सर्विस डिलिवरी गेटवे

मोबाइल शासन, जिसे एम-गर्वनेंस भी कहा जाता है का लक्ष्य है सभी नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं और सूचना प्रदान करने के लिए वायरलेस और नई मीडिया तकनीकी मंचों, मोबाइल उपकरणों व अनुप्रयोगों को प्रभावी बनाना। यह ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों में संपर्क की संभावनाओं का विस्तार करेगा जहां मोबाइल की पहुंच इंटरनेट से अधिक है। कुल रणनीति समेकित विकास की शक्ति के द्वारा भारत को विश्व का नेतृत्वकर्ता बनाने की है।

राष्ट्रीय क्लाउड अभियान

एक जीआई क्लाउड के रूप में विकसित *मेघराज* भारत सरकार का क्लाउड है जो क्लाउड आधारित संरचना संसाधनों के आम कोष और मांग पर उपलब्ध अनुप्रयोगों के रूप में कार्य करता है। इसमें आईसीटी संरचना के आदर्श प्रयोग, ई शासन अनुप्रयोगों की नियुक्ति और त्वरित विकास, सफल अनुप्रयोगों के त्वरित प्रयोग और प्रमाणीकृत सेवाओं की मेजबानी सम्मिलित है।

राज्य डेटा केंद्र

सेवाओं, अनुप्रयोगों और सरंचनाओं को राज्यों के लिए जी2सी, जी2जी और जी2बी सेवाओं का प्रभावी इलैक्ट्रॉनिक वितरण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इन सेवाओं को स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गांव के स्तर तक दिया जा सकता है।

कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)

सीएससी का उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी वीडियो, वॉइस और डेटा कंटेंट सेवाओं को ई गर्वनेंस, शिक्षा, टेलीमेडिसिन, मनोरंजन व अन्य निजी सेवाओं में प्रयोग किया जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में वेब सक्षम ई गर्वनेंस सेवाओं को प्रदान करता है जिसमें आवेदन प्रपत्र, प्रमाणपत्र और बिजली, फोन और पानी के बिल सहित प्रमाणपत्रों और भुगतान जैसी सेवाएं सम्मिलित हैं।

स्टेट पोर्टल और सर्विस डिलिवरी गेटवे

राष्ट्रीय ई गर्वनेंस योजना का लक्ष्य सभी सरकारी सेवाओं को आम नागरिक तक उसके मुहल्ले में आम सेवा डिलिवरी आउटलेट से प्रदान करना और कुशलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता प्रदान करना है। यह सब केवल बहुत ही कम लागतों पर। सरकार का लक्ष्य एक एकीकृत सूचना संरचना प्रदान करना है जो उपयोगिता सेवाओं को बेहतर पहुंच के लिए विस्तारित, एकीकृत व बेहतर करेगी।

आईटी बीपीएम उद्योग के लिए इन सभी पहलों का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। अपने अपने क्षेत्र में ये सभी योजनाएं स्वयं में विशाल हैं और वांछित परिणामों को पाने के लिए उद्योगों से एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एक 146 अरब डॉलर उद्योग जिसने वैश्विक रूप से रास्ता दिखाया और सुदूर कई समाधानों को प्रस्तुत किया वह अब दोराहे पर है। अब यही सफलता भारत में दोहराने की जरूरत है और घरेलू प्रगति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ❑

वायदे हुए पूरे
परिणाम आये

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

वायदा

"मैं देश के गरीबों को बैंक खाते की सुविधा से जोड़ना चाहता हूँ।"

परिणाम

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की 28 अगस्त 2014 को शुरुआत; 17 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए; 29 जुलाई 2015 तक खातों में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत राशि।

मेक इन इंडिया

वायदा

"मैं दुनियाभर के लोगों से अपील करना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया... आइये हिंदुस्तान में अपने उत्पादों का निर्माण कीजिये।"

परिणाम

25 सितम्बर 2014 को **मेक इन इंडिया कार्यक्रम** की शुरुआत; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 48 प्रतिशत का इजाफा; बेसलाइन प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया का नंबर 1 निवेश गंतव्य।

स्वच्छ भारत

वायदा

"गरीबों को इज्जत मिले
शुरुआत स्वच्छता से हो
दो अक्तूबर से स्वच्छ
अभियान की शुरुआत क
उसे आगे ले जाऊंगा।"

परिणाम

दो अक्तूबर 2014 को
शुरुआत; 2019 तक
बनाने का लक्ष्य; देशभर
शौचालय निर्माण के
ओर सरकार अग्रसर।

69 वां स्वतंत्रता दिवस
15 अगस्त, 2015

प्रधानमंत्री से इंटरै
Narendra
Prime Minister
www.pmindia.g

YH-149/2015

सामने

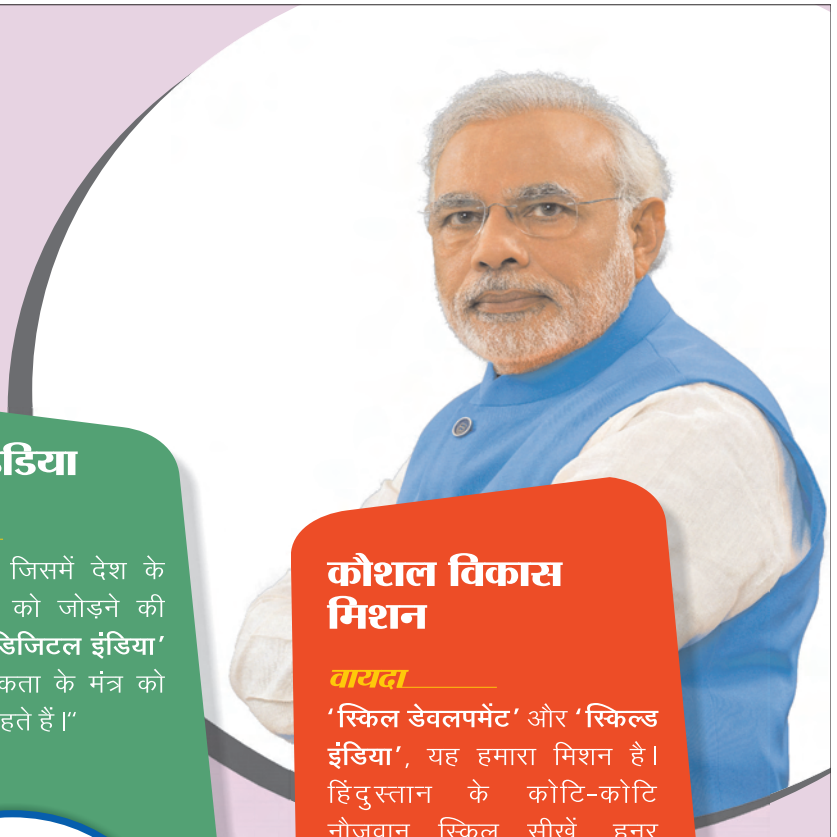

…जिसकी
…ती है। मैं
…छ भारत
…रूंगा और

…**स्वच्छ भारत** की
…भारत को स्वच्छ
…र के विद्यालयों में
…लक्ष्य प्राप्ति की

डिजिटल इंडिया

वायदा

"यह आईटी है जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को जोड़ने की क्षमता है। हम **'डिजिटल इंडिया'** के माध्यम से एकता के मंत्र को साकार करना चाहते हैं।"

Digital India
Power To Empower

परिणाम

1 जुलाई 2015 को **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम** की शुरुआत; योजना के जरिये भारत को डिजिटल माध्यम से जोड़ने का प्रयास; भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण जिससे आयात में कमी आयेगी; 75 बिलियन डॉलर का प्रस्तावित निवेश।

कौशल विकास मिशन

वायदा

'स्किल डेवलपमेंट' और **'स्किल्ड इंडिया'**, यह हमारा मिशन है। हिंदुस्तान के कोटि-कोटि नौजवान स्किल सीखें, हुनर सीखें।

SKILL INDIA

परिणाम

15 जुलाई 2015 को मिशन की शुरुआत; अगले 7 सालों में 40 करोड़ भारतीयों को कौशल्य प्रदान करना।

davp 22202/13/0029/1516

…ट करें
…Modi
…f India
…v.in

प्रधानमंत्री से जुड़िए
/Narendramodi

समाचार, विचार और अन्य
www.narendramodi.in

विचार साझा करें
myGov मेरी सरकार
www.mygov.in

सत्यमेव जयते
सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

Career Launcher

Civil Services Aspirants

200+*

CL छात्रों ने सिविल सेवा परीक्षा '14 में सफलता प्राप्त की

रैंक 13

निशांत जैन
CL पंजीकरण संख्या:
3003133

रैंक 25

मनीष मिश्रा
CL पंजीकरण संख्या:
10019970

रैंक 53

महिमा सिकंद
CL पंजीकरण संख्या:
10074278

रैंक 55

अनुराग जयंती
CL पंजीकरण संख्या:
10019081

रैंक 63

मेघा निधि दहल
CL पंजीकरण संख्या:
CL ID: 1037371

रैंक 89

शांतनु शर्मा
CL पंजीकरण संख्या:
CL ID: 10023473

रैंक 90

शिवाले अभिजीत तुकाराम
CL पंजीकरण संख्या:
CL ID: 1989179

और भी बहुत से...

*परिणाम आंतरिक परिवीक्षाधीन, पेड/ निःशुल्क मॉक टेस्ट में भाग लेने वाले सभी छात्रों को शामिल करते हुए

छात्रों की नज़र में CL

सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा के लिए CL की टेस्ट सीरीज़ अत्यंत लाभदायक रही। यह वास्तविक परीक्षा के बिल्कुल हू-ब-हू थी जिससे मैं परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सका। इसके अतिरिक्त, मॉक इंटरव्यू वाले पैनेल के सभी सदस्यगण अत्यंत सौहार्दपूर्ण थे उन्होंने इंटरव्यू के विभिन्न पहलुओं में मदद की।

रैंक- 63 मेघा निधि दहल
CL पंजीकरण संख्या: 1037371

CL का पीडीपी प्रोग्राम (मॉक इंटरव्यू) अत्यंत लाभदायक रहा। मॉक इंटरव्यू सत्र बहुत विस्तृत थे तथा पैनेल ने महत्वपूर्ण फीडबैक दिया जिससे कि मैं बेहतर तैयारी कर सकी।

रैंक- 114 श्रुति पांडेय
CL पंजीकरण संख्या: 10023474

सिविल सेवा परीक्षा में मेरी सफलता में टीम CL की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसने सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति बनाने में मदद की। CL के मॉक साक्षात्कार हू-ब-हू वास्तविक साक्षात्कार जैसे थे। मॉक इंटरव्यू के व्यक्तित्व विश्लेषण तथा महत्वपूर्ण फीडबैक से मेरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई।

रैंक- 509 गरिमा तिवारी
CL पंजीकरण संख्या: 10016671

2016 के लिए नए बैच उपलब्ध :

इंटिग्रेटेड GS फाउंडेशन (प्री + मेन) एवं CSAT (हिंदी एवं अंग्रेज़ी माध्यम)

पंजीकरण कराने के लिए 888-2-520-520 पर मिस कॉल करें

दिल्ली CL सिविल सेवा परीक्षा के अध्ययन केंद्र

मुखर्जी नगर: 204/216, द्वितीय तल, विराटभवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन – 41415241/46

ओल्ड राजेन्द्र नगर: 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट्स के सामने, फोन – 42375128/29

/CLRocks

Career Launcher

www.careerlauncher.com/civils

YH-138/2015

गांव होंगे स्मार्टनेस की असली कुंजी

संजय श्रीवास्तव

बेंगलुरु उन शहरों में है, जहां अच्छे तरीके से ग्रामीण इलाकों का शहरीकरण किया गया और शहर को विस्तार मिला। वहां बनी इलैक्ट्रॉनिक सिटी गांवों की जमीनों के सटीक उपयोग का ही नतीजा थी। इस शहर में अब विस्तार की ज्यादा संभावनाएं बेशक नहीं दीखती हों तब भी अनुमान है कि इसका मौजूदा 99 वर्ग किलोमीटर का एरिया और बढ़कर 696 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी को किस कदर गांवों की जरूरत पड़ने वाली है

भारत गांवों में रहता है। हालांकि वर्ष 2011 के जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि बहुत तेजी से गांवों के लोग शहर में आ रहे हैं। माना जाता है कि हर एक मिनट पर गांव के 30 लोग शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। शहरों का विकास हो रहा है। शहरों की सीमाएं बढ़ रही हैं। उनकी सरहदों को छू रहे गांव शहर का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल देश की 34 फीसदी आबादी शहरों में रहती है। वर्ष 2041 तक ये आंकड़ा बढ़कर 50 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में भविष्य में बनने वाले स्मार्ट शहरों पर दोहरी जिम्मेदारी होगी कि किस तरह वो भविष्य की बढी आबादी के लिए तैयार है और कैसे आस पास के गांवों को शहरीकरण के लिए सुनियोजित ढंग से समायोजित कर पाते हैं।

भारत जैसे देश में शहरीकरण की रफ्तार यूरोप और चीन जैसे देशों की तुलना में धीमी रही है। चीन का शंघाई शहर वर्ष 1949 में महज 636.18 वर्ग किलोमीटर में फैला था और आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा शहर था। अब ये महानगर 6340.5 वर्ग किलोमीटर में फैल चुका है। इसमें 20 नगर और 10 उपनगरीय इलाके हैं। भारतीय शहरों का फैलाव वर्ष 1991 के बाद तब बढ़ता हुआ लगा जब यहां आर्थिक परिदृश्य बदलने लगा। ये समय की जरूरत थी। नई आर्थिक नीतियों का तकाजा भी। नए ग्रामीण-शहरी इलाकों का उदय होने लगा। शहरों में जमीनें मंहगी और जगह कम थी। लिहाजा विकास के लिए 90 के दशक में शहर की सीमाओं से सटे इलाकों में औद्योगिक से लेकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के अवसर देखे जाने लगे। इस दौड़ में बहुत से शहरी म्युनिसिपल निकायों खुद से सटे गांवों का शहरीकरण कर उनका बेहतर नियोजन किया। कुछ इस चुनौती के सामने लड़खड़ा गए। अब एक नया चरण सामने आने जा रहा है। ये देश में स्मार्ट सिटी का दौर होगा। अब समय का तकाजा ये होगा कि स्मार्टशहर अपनी सीमाओं से जुड़े गांवों को खुद से जोड़कर एक ईकाई के तौर पर कितने स्मार्ट हो पाते हैं। स्मार्ट शहर की नई अवधारणा पर कितने खरे उतरते हैं।

हमारे तमाम बड़े शहरों के फैलाव में पिछले कुछ दशकों में बड़ा बदलाव आया है। मुंबई जैसे शहर के आस पास बसाए गए नवी मुंबई, ठाणे और वसई जैसे नए उपनगरों के बाद वहां ज्यादा फैलाव और शहरीकरण की गुंजाइश नहीं रह गई है। कुछ ऐसा ही हाल पुणे जैसे शहर का भी है। पुणे ने पिछले कुछ दशकों में करीब दो दर्जन गांवों में खुद में समाहित किया लेकिन आज शहर में मिलाए गए इन ग्रामीण-शहरी इलाकों की अपनी मूलभूत समस्याएं हैं। नए इलाके न तो ढंग से शहरी हो पाए और न ही अब ग्रामीण हैं। वहां शहर की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। बेशक प्रस्तावित पुणे स्मार्ट सिटी में 34 नए गांवों को मिलाए जाने की योजना को शहर की नगरपालिका से हरी झंडी मिल चुकी है लेकिन सवाल वही है कि आगे आने वाले समय में ये शहर नए गांवों का सुनियोजित शहरीकरण कैसे कर सकेगा। आप अगर पुणे के फैलाव को देखेंगे तो शायद हैरान रह जाएंगे। वर्ष 1857 में उनका एरिया 7.74 वर्ग किलोमीटर फैला था और 2013 में ये

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। लगभग ढाई दशक से बहुविध विषयों पर लेखन कर रहे हैं। प्रकाशित पुस्तकें: *1857 से लेकर 1947 वे 90 साल, मर्लिन मुलरो-स्वप्न परी, क्रिकेट के चर्चित विवाद* आदि। संप्रति एक राष्ट्रीय दैनिक से जुड़े हैं। ईमेल: sanjayratan@gmail.com

क्षेत्रफल बढ़कर 243.8 वर्ग किलोमीटर तक जा पहुंचा।

स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि वहां के निवासियों को सतत बिजली, पानी की आपूर्ति के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बेहतर परिवहन प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक प्रशासन और बेहतर टाउन प्लानिंग। परिप्रेक्ष्य में स्मार्ट सिटी का मतलब ये भी है कि वो शहर जो अपने निवासियों की जरूरतों और सुविधाओं के बारे में सोचे और उन कसौटियों पर खरा उतरे। वह अपनी व्यवस्थित संरचना के साथ वित्तीय तौर पर संतुलित और स्मार्ट हो। इसलिए देश में हाल में बने कुछ नए शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने अवधारणा इसलिए नाकाम हो गई, क्योंकि वो स्व वित्तीय पोषण के पैमाने पर खरे नहीं उतर सके। पुणे के सामने चुनौती ये है कि अतीत में उसने जिन गांवों को शहर में मिलाया, वहां तक नियोजन को अमली जामा नहीं पहनाया जा पाया। मूलभूत सुविधाओं की भी दरकार बनी हुई है। हैदराबाद में तस्वीर अलग है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 36 गांवों को मिलाने की योजना थी लेकिन न केवल नगर निगम के सदस्यों में ही इस पर सहमति बन पाई और न ही ग्राम पंचायत इसके लिए बहुत इच्छुक हैं। वो अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं। कोल्हापुर इसलिए स्मार्ट सिटी की दौड़ में चूक गया क्योंकि वहां का नगर निगम अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं कर सका। किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए आस पास के ग्रामीण इलाके इसलिए जरूरी हैं क्योंकि बगैर पर्याप्त जगह के अनुमानित जनसंख्या वृद्धि और विकास की चुनौती से नहीं निपटा जा सकता।

ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसपल कारपोरेशन की 36 गांवों को मिलाने की योजना थी लेकिन न केवल म्युनिसपल कारपोरेशन के सदस्यों में इस पर सहमति बन पाई और न ही ग्राम पंचायत इसके लिए बहुत इच्छुक हैं। वो अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं। कोल्हापुर इसलिए स्मार्टसिटी की दौड़ में चूक गया क्योंकि वहां का म्युनिसपल कारपोरेशन अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं कर सका।

हालांकि स्मार्ट सिटी के लिए पहले 20 शहरों की घोषणा अगले साल होने वाली है लेकिन स्मार्ट सिटी के चुनौतीपूर्ण पहलुओं के मद्देनजर दिल्ली देश के उन चुनिंदा शहरों में है, जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए सारे आदर्श तत्व मौजूद लगते हैं। उन्हें कुछ प्रयासों से अगले दो तीन वर्षों में ही संभव भी किया जा सकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अभी से अपनी ओर से दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना को अमलीजामा पहनाने में जुट गया है। उसके अनुसार महानगर में अगले तीन वर्षों में चार सब-स्मार्ट सिटी आकार ले सकती हैं। हालांकि योजना यहां पांच सब स्मार्ट सिटी बनाने की है। महानगर को उसी लिहाज पांच जोन में बांटा गया है।

दिल्ली के गांवों का इस शहर में मिलते जाने का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। ये महानगर कुछ इस तरह बसा है कि इसके अंदर और बाहर दोनों ओर गांव बसे हुए हैं। समय के साथ कुछ गांवों का नियोजन इस तरह से शहर में किया गया कि आज वो राजधानी का सुनियोजित हिस्सा हैं। वर्ष 1908 में जब दिल्ली के भूमि राजस्व विभाग ने शहर और गांवों की हदबंदी की थी तब दिल्ली में 362 गांव थे। उन्हें लाल डोरा भी कहा जाता था। इन्हें लालडोरा कहे जाने की भी कहानी है, चूंकि विभाग ने हदबंदी की माप जोख के लिए लाल डोरे का इस्तेमाल किया था लिहाजा इसे लाल डोरा कहा जाने लगा। वर्ष 1957 में दिल्ली नगर निगम बनने के बाद अब तक करीब 135 गांव शहरी क्षेत्र का हिस्सा बन चुके हैं। उन्हें शहर की प्लानिंग की दृष्टि से विनयमित करने की कोशिश की गई है। करीब 227 गांवों में करीब 89 गांव डीडीए के प्रस्तावित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले हैं। अपवाद हो सकते हैं लेकिन दिल्ली को देखकर लगता है कि यहां काफी हद तक गांवों को नियोजित करने की कोशिश की गई है। बेशक विसंगतियां हैं, समस्याएं भी आ रही हैं।

दिल्ली में फिलहाल आबादी 1.82 करोड़ है, जो अगले कुछ वर्षों में 2.3 करोड़ हो जाएगी। मौजूदा दिल्ली में ही पर्याप्त जगह निकालने के लिए डीडीए ने महानगर को पांच जोन में बांटा है। इनमें मौजूदा कालोनियों, इलाकों के साथ गांवों और बाहरी इलाकों को भी जोनों में शामिल किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को उम्मीद है कि उसकी नई भूमि संचयन या भूमि एकत्रीकरण नीति से 20 हजार से 25 हजार हेक्टेयर तक जमीन हासिल हो सकेगी, जिसके जरिए वो शहर की तस्वीर बदलने की योजना को साकार कर पाएगा। इसके तहत इच्छुक किसान और भूमि स्वामी अपनी जमीन विकास शुल्क के साथ डीडीए को दे सकेंगे। डीडीए इन्हें विकास के लिए स्टेट डेवलपर्स को देगा। विकसित किए जाने के बाद इसका 60 फीसदी तक हिस्सा उसके मालिक को वापस दे दिया जाएगा। बाकि विकसित एरिया डीडीए को मिलेगा।

एक बार डीडीए द्वारा विकास हो जाने के बाद ये संपत्ति न केवल नियमित हो जाएगी बल्कि इसकी कीमत में काफी बड़ा इजाफा होगा। ये भूमि स्वामी के ऊपर होगा कि वो विकसित संपत्ति का उपयोग किस तरह करता है, वो इसे बेच भी सकता है या फिर मास्टर प्लान में दी गई योजना के अनुसार इसका उपयोग भी कर सकेगा। हालांकि इस योजना को लेकर किंतु परंतु वाली स्थिति है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि कोई भूमि स्वामी अपनी जमीन का विकास शुल्क क्यों देगा, उससे उसे क्या फायदा मिलेगा। डीडीए मानता है कि एक बार इस पर आधिकारिक संस्था द्वारा विकसित किए जाने की मुहर लगने के बाद इस जमीन के दामों में जबरदस्त उछाल आएगा। खरीदार इसे मुंहमांगी कीमत पर लेना चाहेंगे। वहीं डीडीए को ये फायदा होगा कि वो इन जमीनों को हासिल करने के बाद वांछित तरीके से शहर में स्मार्ट सिटी की योजनाओं, नियोजन और सुविधाओं पर अमल कर सकेगा। हालांकि ये योजना अभी एकदम शुरुआती चरण में है। अगर ऐसा हो गया तो देश की राजधानी अन्य शहरों के लिए मिसाल और मॉडल बन सकेगी।

1957 में दिल्ली म्युनिसपल कारपोरेशन बनने के बाद अब तक करीब 135 गांव शहरी क्षेत्र का हिस्सा बन चुके हैं। उन्हें शहर की प्लानिंग की दृष्टि से रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। करीब 227 गांवों में करीब 89 गांव डीडीए की प्रस्तावित परियोजना का हिस्सा बनने वाले हैं। दिल्ली को देखकर लगता है कि यहां काफी हद तक गांवों को नियोजित करने की कोशिश की गई है।

इसी तरह कोलकाता को लेकर माना जा रहा है कि अगले दस वर्षों में वहां शहरी

(शेषांश पृष्ठ 37 पर)

पर्यावरण भी रहे स्मार्ट

प्रभांसु ओझा

शहर तो स्मार्ट बन जाएंगे मगर वहां रहने वाले लोगों को कैसे स्मार्ट और स्किल्ड बनाया जाएगा क्योंकि कोई भी शहर स्मार्ट तो वहां रहने वाले नागरिकों से ही बनता है। क्या स्मार्ट शहरों की तकनीकी पर्यावरण की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम होगी यह एक बड़ा सवाल है और इसका सीधा सा जवाब यह है कि तकनीकी कितनी भी सक्षम हो मगर लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरुक रहना होगा तभी शहर असली मायनों में स्मार्ट होगा

शहर शब्द सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी सपनों भरी दुनिया के ख्याल तैरने लगते हैं जहां ऊंचे-ऊंचे महल हैं, बड़े-बड़े फ्लाईओवर्स हैं, जहां तेज गति से भागती गाड़ियां हैं, जहां घर से थोड़ी दूर पर स्कूल और अस्पताल है, जहां हमारे एक फोन कॉल से सेकंडों में पुलिस के लोग हमारी सहायता को उपलब्ध होते हैं और इन सब के बीच हौसलों के पंख लगाए जिंदगी उड़ रही होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां दिन और रात के फासले खत्म हो जाते हैं। ऐसे में अगर बात स्मार्ट शहर की हो तो कहना ही क्या। जोकि सूचना और संचार तकनीकी पर आधारित होगा और डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार करेगा। आम जनमानस शहर को सुविधाओं का संसार ही मानता है हालत भले ही इससे उलट हों। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि शहर की हवाओं में खुशबू की बजाए जहर घुलता जा रहा है। शहर का बिना फिल्टर किया सामान्य जल पीने से हम तमाम बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। हर दिन शहर पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है मगर संसाधन सीमित ही हैं।

एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2050 तक दुनिया की 75 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करेगी जिससे यातायात व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं पर जबर्दस्त दबाव होगा। किसी भी शहर की रूपरेखा में आठ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। पहला है सरकारी प्रशासन, दूसरा ऊर्जा-पानी, बिल्डिंग, पर्यटन, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा और अंतिम सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु हैं पर्यावरण। ये ऐसे बिंदु हैं जो एक शहर में होने चाहिए। ऐसे में बिना किसी समुचित योजना के इन सुविधाओं की कल्पना भी शहरों में नहीं की जा सकती।

स्मार्ट शहर एक ऐसी ही कल्पना का हिस्सा हैं जो तकनीक के माध्यम से शहर को तमाम सुविधाओं से लैस बनाएंगे और शहरों की जिंदगी को आसान करेंगे। भविष्य के स्मार्ट शहर में बिजली के ग्रिड से लेकर सीवर पाइप, सड़कें, कारें और इमारतें हर चीज एक एक नेटवर्क से जुड़ी होगी। इमारत अपने आप बिजली बंद करेगी, स्वचालित कारें खुद अपने लिए पार्किंग ढूंढेंगी और यहां तक कि कूड़ादान भी स्मार्ट होगा। पिछले साल बार्सिलोना शहर के एक प्रमुख अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि आने वाले स्मार्ट शहर भविष्य में कई देशों से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। भारत में स्मार्ट सिटी बनाने की बात प्रधानमंत्री चुनाव प्रचारों के वक्त से ही करते आए हैं। सरकार ने बजट में इसके लिए 7,060 करोड़ रूपये का प्रावधान भी किया है। 40 लाख तक की आबादी वाले शहर स्मार्ट सिटी के लिए पहली पसंद हैं, जबकि इससे बड़े शहरों के साथ सैटेलाइट शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना है।

स्मार्ट सिटी कैसी हो, इसका मसौदा केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने सार्वजनिक किया है। इस संबंध में जो सबसे बड़ी चिंता है वह है पर्यावरण की। स्मार्ट शहर पर्यावरण की दृष्टि से कितने अनुकूल होंगे? उनमें स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल की की क्या

लेखक युवा पत्रकार हैं। पर्यावरण संबंधी विषयों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहते हैं। ईमेल: prabhansukmc@gmail.com

व्यवस्था होगी, इन शहरों का कचरा निस्तारण सिस्टम कैसा होगा, हर दिन बेतहाशा गति से बढ़ते प्रदूषण पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, इन शहरों के भवन निर्माण की संरचना क्या होगी? जिन बातों का जिक्र शहरी विकास मंत्री ने स्मार्ट शहरों की रूपरेखा के अंतर्गत किया है अगर वास्तविक रूप में उन्हें लागू किया जाता है तो शहर निश्चित रूप से पर्यावरण के अनुकूल होगा ऐसी अपेक्षा है। शहरों में जल की बर्बादी को कैसे रोका जाए, जल निकासी की ऐसी व्यवस्था हो जिससे प्रदूषण न के बराबर हो, वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को न्यूनतम किया जाए, ऊर्जा चुनौती भारत में लगातार बढ़ती जा रही है परिणामस्वरूप ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है इसके लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए तो ऐसा शहर निश्चित रूप से आदर्श शहर होगा। हमें वैश्विक स्तर पर ऐसे स्मार्ट शहरों से सीख लेने की आवश्यकता है जो पर्यावरणीय मानकों की दृष्टि से एक आदर्श स्थापित करते हैं। इसलिए एक नजर इस पर भी डालना जरूरी है की वैश्विक स्तर स्मार्ट शहरों की क्या स्थिति है और वहां इन शहरों में क्या सुविधाएं हैं और इनका निर्माण कैसे किया जा रहा है।

जिन बातों का जिक्र शहरी विकास मंत्री ने स्मार्ट शहरों की रूपरेखा के अंतर्गत किया है अगर वास्तविक रूप में उन्हें लागू किया जाता है तो शहर निश्चित रूप से पर्यावरण के अनुकूल होगा ऐसी अपेक्षा है। हमें वैश्विक स्तर पर ऐसे स्मार्ट शहरों से सीख लेने की आवश्यकता है जो पर्यावरणीय मानकों की दृष्टि से एक आदर्श स्थापित करते हैं।

पर्यावरण अनुकूल स्मार्ट शहरों में प्रमुख शहर है संयुक्त अरब अमीरात का मास्दार शहर। ये शहर अबू धाबी के रेगिस्तान के बीचों-बीच बसाया जा रहा है। इसे धरती पर सबसे ज्यादा संवहनीय या सस्टेनेबल और दीर्घकालिक शहर के रूप में बसाया जा रहा है। शहर में सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा के संयंत्र लगे हैं जिससे प्रदूषण कम से कम हो। शहर को गाड़ियों से मुक्त रखा गया है। यहां कोई कार नजर नहीं आएगी बल्कि आवाजाही के लिए बिजली से चलने वाली बिना ड्राइवर की गाड़ियां बनाई जा रही हैं। बस के रूटों को, कचरा उठाने की प्रक्रिया को सेंसर की मदद से और सक्षम किया जा रहा है। इसके अलावा परिवहन के लिए बिना सीधा संपर्क के पेमेंट व्यवस्था तैयार की जा रही है।

ऐसे शहर निश्चित रूप से पर्यावरण अनुकूल हैं और सतत व संपोषणीय विकास को प्रोत्साहित करते हैं। हमारी स्मार्टनेस इसी में है की हम किस तरह से जीवन और रहन सहन के ऐसे तरीके इजाद कर लेते हैं जो प्रकृति के अनुकूल है. भारत में स्मार्ट शहरों के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कैसे बसे बसाए शहरों को स्मार्ट बनाया जाए? इसकी अपेक्षा उन शहरों को पर्यावरण के अनुकूल अधिक आसानी से बनाया जा सकता है जो पूर्णतया: नए बसाए जाएंगे। पहले से बसे बसाए शहर जिन्हें स्मार्ट शहरों की सूची में जगह मिली है वहां किसी भी तरह के नए सिस्टम को स्थापित करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

कैसे हों हमारे घर: शहरों में अवैज्ञानिक तरीके से घरों का निर्माण प्रदूषण का प्रमुख कारण हैं ऐसे स्मार्ट शहरों से यह उम्मीद किया जाना लाजिमी है की यहां घर पर्यावरणीय मानकों के अनुकूल होंगे। अब हरित पर्यावरण की रक्षा के लिए हरित अर्थव्यवस्था, हरित न्यायालय, हरित राजनीति जैसे मुद्दों के साथ ही एक ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा दिए जाने की बात की जा रही है जो पर्यावरण अनुकूल हो। स्मार्ट शहरों के भवन निर्माण के साथ जो प्रमुख बात जुड़ी हुई है वह है इनका पर्यावरण अनुकूल होना। ऐसा घर जिसके उपकरण सौर और वायु ऊर्जा से चलें। जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कंपोस्टिंग सिस्टम हो।

स्मार्ट होम्स यानी ऐसे घर जहां अधिकांश चीजें तकनीक चालित होती हैं। इसमें वातानुकूलन, प्रकाश व्यवस्था, निगरानी, सुरक्षा, दरवाजों व खिड़कियों आदि पर आवागमन आदि तमाम चीजें तकनीकी संचालित होती हैं। एक अच्छी गृह स्वचालन प्रणाली में कई तरह की सुविधाओं का मिश्रण होता है जैसे बगीचे में आवश्यकता अनुसार पानी पहुंचाना या पानी गर्म करने के साधन का काम पूरा होते ही स्वत: बंद (स्विच ऑफ) हो जाना या फिर कमरे का तापमान परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार स्थिर रखना आते हैं। होम ऑटोमेशन सिस्टम के द्वारा पूरे घर की विद्युत व्यवस्था पर भी नियंत्रण किया जाता है। इनमें टच स्क्रीन एलसीडी मॉनीटर लगे होते हैं जिनपर पूरी इमारत तक को देखा जा सकता है और एक स्थान से ही विद्युत उपकरणों पर नियंत्रण रख सकते हैं। गति को पहचानने वाले मोशन सेंसर के माध्यम से कमरे में किसी की उपस्थिति होने या न होने पर प्रकाश स्वयमेव खुल या बंद हो जाएगा। भवन निर्माण इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ष के आखिर तक दुनिया के 11 फीसदी घर स्मार्ट की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, अमेरिका में अब ही करीब 17 फीसदी घर स्मार्ट होम की श्रेणी में आते हैं लेकिन वैश्विक तौर पर इसका औसत पांच फीसदी के आसपास ही हैं। कुल मिलाकर स्मार्ट होम्स एक ऐसी संकल्पना है जो ग्रीन होम की ही संकल्पना को साकार करेंगे।

भारत में स्मार्ट शहरों के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कैसे बसे बसाए शहरों को स्मार्ट बनाया जाए? इसकी अपेक्षा उन शहरों को पर्यावरण के अनुकूल अधिक आसानी से बनाया जा सकता है जो पूर्णतया: नए बसाए जाएंगे। पहले से बसे बसाए शहर जिन्हें स्मार्ट शहरों की सूची में जगह मिली है वहां किसी भी तरह के नए सिस्टम को स्थापित करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

स्मार्ट शहरों के निर्माण के समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है कि स्मार्ट होम्स के तमाम मानकों का पालन किया जाए तभी शहर असली मायनों में स्मार्ट होंगे। सामान्य घरों में ऊर्जा दुरुपयोग से हम सब वाकिफ हैं। स्मार्ट घरों ने ऊर्जा बचत की परिकल्पना को साकार किया है। ऐसे घर जहां ऊर्जा बचत के लिए अक्षय ऊर्जा और स्मार्ट होम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम हो, जल का बेहतर इस्तेमाल किए जाने की तकनीकें हों निश्चित रूप से किसी वरदान से कम नहीं होंगे। कुछ स्मार्ट प्रोडक्ट्स का भी उल्लेख जरूरी है जो इन घरों को स्मार्ट बनाएंगे। इनमें प्रमुख हैं–आइग्रिल, स्मार्ट बेबी मॉनीटर, स्मार्ट बेबी मॉनीटर, थर्मोस्टेट, स्काइबेल, प्लग मोशन सेंसिंग तकनीक, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स।

हमारे घर बनाने का तरीका और निश्चित रूप से इसका पर्यावरण से सीधा संबंध है। उस

समय से जबकि मानव गुफाओं मे रहता था और अब जबकि आलीशान कंकरीट के बड़े बड़े महलों मे पहुंच गया। इस क्रम मे उसने भले ही कितना भी भौतिक और औद्योगिक विकास किया हो परंतु इन बड़े-बड़े भवनों के निर्माण से अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की क्षति हुई है तो वह है हमारा पर्यावरण। क्या स्मार्ट शहर यह क्षतिपूर्ति कर पाएंगे? कुछ दिनों पहले आई एक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है की भारत में ग्रीन रेटेड बिल्डिंग्स, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा जारी अपने सरकारी रेटिंग प्रणाली के न्यूनतम मानक स्तर को भी पूरा नहीं कर पा रही हैं। भारत ने 2007 में भवनों के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के रूप में ग्रीन मूल्यांकन इंटीग्रेटेड हैबिटेट एसेसमेंट (गृहा) को अपनाया। भारत ने भवनों के लिए ग्रीन रेटिंग की यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका की एक निजी संस्था यूएसजेबीसी द्वारा भारत में भवनों की ग्रीन रेटिंग के लिए शुरू की गई एक निजी पहल का परिणाम थी। भारत मे कुल ग्रीन रेटेड भवन निर्मित क्षेत्र भारत के कुल भवन निर्मित क्षेत्रों का महज 3 प्रतिशत ही है। रिपोर्ट के अनुसार इन इमारतों के निर्माण तथा उनके संचालन मे 30-50 फीसदी ऊर्जा और 20-30 फीसदी पानी बचाने का पैमाना तो महज एक स्वप्न बनकर रह गया है और मूल्यांकन व्यवस्था में तय किए गए विभिन सिल्वर गोल्ड तथा डायमंड स्टार के पैमानों में ज्यादातर भवन न्यूनतम सिल्वर स्टार के लायक भी नहीं हैं।

अगर हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय की ऐतिहासिक भवन संरचना को देखें तो यह प्रकृति के बिल्कुल करीब है जबकि उस समय तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी। हमारे शहरों में आए दिन भवन गिरने से होने वाली मौतों, भवनों का भूकंपरोधी ना होना, तथा ज्यादातर भवन ऐसे ही हैं जहां पर दिन और रात का पता ही नहीं चलता है। बहुत ही कम घरों मे खिड़कियां देखने को मिलती हैं। हम नदियों और पहाड़ों की छाती चीरकर अगर ऐसे ही बड़े-बड़े भवन बनाते रहे तो एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अत: आवश्यकता इस बात की है कि अब हरित भवनों के निर्माण को अधिक-से-अधिक प्रोत्साहित किया जाए तथा बेतहाशा भवन के ऊपर भवन बनाने की प्रवृत्ति को कम किया जाए। स्मार्ट शहरों की जो वर्तमान रूपरेखा है और जो वैश्विक आंकडे हैं वे इस बात का संतोष देते हैं कि इन शहरों का निर्माण पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएगा बल्कि कई रूपों में समृद्ध करेगा।

स्मार्ट घरों ने ऊर्जा बचत की परिकल्पना को साकार किया है। ऐसे घर जहां ऊर्जा बचत के लिए अक्षय ऊर्जा और स्मार्ट होम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम हो, जल का बेहतर इस्तेमाल किए जाने की तकनीकें हों निश्चित रूप से किसी वरदान से कम नहीं होंगे।

स्मार्ट शहर बनाम स्मार्ट गांव: गांवों में ऐसे घरों की संख्या करीब 11 करोड़ 50 लाख हैं, जहां शौचालय नहीं हैं। लोग खुले में शौच को जाने के लिए मजबूर हैं। इन घरों में शौचालय की सुविधा देने का खर्च अनुमानत: 22 खरब से 26 खरब रुपये है। ऐसे में यह सवाल बरबस उठ जाता है कि जब हमारे गांवों की स्थिति इतनी दयनीय है तो भला स्मार्ट शहरों की कल्पना कैसे की जा सकती है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि स्मार्ट शहरों की बजाए स्मार्ट गांवों की भी बात की जाए। इस दिशा में सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना जरूरी है। सोचना इस दिशा में भी है की शहर तो स्मार्ट बन जाएंगे मगर वहां रहने वाले लोगों को कैसे स्मार्ट और स्किल्ड बनाया जाएगा क्योंकि कोई भी शहर स्मार्ट तो वहां रहने वाले नागरिकों से ही बनता है। क्या स्मार्ट शहरों की तकनीकी पर्यावरण की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम होगी यह एक बड़ा सवाल है और इसका सीधा सा जवाब यह है कि तकनीकी कितनी भी सक्षम हो मगर लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरुक रहना होगा तभी शहर असली मायनों में स्मार्ट होगा। ❑

(पृष्ठ 34 का शेषांश)

फैलाव की दर सबसे ज्यादा होने वाली है। इसके लिए पश्चिम बंगाल में योजनाएं बनने लगी हैं। आस पास के गांवों को शहर में मिलाने की बातें हो रही हैं। फिलहाल कोलकाता का फैलाव 158 वर्ग किलोमीटर में है और वर्ष 2025 तक इसका फैलाव 1851 वर्ग किलोमीटर होने की उम्मीद है। यानि 901 फीसदी बढोतरी। बेंगलुरु उन शहरों में है, जहां अच्छे तरीके से ग्रामीण इलाकों का शहरीकरण किया गया और शहर को विस्तार मिला। वहां बनी इलैक्ट्रॉनिक सिटी गांवों की जमीनों के सटीक उपयोग का ही नतीजा थी। इस शहर में अब विस्तार की ज्यादा संभावनाएं बेशक नहीं दीखती हों तब भी अनुमान है कि इसका मौजूदा 99 वर्ग किलोमीटर का एरिया और बढ़कर 696 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी को किस कदर गांवों की जरूरत पड़ने वाली है।

अहमदाबाद, कोच्चि, कोयम्बटूर, कोटा, रेवाड़ी कुछ ऐसे शहर हैं, जहां पिछले दो दशकों में बहुत तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ तो आबादी भी बढ़ी। ऐसे में शहरी निकायों पर नियोजन पर भी उतना दबाव बढ़ा। भारतीय शहर पहले ही आबादी और अनियंत्रित विकास से लबालब हो रहे हैं। दिल्ली से सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाकों को ही देख लीजिए। जब तीन दशक पहले एनसीआर इलाके में नए शहरों की नींव पड़ रही थी, तब उन्हें उस समय के लिहाज से स्मार्ट सिटी की अवधारणा से ही तैयार किया गया था। अगर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे इलाके नहीं होते तो दिल्ली का न जाने क्या हाल होता। लेकिन एनसीआर के उस जमाने के ये स्मार्ट शहर भी फैलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं।

वर्ष 1981 में जब गुडगांव को स्मार्टसिटी बनाने की योजना शुरू हुई तब यहां की आबादी महज एक लाख थी और 2011 में ये 15 लाख से ऊपर पहुंच चुकी थी। जैसे जैसे यहां आबादी और सुविधाओं का दबाव बढ़ रहा है, आसपास के गांवों को भी इसमें समेटा जा रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति नोएडा की है। पिछले दो दशकों में यहां आबादी बीस गुना बढ़ चुकी है। ग्रेटर नोएडा अपेक्षाकृत नया है। उसका फैलाव 50 वर्ग किलोमीटर का है लेकिन अगले दस वर्षों में इसमें 140 फीसदी विस्तार होने की उम्मीद है। इसके लिए अभी से ये शहर आसपास के ग्रामीण इलाकों तक अपनी शहरीकरण योजनाएं बनाने में जुट गया है।

हालांकि इन स्मार्ट सिटी के बनने और आकार लेने के साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी होगा कि जितने बड़े पैमाने पर तमाम राज्यों से सैकड़ों-हजारों लोग दिल्ली और एनसीआर में पहुंचते हैं, उसका बोझ ये स्मार्टसिटी भी कब तक बर्दाश्त कर पाएंगी और आने वाले वर्षों के लिए क्या वो उसके तैयार हैं या हमें स्मार्टसिटी तैयार करने के साथ नए प्रवासियों को लेकर भी कुछ नियम तय करने होंगे।❑

Mc Graw Hill Education

सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा हेतु आधारभूत मार्गदर्शिका

₹ 225/-

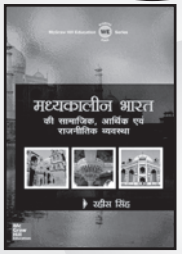

ISBN: 9789339222727

₹ 310/-

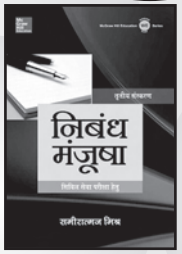

ISBN: 9789339217730

₹ 165/-

ISBN: 9789339219093

₹ 225/-

ISBN: 9789339219079

₹ 400/-

ISBN: 9781259003851

₹ 340/-

ISBN: 9780070221758

₹ 215/-

ISBN: 9780070144842

₹ 425/-

ISBN: 9789339214128

₹ 695/-

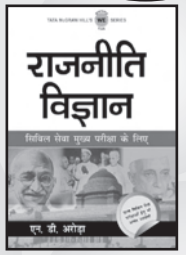

ISBN: 9780070144866

₹ 450/-

ISBN: 9780070264205

अन्य उपयोगी पुस्तकें

ISBN	AUTHOR	TITLE	PRICE (₹)
9789339222710	रमेश सिंह	भारतीय अर्थव्यवस्था, सप्तम संस्करण	550.00
9780070144859	डी.आर. खुल्लर	भूगोल सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए	715.00
9780070660328	मोहम्मद तारिक	आधुनिक भारत का इतिहास	240.00
9789351341864	पी.एल. गौतम	प्राचीन भारत का इतिहास	445.00
9789339204204	माजिद हुसैन व रमेश सिंह	भारत का भूगोल, पंचम संस्करण	525.00
9789351342663	एम. लक्ष्मीकांत	भारत की राज्यव्यवस्था, चतुर्थ संस्करण	490.00
9780071329477	एम. लक्ष्मीकांत	भारतीय शासन	395.00
9789339217754	माजिद हुसैन	भारत एवं विश्व का भूगोल, द्वितीय संस्करण	450.00

Mc Graw Hill Education

मैक्ग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

बी-4, सैक्टर-63, नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201 301

उत्तर

दिल्ली/हरियाणा/पंजाब/चंडीगढ़/जम्मू-कश्मीर/हिमाचल प्रदेश/राजस्थान/मध्य प्रदेश: आशीष पराशर (ashish.prashar@mheducation.com)
हरियाणा/पंजाब/चंडीगढ़/जम्मू-कश्मीर/हिमाचल प्रदेश/दिल्ली एन.सी.आर.: जनेन्द्र अत्री (09599295604), राजीव शर्मा (07042799344)
दिल्ली/राजस्थान: आनन्द सिंह (09599196777), दिलीप चौरसिया (09560072125)
उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड: जगदीश ध्यानी (07042799338), जितेन्द्र मिश्रा (07042799339); **मध्य प्रदेश:** रोहित शैल (07042799341)

पूर्व

उत्तर-पूर्व/ओडिशा: अनुप कुमार कुंडू (09831498906)
बिहार/झारखंड: रणविजय कुमार (07042799348), नितेश कुमार निशु (09560779393)

पश्चिम

महाराष्ट्र/गोवा/गुजरात/छत्तीसगढ़: जूनियस रॉड्रिक्स (09833054319); **महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़:** सौरभ कानूनगो (07718812361)
गुजरात: नरेन महतो (07718812363)

*Prices are subject to change without prior notice.

SHIPPING FREE Above ₹ 500/-

संपर्क करें: @ /McGrawHillEducationIN /MHEducationIN
टोल फ्री नं०: 1800 103 5875 | ई-मेल: reachus@mheducation.com | खरीदें: @ www.mheducation.co.in

YH-147/2015

सुरक्षित एवं आपदा मुक्त शहर

आर के भसीन

संवहनीय व्यवस्था तभी संभव है, जब वस्तुओं और एजेंसियों के बीच ऐसे भौतिक एवं आभासी जोड़ तैयार किए जाएं, जो पहले कभी नहीं थे। प्रौद्योगिकी को भूमिका निभानी होगी और वह हमारे पारितंत्र से मिली समूची सूचना का उपभोग करने का हमारा तरीका ही बदल देगी। इससे पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार की बुराई दूर करने में मदद मिलेगी, जिससे कारोबार तथा आम नागरिक के जीवन की गुणवत्ता भी सुधारेगी। यह चरणबद्ध प्रक्रिया होगी, जो स्मार्ट सिटी अभियान के लिए हाल ही में कोष के आवंटन के साथ आरंभ हो चुकी है

स्मार्ट सिटी पर प्रधानमंत्री का तभी से मुखर जोर रहा है, जब से उन्होंने केंद्र सरकार की कमान संभाली है। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी सरकार 100 स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया आरंभ करेगी, जिसके लिए इस वर्ष के बजट प्रस्ताव में 7060 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पहले से मौजूद मझोले आकार के कुछ शहरों को चिह्नित करने का कार्य नेशनल सस्टेनेबल एंड स्मार्ट सिटी मिशन (एनएसएचएससीएम) द्वारा होगा, जो इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगा।

हम जानते हैं कि शहरीकरण जारी रहेगा। प्रत्येक देश के लिए शहर विकास के उत्प्रेरक का काम करते हैं और भारत भी अलग नहीं है। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार लगभग 31 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है और इसके 40 प्रतिशत तक जाने की अपेक्षा है तथा अगले 15 वर्ष में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान लगभग 75 प्रतिशत रहेगा। यदि वैश्विक अनुभव की बात की जाए तो किसी भी देश में 30 प्रतिशत के बाद शहरीकरण अधिक तेजी से होता है। इस प्रकार भारत उस मोड़ पर खड़ा है, जहां शहरों में कमी नहीं आएगी।

आरेख 1: बढ़ता शहरीकरण

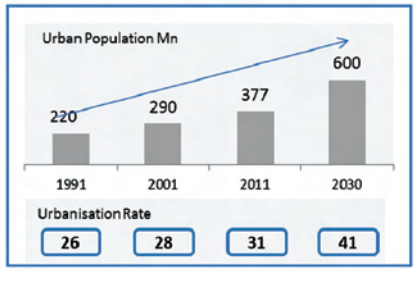

इसलिए विकास की संभावना को बढ़ाने तथा गिरावट को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे (सभी प्रकार के) में निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है। आवश्यकताओं एवं भावी परिदृश्य को देखते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 100 स्मार्ट शहर विकसित करने का कार्य आरंभ किया है।

क्या है स्मार्ट सिटी?

स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को देखते हुए इसे कई प्रकार से परिभाषित किया गया है। इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं है, लेकिन कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं:

अमेरिकी वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना कार्यालय के अनुसार स्मार्ट सिटी वह है, जो अपने नाजुक बुनियादी ढांचे की स्थिति पर नजर रखे और उसका एकीकरण करे, अपने संसाधनों का सबसे अधिक इस्तेमाल करे, देखरेख की गतिविधियों की योजना बनाए और सुरक्षा के पहलू पर नजर रखे तथा साथ में सेवाओं में अधिक से अधिक वृद्धि करे। ब्रिटेन में कारोबारी नवाचार एवं कौशल विभाग कहता है कि स्मार्ट सिटी 'वे प्रक्रिया अथवा कदम हैं, जिनके माध्यम से शहर रहने के अधिक योग्य और लचीले बनते हैं तथा इस प्रकार नई चुनौतियों पर शीघ्र प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार स्मार्ट सिटी में

लेखक मूल रूप से बैंकर हैं, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव है। मार्च 1985 में कार्मिक अधिकारी के रूप में बैंक में आने से पहले उन्होंने लगभग 15 वर्ष तक विनिर्माण एवं प्रकाशन उद्योगों में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया था। उन्होंने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रमुख (मानव संसाधन विकास) के पद पर कार्य किया और 2009 में सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद उन्होंने प्रख्यात राष्ट्रीय संगठनों के साथ संयुक्त निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में कार्य किया, जहां वह साइबर सुरक्षा समेत आंतरिक सुरक्षा, बौद्धिक संपदा, विधि, भंडारण, बैंकिंग और वित्त एवं बीमा विषयक परिषदों में रहे। फिलहाल वह उद्योग, व्यापार एवं सेवा महासंघ में महासचिव का पद संभाल रहे हैं। ईमेल: sg@federationits.in

प्रत्येक नागरिक को सभी सार्वजनिक एवं निजी सेवाओं का प्रयोग अपने लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना चाहिए।'

क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्मार्ट सिटी को मोटे तौर पर मौजूद पारंपरिक क्षमताओं का लाभ उठाना चाहिए तथा जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक क्षमताओं, सतत विकास एवं संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए।

रूपरेखा एवं प्रमुख विशेषताएं

शहरी विकास मंत्रालय के व्यापक दिशानिर्देश के अंतर्गत तीन प्रमुख क्षमताओं वाले एकीकृत खाके को क्रियान्वयन का मॉडल कहा जा सकता है। इसमें उन प्रमुख घटकों पर प्रकाश डाला गया है, जो बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने वाले घटक के साथ स्मार्ट सिटी को परिभाषित करते हैं और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

स्मार्ट सिटी का पारितंत्र सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच व्यापक साझेदारी (पीपीपी) है। नगर योजनाकार एवं विकासकर्ता, गैर सरकारी संगठन, आईटी प्रणाली का एकीकरण करने वाले, सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ता, ऊर्जा एवं जनोपयोगी सेवा प्रदाता, ऑटोमोटिव उद्योग एवं मोबाइल प्रौद्योगिकी, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, मशीन टु मशीन तथा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के लिए के लिए तकनीकी प्रदाता, सभी को समुदाय के साथ मिलकर भूमिका निभानी होती है।

शहरों को सुरक्षित एवं आपदा मुक्त रखने का बिंदु कुछ हद तक जीवन की निरंतरता तथा गुणवत्ता में ही आ जाता है। कुछ संभावित तरीकों पर नजर डालते हैं, जिनसे शहर (क) आपदा मुक्त एवं (ख) सुरक्षित रहेंगे।

(क) जन संरक्षा एवं सुरक्षा: जनता की संरक्षा एवं सुरक्षा नगर प्रशासकों के लिए सर्वोपरि हो गई है। अपराध, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना अथवा आतंकवाद से सुरक्षा इसके दायरे में आते हैं। संरक्षा केवल सड़क पर हिंसा तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि इसमें वित्तीय अपराध, साइबर अपराध, सूचना की चोरी आदि भी शामिल हो गई हैं। टेली सर्विलांस की भूमिका यहीं पर विश्वसनीय हो जाती है और समयोचित संचार क्षमताओं के साथ मिलकर यह आपात स्थिति के समय कार्रवाई करने में सहायता कर सकती है। खुफिया सूचना

आरेख 2: समेकित ढांचा

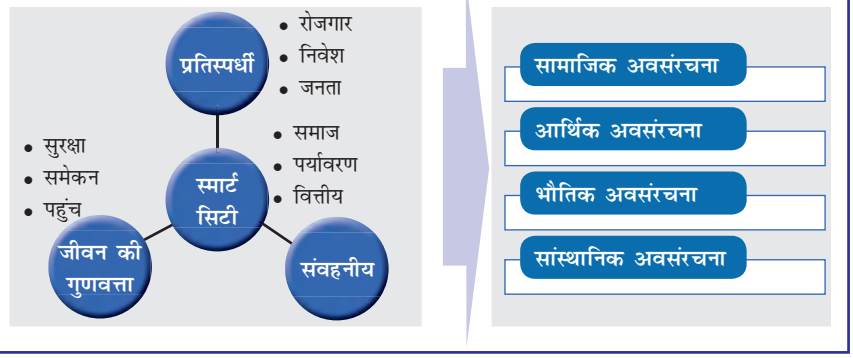

एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने से लेकर एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने, किसी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया दलों के साथ संपर्क सुनिश्चित करने के लिए टेली सर्विलांस प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने आदि सभी से नागरिकों एवं बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का वातावरण बनता है।

सुरक्षित एवं संरक्षित शहर के लिए आवश्यक कुछ प्रणालियां एवं उपाय इस प्रकार हैं:

- **टेली सर्विलांस:** प्रणालियों का चौबीसों घंटे उपलब्ध रहना और इतना विश्वसनीय होना कि आपात स्थिति में वह परिचालन नियंत्रण केंद्रों से दिशा निर्देश प्राप्त कर लेंगी, महत्वपूर्ण है। सर्विलांस अर्थात निगरानी छोटे-मोटे अपराधों को रोकती है और खुफिया जानकारी का अच्छा स्रोत होती है। इस सूचना अथवा दृश्यों को किसी भी स्थान से किसी भी स्क्रीन पर देख पाना भी महत्वपूर्ण है, चाहे स्मार्टफोन के जरिए हो या लैपटॉप अथवा पुलिस क्रूजर टर्मिनल के जरिए हो।
- **सूचना की गोपनीयता (डेटा इंटेग्रिटी):** उपकरणों में कूटलेखन की सुविधाएं डिजाइन करने और डालने से यह सुनिश्चित होता है कि वे आवश्यक नियंत्रण केंद्र से ही संचार कर सकें और यह संपर्क प्रमाणित किया जा सके। किंतु गोपनीयता का अर्थ होगा कि सूचना को कूट भाषा में तैयार किया जाए ताकि उसे असुरक्षित मार्गों से भी भेजा सके। प्रमाणन, हस्ताक्षर एवं कूट लेखन के लिए डिजिटल प्रमाण-पत्रों का उपयोग भी किया जा सकता है। अनुसंधान समुदाय में वर्तमान में अल्गोरिद्म (कलन विधि) उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग सूचना को साझा करते समय गोपनीयता बनाए रखने में किया जा सकता है।
- **सहयोगपूर्ण प्रतिक्रिया के प्रयास:** ऐसा बुनियादी ढांचा रखना आवश्यक है, जो संगठनों को किसी प्रणाली से आ रही सूचना के आधार पर किसी अन्य प्रणाली में कार्य करने की क्षमता दे - उदाहरण के लिए यदि कोई प्रणाली संकेत देती है कि वाहन चुराया गया है तो उसे समीप के कैमरा को स्वत: ही निर्देश देना चाहिए कि वह चालक का वीडियो रिकॉर्ड कर ले। सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों से सामूहिक कार्रवाई होती है - इसी मामले में जब वाहन की पहचान हो जाती है तो समीप के सभी पुलिस अधिकारियों के पास चेतावनी पहुंचनी चाहिए, जिसके बाद वे अपनी साझी सूचना के आधार पर एक साथ कार्य करें। अथवा जब कोई नागरिक एंबुलेंस सेवा चाहता है तो सबसे निकटवर्ती अस्पताल तक के सभी ट्रैफिक सिग्नलों को सूचना मिल जानी चाहिए ताकि वे हरे हो जाएं।

(ख) आपदा मुक्त: स्मार्ट सिटी केवल आराम पहुंचाने हेतु नहीं हैं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम से कम करने के लिए भी हैं। इसके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण शहरी नियोजन तथा ऐसी इमारतों के निर्माण की आवश्यकता है, जो प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला कर सकें। इसके अतिरिक्त शहरों को ऊर्जा दक्षता के नए साधन, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था एवं हवा, पानी तथा मिट्टी के शोधन की प्रणाली विकसित करनी होंगी ताकि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम हो सके। सबका ध्यान रहने की मॉड्यूलर एवं स्वायत्त इकाइयों की ओर चला जाएगा, जिनमें वे सभी

सुविधाएं होंगी, जिनकी आवश्यकता किसी व्यक्ति को कई हफ्तों तक रहने के दौरान पड़ सकती है। पुनरुद्धार के उपकरण एवं 3डी प्रिंटिंग जैसे नए आविष्कार इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

स्मार्ट सिटी को आपदा मुक्त बनाने वाले कुछ सरल उपाय इस प्रकार हो सकते हैं:

- **चौबीसों घंटे संपर्क सुनिश्चित करना:** आपात स्थितियों में प्रौद्योगिकी सभी को जोड़ने का कार्य कर सकती है। आपदा से बचाव हेतु ऑनलाइन समुदाय तैयार किए जा सकते हैं और किसी विशेष आपदा की स्थिति में उनसे संपर्क करने की जानकारी दी जा सकती है। उदाहरण के लिए गूगल ने अपना प्रोजेक्ट लून उतारा, जिसमें गुब्बारों को ऊपर भेजकर आपदा के समय सुदूर स्थानों पर अथवा सामान्य समय में गरीब स्थानों पर लोगों को वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जाती है। दुनिया के कुछ हिस्सों में गुब्बारों के परीक्षण के बाद अब यह परियोजना दूसरे चरण में प्रवेश करने वाली है।
- **आपदा निवारक केंद्र:** ऐसे लचीले एवं संवहनीय समुदाय तैयार करना, जो प्राकृतिक आपदाओं के समय वैकल्पिक ऊर्जा भी उपलब्ध करा सकें। इन सहयोगी केंद्रों का उपयोग सौर ऊर्जा, वर्षा का जल संग्रह करने और कचरे से खाद बनाने में किया जाएगा।
- **मॉड्यूलर आवासीय सुविधाएं, जिनका प्रयोग आवश्यकता के समय राहत शिविर लगाने में किया जा सके:** इनमें खाना पकाने, नहाने और सोने के स्थान जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी।
- स्मार्ट फोन और बुनियादी ढांचे में सेंसरों द्वारा तैयार की गई सूचना प्राकृतिक आपदाओं के मामले में बेहतर प्रतिक्रिया दे सकती है। उदाहरण के लिए भूकंप आने पर बचाव दलों को इम्प्लांट किए गए चिकित्सा उपकरणों अथवा सेंसरों से आ रहे सिग्नल पकड़कर प्रभावितों की सूचना दी जा सकती है। स्मार्टफोन सेंसरों से आ रहे सिग्नलों को कई गुना बढ़ा देंगे और बचाव दल उन सिग्नलों को पकड़ सकेंगे। एक अन्य उदाहरण सबवे प्लेटफॉर्म है, जिसमें अधिक भीड़ होने पर निगरानी करने और चेतावनी देने के लिए सेंसर लगाए गए हैं। जब उन्हें लगता है कि प्लेटफॉर्म की क्षमता भर की भीड़ आ गई है तो सेंसर पुलिस तथा यातायात अधिकारियों को स्वत: ही सूचित कर देते हैं, जो परिवहन के अतिरिक्त साधन के तौर पर बसों को स्टेशन पर भेज देते हैं।

वक्त का तकाजा है कि अलग थलग काम करने वालों से सूचना साझा कराई जाए तथा सभी मंत्रालयों में एक समन्वित प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए, जो इस समन्वित प्रयास की देखरेख कर सके।

संवहनीय व्यवस्था तभी संभव है, जब वस्तुओं और एजेंसियों के बीच ऐसे भौतिक एवं आभासी जोड़ तैयार किए जाएं, जो पहले कभी नहीं थे। प्रौद्योगिकी को भूमिका निभानी होगी और वह हमारे पारितंत्र से मिली समूची सूचना का उपभोग करने का हमारा तरीका ही बदल देगी। इससे पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार की बुराई दूर करने में मदद मिलेगी, जिससे कारोबार तथा आम नागरिक के जीवन की गुणवत्ता भी सुधारेगी। यह चरणबद्ध प्रक्रिया होगी, जो स्मार्ट सिटी अभियान के लिए हाल ही में कोष के आवंटन के साथ आरंभ हो चुकी है। इस कार्यक्रम की संभावना का दोहन करने के लिए निवेश के साथ प्रभावी क्रियान्वयन भी करना होगा। ❑

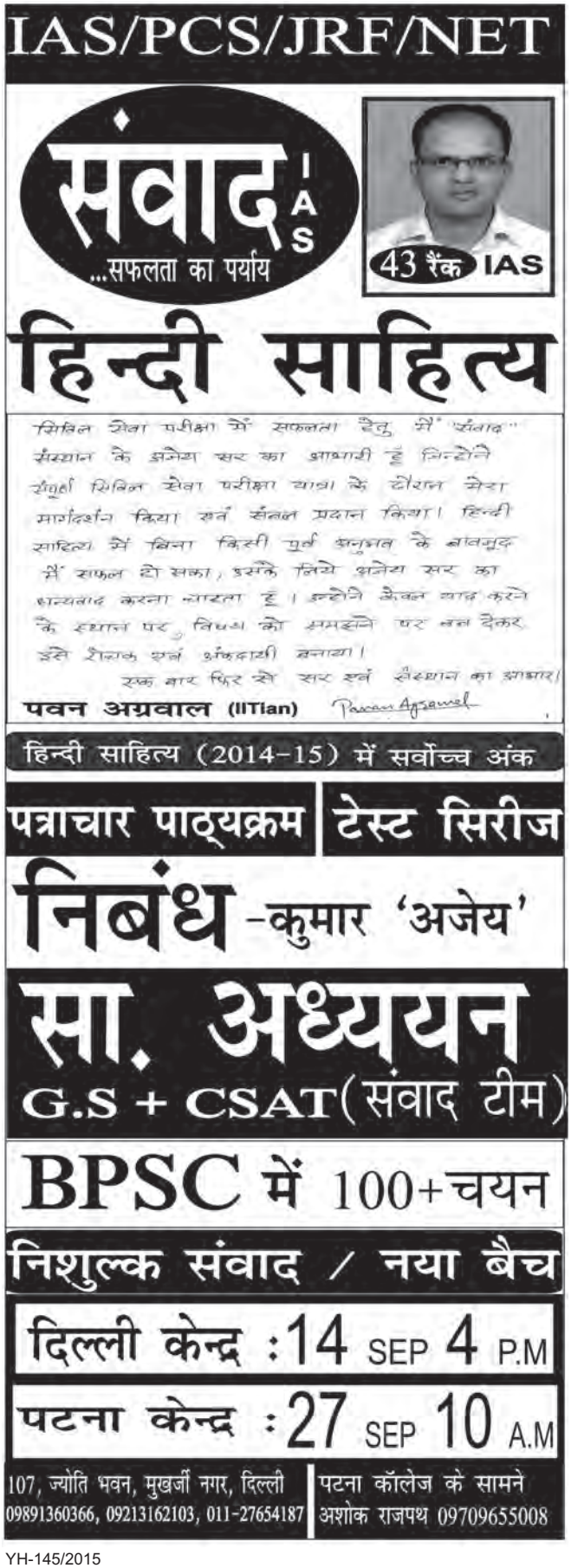

YH-145/2015

PATANJALI IAS

The Most Genuine, Reliable and Result Oriented Institute

सामान्य अध्ययन-1000 अंक + वैकल्पिक विषय-500 अंक + निबंध- 250 अंक + साक्षात्कार-275 अंक = कुल अंक-2025

संपूर्ण पाठ्यक्रम की सारगर्भित एवं समयबद्ध तैयारी 'पतंजलि संस्थान' के साथ
प्रत्येक खण्ड हेतु प्रामाणिक विशेषज्ञों की अनुभवी टीम

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन बैच - 2016

1 निः शुल्क कार्यशाला
Sep 11:30 am

- नियमित कक्षाएँ
- निर्धारित समयावधि में पाठ्यक्रम का योजनाबद्ध अध्यापन
- परिष्कृत, सारगर्भित एवं सटीक सामग्री
- नियमित टेस्ट एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

2014 रिजल्ट संस्थान से संबंधित 40 से अधिक सफल अभ्यर्थी

Outshining Results in 2014

More than 80% students selected with Philosophy Optional (Eng. or Hindi Med.) are trained by 'PATANJALI'

दर्शनशास्त्र

3 निः शुल्क कार्यशाला
Sep 09:15 am

JAIPUR CENTRE

RAS प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा का बैच जारी

नया बैच प्रारम्भिक परीक्षा के तुरंत बाद

दर्शनशास्त्र | निबंध | CSAT | TEST SERIES

दिल्ली एवं जयपुर के अतिरिक्त देश के किसी भी शहर में हमारी कोई भी शाखा या फ्रैंचाइजी नहीं है। अतः विद्यार्थी किसी भी भ्रामक विज्ञापन से सतर्क रहें।

HEAD OFFICE
202, 3rd Floor, Bhandari House (above post office)
Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 011-32966281, 9810172345, 7042499101, 2 , 3 , 4, 5

OLD RAJINDER NAGAR
104, 2nd Floor, Near Axis Bank
Old Rajinder Nagar, Delhi-60
Ph.: 011-45615758, 9811583851, 9555043146

JAIPUR CENTRE
31, Satya Vihar, Lal Kothi, Near Jain
ENT Hospital, New Vidhan Sabha, Jaipur
Ph.: 9571456789, 9680677789

YH-142/2015

शहरी कायाकल्प मिशनः कार्यान्वयन रणनीति

राकेश रंजन

25 जून, 2015 को भारत ने अपने बहुप्रतिक्षित शहरी कायाकल्प मिशन का शुभारंभ किया। संक्षेप में कहें तो, इस मिशन का उद्देश्य राज्यों को 100 स्मार्ट सिटी के निर्माण, 500 वर्ग-1 के शहरों के कायाकल्प, 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने, 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने, और विरासत केंद्रों के सुरक्षित रखने के लिए सहायता प्रदान करना है। जिन लोगों ने इस मिशन के बारे में जाना है, उनकी आशाएं अब और बढ़ गई हैं। विशेष कर मिशन के 'स्मार्ट सिटी कार्यक्रम' को लेकर, क्योंकि देश में कुछ नए कार्यक्रमों के जरिए आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से अपनी समस्याओं के त्वरित निदान के लिए उम्मीदें मुखर हो रही हैं

1-3 अगस्त, 2015 को सरकार की थिंक टैंक - नीति आयोग ने मानव विकास संस्थान (आईएचडी) एवं फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 'भारत में सतत और समावेशी शहरी विकास' पर एक तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरी विशेषज्ञ शामिल हुए।[1] उम्मीद के मुताबिक ही इस सम्मेलन के प्रभावी मुद्दों में शहरी कायाकल्प मिशन शामिल था। यदि संक्षेप में समझना चाहें तो इस मिशन से संबंधित निम्नलिखित प्रश्न इस सम्मेलन के दौरान पूछे गए:-

- तीव्र, पहले से अधिक स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास के संदर्भ में कुशल शहरीकरण के लिए एक विशेष तौर पर महत्वपूर्ण पूर्व-अपेक्षा है। ऐसे में भारत में स्मार्ट सिटी के जरिए कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी?
- इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या मिशन की पूर्ण सफलता को सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माताओं और क्रियान्वयन एजेंसियों के पास कोई कार्य प्रणाली या अधूरे कार्य हैं, जिन्हें तेजी से पूरा किया जाना हो?

इस आलेख में संक्षेप में इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रालयों ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के बड़ी सीख को शामिल करने के काफी उपाय किए हैं। इसमें किसी परियोजना का केंद्र से सूक्ष्म प्रबंधन नहीं करना और राज्य सरकारों को वृहतर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना शामिल है। हालांकि स्मार्ट सिटी की रूपरेखा तय करने में बहुत कुछ राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही भारत में कुशल शहरीकरण और इसके क्रियान्वयन की सफलता राज्य सरकारों द्वारा राज्य शासन से आगे बढ़कर शहरी शासन को शक्ति हस्तांतरित करने की उनकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करेगा। यह प्रक्रिया हाल ही पूर्ण हुए भारत के प्रमुख कार्यक्रम 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' में शुरू की गई थी, लेकिन अधूरी रह गई।

इसमें कुछ क्रमिक विरोधाभास भी हैं। पहला, नगरीय सुविधाओं की आपूर्ति में कुशलता हमारे जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करता है। संक्षेप में इन्हें निम्न तीन[2] वृहद श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक शहर स्मार्ट है यदि यह वह (1) सुनिश्चित करता है कि नगर के भीतर आर्थिक उद्यमों के विस्तार हेतु निवेश आकर्षित करने के लिए सकारात्मक संतुलन अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ता है, वहन करने योग्य मूल्य पर सभी को आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराता है तथा ग्रामीण शहरी संपर्कों को मजबूत करने का लाभ प्राप्त करता है। (2) सुनिश्चित करता है कि वह व्यवस्थित रूप से बसा हुआ है और सामूहिक स्थलों आदि के निर्माण के जरिए लोगों को उच्च स्तरीय जीवन प्रदान करता है। (3) सुनिश्चित करता है कि इसका ऊर्जा उपभोग संतुलित है और भौतिक पर्यावरण के साथ इसका साहचर्य स्थायी है। इस आलेख में आर्थिक विकास में शहरों की भूमिका पर सीमित प्रकाश डाला गया है। हालांकि किसी भी तरह से, अन्य गतिविधियों के महत्व को

लेखक नीति आयोग, भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के विभाग के सलाहकार हैं। यहां व्यक्त किए गए विचार उनके निजी विचार हैं। ईमेल: ranjanrakesh100@gmail.com

नकारा नहीं गया है। दूसरा, इस आलेख में जाहिर किए गए विचार जरूरी रूप से ऊपर उल्लिखित सम्मेलन के परिणाम नहीं हैं। तीसरा, मिशन की व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसके घटकों, कार्यक्रमों का आकार, उनका प्रारूप और दिशानिर्देश संबंधित मंत्रालयों द्वारा जनता के समक्ष रखे गए हैं।[3] अंत में, शासन से संबंधित चुनौतियों और अधूरे कार्यों को सूचीबद्ध करते समय, व्यर्थ की चीजों को छोड़कर केवल महत्वपूर्ण का चुनाव किया गया है।

इससे आगे, आलेख को निम्न प्रकार से बांटा गया है: खंड-1 भारत के विकास के संदर्भ में शहरीकरण के महत्व को संक्षिप्त रूप से विश्लेषित करता है और शहरीकरण में चुनिंदा बड़े चलन पर ध्यान देने के बाद, स्मार्ट बनने की योग्यता हासिल करने के लिए नगरीय शासनों की संभावित भूमिकाओं (जिसे पूरा करने की उनसे आशा की जाती है) को सूचीबद्ध किया गया है। फिर, जैसा कि यहां उल्लिखित है, शहर विकास का इंजन बनें, इस पर बहुत कम फोकस किया गया है। खंड-2 में शासन से संबंधित बड़ी चुनौतियों और अधूरे कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है और उनके हल के लिए बड़े पैमाने पर संस्तुतियां की गई है।

ग्रामीण भारत में कृषि रोजगार से दूर कुछ बदलाव के साथ, यह किसी के लिए मानना मुमकिन नहीं है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर सकता है, जबकि इसका आधा कार्य बल कृषि और संबद्ध गतिविधियों में उलझा है, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में केवल 17 प्रतिशत का योगदान देते हैं।

समावेशी आर्थिक वृद्धि और स्मार्ट सिटी

एक कुशल शहरीकरण कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। पहला, भारत की जीडीपी में कृषि और संबंद्ध गतिविधियों की हिस्सेदारी में, 1951 में 51.45 प्रतिशत के मुकाबले 2014-15 में 16.82 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद, इन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक बल के प्रतिशत में एक व्यावसायिक ठहराव दिखता है। इस दौरान कार्यरत श्रमिक बल की संख्या 70 प्रतिशत से घटकर केवल 54.6 प्रतिशत तक ही पहुंची है। तीव्र समावेशी विकास के लिए, तत्काल रूप से जरूरी है कि गैर-कृषि क्षेत्र में और भी तीव्र गति से लाभकारी रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में प्रभावी वृद्धि दर होने के बावजूद सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में लाभकारी आजीविका के अवसरों के सृजन की क्षमता बहुत अधिक रही। स्थानीय तौर पर चूंकि ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर शहरी हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि कुशल शहरीकरण समोवशी विकास के लिए जरूरी आरंभिक शर्त है।

हालांकि, उपरोक्त कथन काफी हद तक वैध है, यदि कोई भारत में शहरीकरण में उभरते चलन पर ध्यान दें तो, कुछ हद तक इसे पूरा करने की जरूरत है। पहला, प्रसिद्ध अवधारणाओं के विपरीत, भारत में शहरी जनसंख्या में बहुत तीव्र वृद्धि के अभी तक कोई साक्ष्य नहीं है[4], यद्यपि पिछले दशक में वार्षिक घातीय वृद्धि दर (एईजीआर) में मामूली बढ़त दर्ज की गई, जो 1990 में 2.73 प्रतिशत के मुकाबले 2001-2011 के दौरान बढ़कर 2.76 प्रतिशत हो गई, लेकिन अब भी यह 1970 के दशक के 3.8 प्रतिशत के मुकाबले काफी कम है। दूसरा, और फिर से, व्यापक रूप फैले मान्यताओं के विपरीत, ग्रामीण शहरी पलायन भी पूर्ववत् बना हुआ है। वृद्धि के एक महत्वपूर्ण भाग का दावा जिसके आधार पर किया जाता है वह 'जनगणना' का उद्भव है।

कस्बे जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के चारों ओर बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, अभी भी शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं हो पाए हैं। तीसरा, ग्रामीण भारत में गैर-कृषि रोजगार के सृजन के वास्तव में कुछ साक्ष्य मौजूद हैं।[5] भारत का ग्रामीण क्षेत्र विविध कारणों से निश्चित रूप से एक बदलाव से गुजर रहा है। इनमें उच्च कृषि विकास दर (विशेषकर 11वीं योजना के दौरान), घरेलू और विदेशी वित्त प्रेषित धन का उच्च स्तर और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, एकीकृत शिशु विकास योजनाएं आदि जैसे सामाजिक क्षेत्र की सरकारी योजनाओं की निधियों में धन की आपूर्ति शामिल है।

हमारे शहरी कायाकल्प मिशन को पूर्ण करने की दृष्टि से पूरे किए जाने वाले कार्यों के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? पहला, यदि शहरी भारत, भारत के कुल जीडीपी का 63 प्रतिशत उत्पादित करता है और फिर भी गांव से शहर की ओर पलायन पूर्ववत् जारी है, यह दिखाता है कि हमारे शहरों को अब भी समावेशी होने की जरूरत है। इसलिए किसी भी स्मार्ट सिटी में शहरी प्रबंधकों को निम्न विशेष कार्यों को करने की जरूरत है: भारत को यदि यह सुनिश्चित करना है कि उसकी विकास प्रक्रिया व्यापक और समावेशी रहे जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नारे 'सबका साथ सबका विकास' में सन्निहित है, तो समय आ गया है कि अब भारत प्रवासियों के अनुकूल विशेष नीति बनाए। यहां तक कि ग्रामीण भारत में कृषि रोजगार से दूर कुछ बदलाव के साथ, यह किसी के लिए मानना मुमकिन नहीं है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर सकता है, जबकि इसका आधा कार्य बल कृषि और संबद्ध गतिविधियों में उलझा है, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में केवल 17 प्रतिशत का योगदान देते हैं। दूसरा, केवल वर्तमान जनसंख्या के लिए ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में शहरों की ओर आने वाले पूर्वानुमानित प्रवासियों के लिए जो कि आमतौर पर गरीब होते हैं और उनकी भुगतान क्षमता सीमित होती है, के लिए शहर को तैयार करने हेतु उन्हें आधारभूत सुविधाओं की आपूर्ति का विस्तार करना होगा।

हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में प्रभावी वृद्धि दर होने के बावजूद सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में लाभकारी आजीविका के अवसरों के सृजन की क्षमता बहुत अधिक रही। स्थानीय तौर पर चूंकि ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर शहरी हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि कुशल शहरीकरण समोवशी विकास के लिए जरूरी आरंभिक शर्त है।

इसके अलावा जनगणना के आंकडे एक रुझान दिखाते हैं कि भारत की समावेशी विकास की कहानी ज्यादातर मध्यम आकार के कस्बों और शहर के आस-पास के क्षेत्रों

में लिखी जा सकती है, जिनकी संख्या लाखों में है। स्मार्ट सिटी के शहरी प्रबंधकों का मुख्य कार्य सामान्य तौर पर ग्रामीण शहरी आर्थिक संपर्कों को बढ़ावा देना है और शहर से सटे क्षेत्रों में जो कि अब तक विकास से ओझल रहे हैं लेकिन व्यापक आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र के रूप में उभर चुके हैं, भुगतान क्षमता के भीतर सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं सहित आधारभूत सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इससे ग्रामीण और शहरी भारत का एक साथ विकास करना संभव हो पाएगा। यहां एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि एक असंगठित मजदूर और संबंधित नियोक्ता के बीच सीधे बातचीत स्थापित करने के लिए सूचना विनिमय का तंत्र विकसित किया जाए। इसका उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका को कम करना है जो अभी एजेंसी कमीशन के नाम पर मजदूरी का एक बड़ा हिस्सा हड़प जाते हैं।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तविक रूप से, स्मार्ट सिटी के निर्माण में विकास के मानदंडों का सावधानीपूर्वक आकलन आवश्यक है। इसमें एक तरफ जहां शहर की राशि, स्थल और आस-पास से इसका संपर्क महत्वपूर्ण बिंदु है, वहीं दूसरी तरफ शहर की क्षमता के मुताबिक वास्तविक योजनाएं और उसे पूरा करने के लिए संसाधन शामिल हैं। विश्व स्तरीय व्यापार को आकर्षित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से इंजीनियरिंग परियोजना के तौर पर श्रेष्ठ कॉलोनियों का निर्माण एक रणनीति हो सकती है, लेकिन शायद ही कभी यह एक प्रभावी नीति का हिस्सा हो। इसी कारण से स्मार्ट सिटी की निर्माण योजना राज्यों और शहरों को विभिन्न प्रकार के स्मार्ट सिटी के चुनाव की छूट देती है और इसके लिए कायाकल्प और शहरी बदलाव के लिए अटल मिशन (अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन-अमृत) के रूप में एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अमृत के तहत 500 शहरों में अवसंरचनात्मक ढांचों का विकास किया जाएगा और 2022 तक सभी के लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है, जिसके तहत पानी, बिजली, स्वच्छता, ब्रॉडबैंड आदि से युक्त किफायती मकानों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।

वास्तविक रूप से, स्मार्ट सिटी के निर्माण में विकास के मानदंडों का सावधानीपूर्वक आकलन आवश्यक है। इसमें एक तरफ जहां शहर की राशि, स्थल और आस-पास से इसका संपर्क महत्वपूर्ण बिंदु है, वहीं दूसरी तरफ शहर की क्षमता के मुताबिक वास्तविक योजनाएं और उसे पूरा करने के लिए संसाधन शामिल हैं।

अधूरे कार्य एवं क्रियान्वयन की चुनौतियां

भारत में शहरीकरण की चुनौतियां बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और तुलनात्मक अध्ययन के लिए इच्छुक पाठक 12वीं योजना का अध्ययन कर सकते हैं। संक्षिप्त करने के लिए- भारतीय शहरों के पास खंडित शासकीय ढांचा है, जिसमें जिम्मेवारियों और उत्तरदायित्व का स्पष्ट वर्णन नहीं है, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) या शहर की सरकारें जिनके ऊपर शहरों के संचालन की जिम्मेवारी होती है, विश्व के स्मार्ट शहरों के मुकाबले भारत के सांस्थानिक तथा वित्तीय रूप से इतने कमजोर हैं कि ठीक प्रकार से अपने कार्यों के निष्पादन में असमर्थ हैं, और न ही भविष्य के लिए उनको मजबूत किया जा रहा है, आधारभूत संरचना के विकास के लिए काफी अधिक निवेश की जरूरत है, जबकि शहरी शासन के पास निवेश के स्रोत उत्पन्न करने के लिए कोई योजना नहीं है और न ही राज्य/संघीय सरकारों द्वारा हस्तांतरित धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में परियोजनाओं को लागू करने के लिए अपनी क्षमता का विकास कर रहे हैं। यहां पर तदर्थता है, क्योंकि शहरी योजना शहर प्रबंधन में सबसे कमजोर कड़ियों में से एक रहा है। चतुर मध्य वर्ग या शहरी उच्च वर्ग द्वारा शहर के शासन पर कब्जा कर लिया जाता है। जिसमें शहरी गरीबों के लिए बहुत कम स्थान रह जाता है, ऐसी और भी कई कमियां हैं। इसके अलावा भूमि उपयोग का मसला बाज़ार की सच्चाईयों और परिवहन योजनाओं से बेपरवाह चिंताजनक स्थिति में होता है।

सौभाग्य से इन चुनौतियों में से कोई भी ऐसी नहीं है जिससे पार नहीं पाया जा सकता और यदि अन्य देशों ने यह कर दिखाया है तो, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम नहीं कर सकते। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जेएनएनयूआरएम की 2005 में बहुत ही उत्साह और आशा के साथ शुरुआत हुई थी, और इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। इसके जरिए 23 शहरी सुधारों को मंजूरी दी गई, जिसमें से अधिकतर का उद्देश्य शहरी शासन ढांचों में सुधार लाना था और इन सुधारों को पूरा करने के लिए संघीय सहायता को राज्यों से जोड़ना था।

ये सुधार भारतीय शहरी शासन संरचना में रिक्त स्थानों की पहचान कर उनके सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और इन कमियों को कैसे दूर किया जाए, पर आधारित था। शहरी शासन का सशक्तीकरण करना और उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, सतत विकास हेतु और अधिक कुशल भूमि उपयोग के लिए शहरी स्तर पर नियोजन में सुधार, शहरी गरीबों को आधारभूत सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, शहरी स्तर की परियोजनाओं में निजी साझेदारी को बढ़ावा देना, शहरी भूमि बाज़ार में मौजूद विकृति को दूर करना और शासन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना और पारदर्शिता लाना आदि उनके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल थे।

शहरी योजना शहर प्रबंधन में सबसे कमजोर कड़ियों में से एक रहा है। चतुर मध्य वर्ग या शहरी उच्च वर्ग द्वारा शहर के शासन पर कब्जा जमा लेना जिसमें शहरी गरीबों के लिए बहुत कम स्थान रह जाता है, ऐसी और भी कई कमियां हैं। इसके अलावा भूमि उपयोग का मसला बाज़ार की सच्चाईयों और परिवहन योजनाओं से बेपरवाह चिंताजनक स्थिति में होता है।

जेएनएनयूआरएम का एक तात्कालिक योगदान यह बताना था कि शुरुआत कैसे की जाए। इसने वास्तव में कम-से-कम शहरी सुधारों पर बहस को मुख्य धारा में शामिल कराया और कई राज्यों और शहरों ने इन सुधारों को शुरू करने के लिए ठोस कदम उठाए। हालांकि, इस चुनौती के जारी प्रकृति पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। सबसे पहले न्यूयॉर्क या लंदन जैसे शहरों की तुलना में, भारतीय शहरी शासन प्रति एक लाख जनसंख्या पर कर्मचारियों की संख्या में न केवल चिंताजनक रूप से अक्षम है, बल्कि नगरपालिकाओं का समूचा कार्यबल बुरी स्थिति में है। केंद्रीय मंत्रालय से एक आदर्श सुझाव मिलता है कि नगरपालिका में कर्मचारियों की और भर्ती की

जाए। इसका जवाब यह होता है कि जब नगरपालिका शासन मौजूदा कर्मचारियों को ही वेतनमान देने के लिए जूझ रही है, तो बड़ी संख्या में अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए वेतन की व्यवस्था कहां से करेगी।

एक तर्क दिया जाता है कि हाल में 14वें वित्त आयोग ने यूएलबी को मिलने वाली राशि में काफी वृद्धि की है, जिसका उपयोग नगर निकायों के कर्मचारियों के लिए किया जा सकता है। हालांकि, एक मोटे अनुमान के अनुसार ये अनुदान प्रति नगरपालिका के लिए औसत रूप से केवल 4.3 करोड़ रुपये बैठते हैं और वित्त आयोग ने यूएलबी को आधारभूत सुविधाओं के लिए भी इस अनुदान को खर्च करने की सलाह दी है। इससे संबंधित निकटतम चुनौती यह है कि शहरी शासन सहयोगात्मक है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहारिक संस्थानिक संरचना का अभाव है। 74वें सीएए में शहरों के प्रबंधन में निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रमुखता देने का अंतर्निहित पूर्वानुमान यह है कि वे लोगों के प्रति ज्यादा जवाबदेह होते हैं, वे लोगों की जरूरतों को दिखाने के लिए शहरी नियोजन को सुनिश्चित करेंगे और उसी के अनुरूप परियोजनाओं को प्रमुखता देंगे। हालांकि, शहरी क्षेत्र ने कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे नागरिक समाजों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को देखा है, ये स्पष्ट संकेत करते हैं कि शहरी आबादी का एक बड़ा भाग अपना विश्वास निर्वाचित शहरी प्रतिनिधियों के स्थान पर इन निकायों में व्यक्त करता हैं।

शहरी नियोजन जैसे शहरों का प्रबंधन, मेट्रो रेल जैसी शहरी परिवहन परियोजनाएं, स्वच्छता एवं जल आपूर्ति जैसी परियोजनाओं का नियोजन वास्तव में तकनीकी पहलू हैं और शहरी शासन में विशेषज्ञों के महत्व को नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है।

शहरी शासन में दूसरी निकटवर्ती चुनौती नगरपालिका स्तर पर योजनाओं/कार्यक्रमों को एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाना है। शासन संबंधित मामलों में यदि नगरपालिका शासन एकल खिड़की के रूप में कार्य करे तो यह एक आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि, राज्य सरकारों और समकक्ष शासनों में मौजूद समांतर विभागों ने नगरपालिकाओं को यह भूमिका निभाने से रोका है।

एक दूसरा मामला जो कि नगरपालिकाओं को केंद्रीय भूमिका निभाने से मना करता है, वह विशेषज्ञों और निर्वाचित निकायों के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं। शहरी नियोजन जैसे शहरों का प्रबंधन, मेट्रो रेल जैसी शहरी परिवहन परियोजनाएं, स्वच्छता एवं जल आपूर्ति जैसी परियोजनाओं का नियोजन वास्तव में तकनीकी पहलू हैं और शहरी शासन में विशेषज्ञों के महत्व को नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि, शहर प्रबंधकों का जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना अति आवश्यक है, विशेषकर यदि संसाधन कम हों और परियोजनाओं को प्रमुखता के आधार पर पूरा करना हो। विश्व के किसी भी भाग में अनुभव से पता लगता है कि लंबे समय में जनता के प्रति जवाबदेही सर्वोत्तम तरीके से तब सुनिश्चित की जाती है, जब चुने गए जनप्रतिनिधियों को सशक्त किया जाता है। इसलिए दिल्ली मेट्रो रेल का संचालन करने वाले विशेषज्ञों और दिल्ली के नगरपालिकाओं के बीच किस तरह के संबंध होने चाहिए? मेट्रो की दिशा किसे तय करनी चाहिए? अहमदाबाद या दिल्ली में भूमि उपयोग का प्रारूप: विशेषज्ञ के नेतृत्व में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एयूडीए) या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) या संबंधित नगरपालिका निगम को? ये सभी मूल रूप से बहुत कठिन प्रश्न हैं।

दूसरा मामला जो सीधे सभी के लिए आवास कार्यक्रम को प्रभावित करता है, वह है नगर निकायों या शहरी भूमि पर नियंत्रण की कमी होना, क्योंकि सामान्य तौर पर इनका प्रबंधन डीडीए और एयूडीए जैसी विकास एजेंसियां करती हैं। अत: झुग्गी पुनर्वास और सभी के लिए आवास की जिम्मेवारी नगरपालिकाओं की ही होनी चाहिए, जबकि इन कामों को पूरा के लिए जरूरी भूमि पर नियंत्रण दूसरी एजेंसी का होना चाहिए।

अम्रुत और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की निर्माण की योजना का स्पष्ट मत है कि शहरों को ही योजना बनानी है। यहां पर अधूरा कार्य यह है कि राज्य/शहर नियोजन के लिए व्यापक नमूने की व्यवस्था करना चाहते हैं जिसे कि एक तरफ तकनीकी रूप से मजबूत कदम कहा जा सकता है, तो दूसरी और सहयोगात्मक नियोजन तकनीक को शामिल करता है। किसी भी प्रकार से यह एक असाधारण कदम नहीं है। व्यापक नमूने का विकास नहीं होने की स्थिति में सलाकारों द्वारा योजना बनाए जाने का खतरा होता है जिसकी जिम्मेवारी यूएलबी पर या राज्य सरकार पर नहीं होती है। जेएनएनयूआरएम के तहत कई शहरी विकास योजनाओं के साथ यह मामला हो चुका है।

संस्तुतियां

- शहरी मिशन की क्रियान्वयन रणनीति में शहरी शासन से संबंधित सुधारों को शामिल करने की अत्यंत आवश्यकता है। लघु और मध्यम अवधि में गुणवत्तापूर्ण कर्मचारियों की कमी की समस्या के हल के लिए मंत्रालय यूएलबी के लिए धनराशि की व्यवस्था कर सकता है, जिससे बाज़ार से उपयोगी कर्मियों की व्यवस्था की जा सके, क्योंकि समर्पित नगरपालिका कर्मचारियों का सृजन खर्चीला और समय खपाने वाली प्रक्रिया है जो कि केवल लंबे समय के लिए उपयोगी रणनीति हो सकती है।

राज्य/शहर नियोजन के लिए व्यापक नमूने की व्यवस्था करना चाहते हैं जिसे कि एक तरफ तकनीकी रूप से मजबूत कदम कहा जा सकता है, तो दूसरी और सहयोगात्मक नियोजन तकनीक को शामिल करता है। किसी भी प्रकार से यह एक असाधारण कदम नहीं है।

- जेएनएनयूआरएम की तर्ज पर ही सरकार को भी विभागीय कर्मचारियों, जो कि अभी शहरी शासन में कार्यरत हैं, के साथ 18 कार्यों की जिम्मेदारी हस्तांतरित कर राज्यों को लाभ पहुंचाते रहना चाहिए।
- इस प्रकार के हस्तांतरण के साथ ही नगर निकायों के लिए बजट बनाने में बड़े सुधार किए जाने बाकी हैं। पूर्व में योजना आयोग के सदस्य रहे अरुण मायरा के नेतृत्व में एक समिति ने 2012 में संस्तुति की थी कि नगर निकायों के बजट सभी पावतियों और खर्च को दिखाते हुए शुरू होने चाहिए, जिसमें 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के लिए लागू की जाने वाली योजनाओं में राज्य और केंद्र सरकार से प्राप्त सहायताओं का भी जिक्र हो। इससे नगर निकाय शासन को अपनी पावतियों और जिम्मेदारियों के प्रति स्पष्ट

रूप से जवाबदेह बनने और सरकारी पहलों को केंद्रित करने में सुविधा होगी। इससे नगर निकायों के सही कर्तव्य प्रदर्शित होंगे और उनके खातों की पारदर्शिता निजी निवेश आकर्षित करने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि नगर निकाय शासन को निजी निवेश आकर्षित करने के लिए संघीय हस्तांतरण को फायदेमंद और सुरक्षित बनाया जा सके।

- नागरिक समाजों और नगर निकायों के बीच रचनात्मक सहयोग के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म तैयार करने की अत्यंत आवश्यकता है। लोक केंद्रित शहरी नियोजन में सुधार के लिए जरूरी शहरी सेवाओं की कमियों का विश्व स्तरीय सर्वेक्षण तैयार करने के लिए हाल में शीला पटेल के नेतृत्व में सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एरिया रिसोर्स सेंटर (एसपीएआरसी) ने नगर निकाय शासन के साथ साझेदारी की है। इस प्रकार के मॉडल आसानी से दोहराए जा सकते हैं।
- विशेषज्ञों और निवार्चित निकायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध मुश्किल लेकिन संभव हैं। 12वीं योजना में कहा गया है कि यदि भूमिका और जिम्मेवारियां स्पष्ट रूप से वर्णित हैं, तो एक साझेदारी का प्रोटोकॉल विकसित किया जा सकता है। जहां तक सिद्धांत की बात है, परियोजनाओं के चुनाव और प्रमुखता का मसला निर्वाचित निकायों का अधिकार है, जबकि इस पर अमल करने की जिम्मेदारी विशेषज्ञों पर छोड़ी जानी चाहिए। बारहवीं योजना में निर्दिष्ट दूसरा उपयुक्त मॉडल यह है कि नगरपालिकाओं जैसे निवार्चित निकायों को दिल्ली जल बोर्ड वाले निकायों के साथ समझौता करना चाहिए जिसमें उत्पाद और जिम्मेवारियों का स्पष्ट वर्णन हो। इसमें आवश्यक बदलाव करना भी शामिल है ताकि भूमि उपयोग के प्रारूप के निर्धारण के समय विशेषत: क्षमता के भीतर गृह परियोजनाओं और बेघरों के लिए आश्रय स्थल के निर्माण के लिए, नगर निकायों की सहमति हो। इस प्रकार की व्यवस्था से निर्णय लेने और लोगों के प्रति जवाबदेही के लिए व्यावसायिक कौशल का विकास होता है। ❑

संदर्भ

1. भारत में सतत और समावेशी विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (नई दिल्ली, 1-3 अगस्त, नीति आयोग, आईएचडी और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय)
2. बंदरगाह वाले शहर राष्ट्र के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, आदि जैसे अन्य उद्देश्य भी हैं।
3. उदाहरण के लिए भारत सरकार के शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं।
4. देबोलिन कुंडु: शहरी विकास में मंदी (http://infochangeindia.org/urban-india/analysis/slowdown-in-urban-growth.html)
5. प्रणब सिद्धस्वामी, 2014,' 'कृषि से गैर-कृषि: भारतीय गांव है ''शहरीकरण''? सीपीआर शहरी वर्किंग पेपर 4, नवंबर 2014
6. ईशर अहलुवालिया के नेतृत्व में उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी, 2011), शहरी विकास मंत्रालय
7. 12वीं पंचवर्षीय योजना, खंड 2, अध्याय 18, भारत सरकार (2012)

पाठकों से

योजना में प्रकाशनार्थ आलेख व प्रतिक्रियाएं yojanahindi@gmail.com पर ईमेल के द्वारा प्रेषित की जा सकती हैं। आप हमारे फेसबुक पेज **योजना हिंदी** पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी राय, सुझाव व सहयोग का इंतजार रहेगा।

–संपादक

नामांकन आरम्भ

हम आपको प्रशासक बनाते हैं, इतिहासकार नहीं!

SIHANTA IAS

इतिहास का एकमात्र मानक संस्थान

इतिहास

रजनीश राज

निःशुल्क कार्यशाला

1 सितम्बर सायं 5:00 बजे

उपरोक्त सभी प्रतिभागी इतिहास में श्रेष्ठ अंक के कारण ही कामयाब हुए

संकल्पनात्मक विकास एवं लेखन शैली पर सर्वाधिक बल के कारण सिहान्ता के श्रेष्ठ अंकधारी

विष्णुकांत तिवारी-378 अंक
नरेश सैनी -376 अंक
रामाशीष -376 अंक
आलोक पाण्डेय-372 अंक
राजेन्द्र मीणा -371 अंक
मयंक प्रभा -371 अंक
द्रोपसिंह मीणा-371 अंक
इत्यादि

विशिष्ट बिंदु

- बेसिक से उच्च स्तर तक का अध्ययन
- 100% कोर्स कवरेज एवं 100% प्रश्न-पत्र की गारंटी।
- समझ विकसित करने पर विशेष बल।
- प्रश्न समझने एवं उत्तर लिखने का कौशल विकसित करने पर सर्वाधिक बल।
- प्रत्येक अध्याय पर आकस्मिक टेस्ट एवं नियमित टेस्ट।
- मानचित्र की नियमित कक्षाएं।
- प्रत्येक अध्याय से संबंधित अभ्यास पुस्तिका एवं सार संक्षेप

Plot No. 8-9, Flat No. 301-302, Ansal Building, Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

Web: www.sihantaias.com

Ph.: 011-42875012, 08743045487, 09990107573

YH-146/2015

IAS **IGNITED MINDS** PCS

अमित कुमार सिंह के निर्देशन में

पूरे भारत में हिन्दी माध्यम में सर्वाधिक चयन देने वाला संस्थान। इस वर्ष भी कुल 50⁺ चयन

ध्यान दें ये परीक्षा परिणाम साक्षात्कार एवं मॉक इंटरव्यू के नाम पर जुगाड़ से नहीं जुटाये गये हैं। ये सभी हमारे कक्षा कार्यक्रम में शामिल रहे हैं।

Name	Rank	Name	Rank	Name	Rank	Name	Rank	Name	Rank	Name	Rank
NISHANT JAIN	13	PRADIP SINGH	310	AMIT KR. SINGH	396	NIVEDITA GUPTA	591	BHOYAR HARSHAL	791	UTSAV	1075
ANIL DHAMELIA	23	RAJENDER PENSIYA	345	SHREYANSH MOHAN	465	HITESH KUMAR	634	ANIRUDHA	804	KIRNEDU	1106
MIHIR PATEL	27	DHARMVIR SINH	357	ISHANI	502	MEHULKUMAR	704	SANTOSH KUMAR	850	AMIT VASAVA	1114
RAJENDER K PATEL	70	RAJTANIL	367	ALPESH	537	DEEPAK	717	KARTIK	871	AVINSH KUMAR	1132
KAVAN NARESH K.	198	SHASHIKANT SHARMA	384	GHANSHYAM MEENA	539	NIRVKUMAR	751	PULKESH	1050		

हमारे आगामी कक्षा कार्यक्रम

ETHICS

(G.S. PAPER-IV)

ETHICS में हमारे संस्थान से 70 से अधिक विद्यार्थियों को 100⁺ अंक

हमारे अन्य अभ्यर्थी जिन्होने एथिक्स में 100+ अंक प्राप्त किए, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं-

नाम	अंक
अनिल धमेलिया	109
संतोष कुमार	109
मिहिर पटेल	108

नि:शुल्क कार्यशाला के साथ नया बैच प्रारम्भ

दिल्ली केन्द्र	इलाहाबाद केन्द्र
27 AUGUST 7 PM	11 SEPTEMBER 10 AM

दर्शनशास्त्र

एक बार फिर हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ विषय

लगातार 7वें वर्ष दर्शनशास्त्र में (गैर अंग्रेजी माध्यम) सर्वोच्च रैंक एवं सर्वोच्च अंक हमारे संस्थान सें

मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अमित कुमार सिंह सर (Ignited Minds) को दूँगा। विद्यार्थी के तौर पर मेरी यात्रा दर्शनशास्त्र और एथिक्स में सर के प्रशिक्षण से प्रारम्भ हुई और इसका सुखद अन्त IAS बनने के साथ हुआ। आभार अमित सर!
मिहिर पटेल

सबसे युवा टॉपर आयु- 24 वर्ष

311 अंक

295 अंक

288 अंक

281 अंक

सफलता की कहानी जारी.... अब आपकी बारी.....

नि:शुल्क कार्यशाला के साथ नया बैच प्रारम्भ

दिल्ली केन्द्र	इलाहाबाद केन्द्र
27 AUGUST 4 PM	11 SEPTEMBER 4:30 PM

A -2, 1st Floor, Comm. Comp., Near Mukherjee Nagar,Delhi-09
Ph. 8744082373, 9643760414

H-1 , First Floor, Madho Kunj, Katra, Allahabad
Ph. 9389376518, 9793022444

Ph.: 011-27654704, 0532-2642251

Website: www.ignitedmindsias.com

YH-143/2015

शहरी नियोजनः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

पवन कुमार शर्मा

जब भी स्मार्ट शहर यानी बुद्धिमत्ता के साथ बनाए गए सुनियोजित शहर की बात की जाती है तो प्राचीन काल की कई नगरी हमारे ध्यान में आती हैं। अंग्रेजों के आने के बाद भी कई शहर सुनियोजित ढंग से बसाए गए और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भी इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्यकाल के स्मार्ट शहरों के बारे में बात कम ही होती है, जबकि वास्तव में वे शहर ही स्मार्ट सिटी की अवधारणा के सबसे करीब आते हैं। भारत में फतेहपुर सीकरी, पुडुचेरी और जयपुर आदि ऐसे ही शहर हैं

अतीत साक्षी है कि भारत में शहर और गांवों का नियोजन कितना व्यवस्थित होता था। शहर और ग्रामों के व्यवस्थित नियोजन के ही कारण भारत विकास के चरमोत्कर्ष तक पहुंच सका था। नियोजकों ने मस्तिष्क में इन समस्त बातों का भरपूर ध्यान रखा था कि शहर और गांवों के मध्य संतुलन बना रहे । अव्यवस्थित विकास से यह व्यवस्था चरमरा न उठे। संस्कृत साहित्य में इन सभी बातों के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हैं। इस अध्याय में उन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।

नियोजन की अवधारणा

शहर और गांवों के नियोजन के संबंध में चिंतकों ने भरपूर चिंतन किया था और इस बात का ध्यान रखा था कि विकास के संदर्भ में गांव और शहरों के मध्य समन्वय बना रहे। इस हेतु उन्होंने उस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा था। चिंतकों के ध्यान में यह विषय गंभीरता से बैठा हुआ था कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसका सामाजिक और आर्थिक विकास न हो। इसलिए चिंतकों ने नियोजन को राजधर्म माना। इसलिए ही शासकों ने ग्रामीण और शहरी विकास के माध्यम से नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करने के प्रयास किए। इस संबंध में उन्होंने यातायात, जनसंख्या एवं आवासीय व्यवस्थाओं पर अत्यधिक बल दिया। आधुनिक समय की तरह शहरी और ग्रामीण समस्याओं का सामना प्राचीन काल के नागरिकों को नहीं करना पड़ता था। नियोजन में तत्कालीन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर विकास का प्रारूप तैयार किया जाता था। राज्यों के पास एक कार्यक्रम होता था जिसके माध्यम से वे शहर और गांवों में जनसंख्या स्थापना के कार्यों को अंजाम देते थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, कालीबंगा एवं लोथल के खण्डहर इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि उस समय का नियोजन कितना स्पष्ट हुआ करता था। रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति में वर्णित शहरों के वर्णन से उनके नियोजन, विकास एवं भव्यता का आंकलन सहजता से ही किया जा सकता है। उस समय के शहरों अयोध्या, किष्किंधा, लंका, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली, काशी, द्वारिका, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आदि के वर्णन से इस बात के प्रमाण मिल जाते है।

कौटिल्य लिखते हैं कि, ''राज्य की सीमा पर अंतफल नामक दुर्ग रक्षण के संरक्षण में एक दुर्ग की भी स्थापना करें। जनपद की सीमा पर अंतफल की अध्यक्षता में ही आधारभूत स्थानों का भी निर्माण करें। उनके भीतरी भागों की रक्षा व्याघ, शबरी, पुलिंद्र, चाण्डाल आदि वनचर जातियों के लोग करें।[1] राजा को चाहिए कि ऋत्विक, आचार्य पुरोहित तथा श्रोत्रिय आदि ब्राह्मणों के लिए भूमिदान करें किंतु उनसे कर आदि न ले और उस भूमि को वापिस भी न ले। इसी प्रकार विभागीय अध्यक्षों, संख्यायकों (लिपिकों), गोपों (दस-दस गांवों के अधिकारियों), वैद्यों, अश्वशिक्षकों और जंघाकारियों (दूर देश में जीविकोपार्जन करने वाले लोगों) आदि अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रजाजनों के लिए भी राजा भूमि दान करें। किंतु इस प्रकार पाई हुई जमीन को बेचने या गिरवी रखने के लिए वर्जित कर दें।[2] कौटिल्य का मानना है कि सामाजिक सरोकारों की पूर्ति या तो राज्य कर या फिर समस्त समाज स्वयं करे, कोई भी इसमें से बचने का प्रयास करे तो समाज उसका प्रतिकार करे। राजा को चाहिए कि वह आकर (खान) से उत्पन्न सोना-चांदी आदि

लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) के समाज विज्ञान संकाय में के अधिष्ठाता हैं। समाजशात्रीय सेमिनारों में इनकी सक्रिय उपस्थिति रही है। ईमेलः pawan_sharma1967@yahoo.co.in

के विक्रय-स्थान, चंदन आदि उत्तम काष्ठ के बाज़ार, हाथियों के जंगल, पशुओं की वृद्धि के स्थान, आयात-निर्यात के स्थान, जल-थल के कार्य और बड़े-बड़े बाज़ारों या बड़ी-बड़ी मण्डियों की भी व्यवस्था करें।[3] ऐसा करके राजा गांवों की अर्थ व्यवस्था में प्रभारी भूमिका निभा सकता है।

शहरी नियोजन

प्राचीन भारत में शहरी नियोजन की व्यवस्था भी अद्भुत् थी। प्रस्तुत अध्ययन में जो वर्णन किया जा रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि उस समय का नियोजन कितना उच्च स्तर का था। रामायणकार लिखते हैं कि ''अयोध्या के चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जेय थी। घोड़े, हाथी, गाय-बैल, ऊंट तथा गदहे आदि उपयोगी वस्तुओं से वह पूरी भरी-पूरी थी।[4] यानि यह नगर भी था और सुरक्षा की दृष्टि से किले का भी आकार लिए हुए थी। इस प्रकार का समन्वय विरले ही मिलता है। आगे लिखते है कि- ''क्या तुम्हारे सभी दुर्ग (किले) धन-धान्य, अस्त्र-शस्त्र, जल, यंत्र, शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकों से भरे-पूरे रहते है।[5] प्राचीन भारत में नगर नियोजन कुछ मूलभूत नियमों पर आधारित था जैसे कि- मुख्य मार्गो का नियमित विकास, शहर का उपविभाजन तथा सड़कों की चौड़ाई निर्धारित करना। शहर में मंदिर, मार्ग, पैदलपथ, बाज़ार, बाग-बगीचे एवं मनोरंजन के विभिन्न स्थान निर्धारित थे तथा नगर में व्यवस्थित प्रवाह प्रणाली स्थापित करने के परिनियम निर्धारित किए गए थे। इसके अतिरिक्त अग्नि प्रज्वलन के कारण एवं उसके शमन पर भी व्यापक रूप से विचार किया गया था।[6] शहर को राजधानी के रूप में विकसित करने में राजा का प्रासाद केंद्रबिंदु था। मनु ने सुझाया कि राजा को अपनी राजधानी इस प्रकार से बनानी चाहिए जो कि चंदनाकृति, धाकृति, जलाकृति, वृक्षाकृति, पर्वताकृति हो, इन मानव-निर्मित दुर्ग में से किसी भी एक प्रकार के दुर्ग को राजा को संरक्षित कर लेना चाहिए।[7]

कौटिल्य नगर नियोजन की अनेकानेक अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं। नगर के सुदृढ़ भूमि भाग में राजभवनों का निर्माण कराना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि चारों वर्णो की आजीविका के लिए उपयोगी हो। गृह भूमि के बीच से उत्तर की ओर नवें हिस्से में अंत:पुर के पूर्वोत्तर भाग में आचार्य, पुरोहित के भवन, यज्ञशाला, जलाशय और मंत्रियों के भवन बनवाए जाएं। अंत:पुर के पूर्व दक्षिण भाग में महानस (रसोईघर), हस्तशाला और कोष्ठागार हों। उसके आगे पूरब दिशा में इत्र, तेल, पुष्पहार, अन्न, घी, तेल की दुकानें और प्रधान कारीगरों एवं क्षत्रियों के निवास स्थान होने चाहिए। दक्षिण-पूरब में भंडागार, राजकीय पदार्थों के आय-व्यय का स्थान और सोने-चांदी की दुकानें होनी चाहिए। उससे आगे दक्षिण दिशा में नगराध्यक्ष, धान्याध्यक्ष, व्यापाराध्यक्ष, खदानों तथा कारखानों के निरीक्षक, सेनाध्यक्ष, भोजनालय, शराब एवं मांस की दुकानें, वेश्या, नट और वैश्य आदि के निवास स्थान होने चाहिए।

पश्चिम-दक्षिण भाग में ऊंटों एवं गदहों के गुप्ति स्थान (तबेले) तथा उनके व्यापार के लिए एक अस्थाई घर बनवाया जाए। पश्चिम-उत्तर की ओर रथ तथा पालकी आदि सवारियों के रखने के स्थान होने चाहिए। उसके आगे पश्चिम दिशा में ही ऊन, सूत, बांस और चमड़े का काम करने वाले, हथियार और अंक म्यान बनाने वाले और शूद्र लोगों को बसाया जाना चाहिए। उत्तर-पश्चिम में राजकीय पदार्थो को बेचने-खरीदने का बाज़ार और औषधालय लाने चाहिए। उत्तर-पश्चिम में राजकीय पदार्थो को बेचने-खरीदने का बाज़ार और औषधालय होने चाहिए। उत्तर -पूरब में कोष-गृह और गाय-बैल तथा घोड़ों के स्थान बनवाने चाहिए। उसके आगे, उत्तर दिशा की ओर नगर देवता, कुल देवता, लुहार, मनिहार और ब्राह्मणों के स्थान बनवाए जाएं। नगर के ओर-छोर जहां खाली जगह छूटी है, धोबी, दर्जी, जुलाहे और विदेशी व्यापारियों को बसाया जाए।

प्रमुख प्राचीन शहर

रामायणकार ने अपनी अमरकृति रामायण में अनेकानेक शहरों का वर्णन किया है, जैसे- अयोध्या, मिथिला, किष्किंधा, लंका आदि। इन शहरों का वास्तु एवं नगर नियोजन की व्यवस्थितता पढ़कर वैभव और समृद्धि तथा जीवन स्तर की उच्चता का आकलन होता है। इसी प्रकार से महाभारतकार ने महाभारत में भी मथुरा, द्वारिका, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, मगध आदि नगरों का बहुत ही रोचक एवं मनोरम वर्णन किया है, जिससे उस समय के मनुष्यों की सुरूचि का आभास होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में नगरों का तो नामोल्लेख नहीं है किंतु नगर नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए इस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। साथ ही नगर नियोजन की विषयवस्तु को बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से समझाने का प्रयास किया गया है। अपवाह प्रणाली पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है तथा सामाजिक जीवन में आमोद-प्रमोद एवं स्वास्थ्य के संसाधनों पर भी विस्तार से चर्चा की है। कौटिल्य ने अवश्य ही अपने अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र और अन्य नगरों के नियोजन का स्पष्ट वर्णन नहीं किया किंतु उन्होंने रूपरेखा जरूर प्रस्तुत की है। डॉ. पृथ्वीकुमार अग्रवाल ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक प्राचीन भारतीय कला एवं वास्तु में अवश्य अध्याय चार और अध्याय पांच में नगर नियोजन पर विस्तृत प्रकाश डाला है। द्वारका के जो सेटेलाइट से चित्र उपलब्ध हो रहे है वे भी उसकी भव्यता का परिचय देते है। अवंतिका, काशी एवं अन्य नगरों का भी वर्णन प्राचीन संस्कृत साहित्य में बहुतायत से उपलब्ध है और वह भी उनकी भव्यता पर पर्याप्त प्रकाश डालता है।

अयोध्या

रामायणकार ने रामायण में अयोध्या का वर्णन कुछ यूं किया है- ''वह शोभाशालिनी महापुरी बारह योजन लंबी और तीन योजन चौड़ी थी। बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था वह उभयपार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण स्पष्टतया अन्य मार्गो से विभक्त जान पड़ता था। यह राजमार्ग अयोध्या की शोभा में चार चांद लगाने वाला था। इस राजमार्ग पर खिले हुए फूल एवं जल का भरपूर मात्रा में छिड़काव किया जाता था। अयोध्या की तुलना इंद्र की अमरावती से की जा सकती है। अयोध्या के चारों ओर बड़े-बड़े किवाड़ और फाटकों से इसको सुरक्षित किया गया था। अंदर अलग-अलग बाज़ारों का नियोजन था। वह पुरी सभी प्रकार से शोभायमान थी। वहां गगनचुंबी अट्टालिकाएं थी, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों तोपों से वह पुरी व्याप्त थी। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से बहुत ही विशाल थी तथा साखू के वनों से वह चारों ओर से घिरी हुई थी। इसके अतिरिक्त यह चारों ओर से गहरी खाइयों से घिरी थी जिसके कारण यह अनुलंघनीय थी। विभिन्न करदाता सामंत उसकी

सुरक्षा सुनिश्चित किए रहते थे। व्यापार की दृष्टि से वह विभिन्न देशों के व्यापारियों का स्वागत करती थी। अयोध्या के नगर नियोजन में भी महल को केंद्र में रखकर समस्त भवनों का विकास किया गया था।[8]

लंका

लंका के विषय में भी यह वर्णन उपलब्ध है कि इस निर्माण को दानव शिरोमणि ने विश्वकर्मा से कराया था। बाद में यह कुबेर के आधिपत्य में रही तदोपरांत यह पुन: दानवों के शासन में आ गई और रावण ने अपनी रक्ष संस्कृति के प्रचार-प्रसार का केंद्र बनाया। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह सर्वाधिक उपयुक्त स्थान था। रामायण ाकार ने रामायण में इसकी अद्भुत सुंदरता का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है- लंका के चारों ओर गहरी खाइयां खुदी हुई थीं। उनमें उप्पल और पदम आदि कई प्रजातियों के कमल खिले हुए थे। लंका की चारदीवारी सोने की थी तथा पर्वत के समान ऊंचे और शरद-ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी। सुंदरता में वह नगरी आकाश में विचरने वाली नगरी की भांति प्रतीत होती थी। सुंदरता में उसकी तुलना कैलाश पर्वत पर बसी हुई कुबेर की नगरी अलकापुरी से की जा सकती थी।[9] इसमें अनेकानेक बाग-बगीचे-उपवनों की रचना की गई थी। अशोक वाटिका जैसी विशाल वाटिका लंका की शोभा में चार चांद लगाती थी। यहां पर भी रावण का महल केंद्र में था और उसके चारों ओर अन्य प्रासादों का निर्माण किया गया था।

द्वारिका

मथुरा नगरी भी अपने समय के श्रेष्ठ नगरियों में से एक थी किंतु परिस्थितियोंवश श्रीकृष्ण जी को उसका त्याग करना पड़ा। इसलिए उन्होंने विश्वकर्मा से एक सर्वश्रेष्ठ नगरी जिसमें जीवन से संबंधित समस्त वस्तुएं उपलब्ध हों निर्माण करने को कहा तथा उसकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखने का आग्रह किया। विश्वकर्मा ने इन सब बातों का ध्यान रखकर द्वारिका नगरी का निर्माण किया। महाभारतकार महाभारत के ही अंश श्री हरिवंश पुराण में द्वारिकापुरी का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं- सर्वप्रथम विश्वकर्मा ने द्वारकापुरी का मानसिक निर्माण किया। (यानि मानचित्र निर्माण कर श्रीकृष्ण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया।) बाद में उसका वास्तविक रूप तैयार किया। विश्वकर्मा ने द्वारिका के निर्माण में अपने समस्त कौशल का प्रयोग करके उसे अमरावती से भी श्रेष्ठ बना दिया। इसका निर्माण 12 योजन लंबाई एवं 8 योजन चौड़ाई (264 मील, 96 मील) में हुआ था। इसके पूर्व में खेतपर्वत, पश्चिम में सुरक्षा, उत्तर में वेणुभत्त तथा दक्षिण में लतादेष्टा पर्वत इसकी सुरक्षा को उपस्थित थे। ये समस्त पर्वत गहन वनों से आच्छादित थे जो कि इसकी खूबसूरती और सुरक्षा को और बढ़ाने वाले थे। इसमें 50 द्वार थे। इस प्रकार से यह विशालता के साथ-साथ खूबसूरती में भी बेमिसाल थी।[10]

पाटलिपुत्र

भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रचार-प्रसार में जितना योगदान एक लेखक के रूप में मेगास्थनीज ने किया है, इतना संभवत: अन्य किसी ने नहीं किया होगा। भारत में उसने जितना भी समय बिताया उसमें से अधिकांश पाटलिपुत्र में बिताया। संभवत: जितनी व्यापक समझ वह बना पाया इतना अन्य कोई नहीं। पाटलिपुत्र के विस्तार के विषय में लिखते हैं कि यह गंगा के किनारे बसी हुई थी। इसकी लंबाई 9 मील एवं चौ. 2 मील थी। चारों ओर खाइयां थीं। शहर के 64 द्वार थे और चाहरदीवारी को 570 खूबसूरत मीनारों से सुसज्जित किया गया था। चंद्रगुप्त का महल अद्भुत घर था। ग्रीस लेखकों ने उसकी बहुत तारीफ की है। महल के साथ ही खूबसूरत पार्क था जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता था। महल में छायादार वृक्षों की कतारें थीं जो कि आपस में गुंथी हुई थीं। ये वृक्ष संपूर्ण भारत और उससे बाहर से भी थे। इस कारण यहां एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत हो गया था। इन वृक्षों पर अनेकानेक प्रकार के पक्षी चहकते रहते थे और एक-दूसरे स्थान पर पूरी स्वतंत्रता से उड़ान भर सकते थे। महल में खूबसूरत तालाब भी था जिसमें खूबसूरत मछलियां थीं। मछलियों का तालाब में किलोल करना एक अदभुत नजारा प्रस्तुत करता था।[11]

नगर की सफाई और नागरिकों के कर्त्तव्य

नगर और गांवों की साफ-सफाई के लिए नागरिकों में जागरूकता अनिवार्य है। यह ठीक है कि ये समस्त कार्य किसी भी सभ्य समाज में राज्य के ही नियंत्रण में संभव हों तो स्पर्द्धा उचित है, किंतु राज्य अपनी भूमिका तब तक ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर सकता जब तक समाज उसमें अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निर्वहन करता। कौटिल्य इसका पालन सख्ती से कराने की वकालत करते हैं चाहे इसके लिए दंड ही क्यों न देना पड़े।

कौटिल्य इस संबंध में विस्तार से वर्णन करते हैं कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन किस प्रकार से करना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पूरा एक अध्याय ही नागरिकों के कार्य के नाम से दिया है। वे इसमें राज्य और नागरिकों के कार्य का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। जैसे कि समाहर्ता (अधीक्षक) की भांति नागरिक अधिकारी भी नगर के प्रबंध की चिंता करे, धर्मशाला प्रबंधक को चाहिए कि वह धूर्त, पाखण्डी मुसाफिरों को गोप की अनुमति से ही टिकाए, किंतु जिन तपस्वियों या श्रोत्रियों को वह स्वयं जानता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर भी टिका सकता है। इसी तरह, जान पहचान के कारीगरों को व्यवसाई अपने यहां ठहरा सकता था किंतु देश काल के विपरीत आचरण करने वाले व्यक्ति की सूचना तुरंत नागरिक को देनी होती थी। यह व्यवस्था थी कि मद्य-मांस बेचने वाले, होटल वाले और वेश्याएं अपने-अपने परिचितों को अपने घर ठहरा सकते हैं किंतु यदि कोई अपनी हैसियत से अधिक खर्चे तो उसकी सूचना तुरंत स्थानिक को दी जावे। इसी तरह कौटिल्य ने कहा कि गलियों तथा बाज़ारों में और चौराहों, नगर के प्रधान द्वारों, खजानों कोष्ठागारों, गजशालाओं और अश्वशालाओं में पानी से भरे हुए एक हजार घड़ों का हर समय प्रबंध रहना चाहिए। वहीं सड़क पर मिट्टी या कूड़ा-करकट डालने वाले व्यक्ति को पण का आठवां हिस्सा (1/8 पण) दण्ड दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति गाड़ी, कीचड़ या पानी से सड़क को रोके उसे 1/4 पण दण्ड दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति राजमार्ग को इस प्रकार गंदा करे या रोके उसे दुगुना दण्ड दिया जाना चाहिए।

मध्य/आधुनिक काल में शहरी नियोजन

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह ध्यान में आता है कि भारत में पर्याप्त लंबे समय तक प्राचीन स्थापत्य कला का प्रभाव रहा और यह कला प्राय: भारत के परिवेश के अनुरूप ही विकसित हुई तथा इस पर संस्कृत एवं संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु 12 वीं सदी से विदेशी आक्रांताओं के

आक्रमण में तेजी आने के बाद इसमें परिवर्तन आने प्रारंभ हुए। ये परिवर्तन उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यह वह कालखंड है जिसमें संस्कृति और सम्यतागत स्थापत्य कला का विकास तेजी से हुआ है।

मध्यकाल में अधिकांशत: भारतवर्ष में मुगल वंश का शासन रहा। इस दौरान नगरों की प्रमुख विशिष्टता उनके अंदर महल, किलों एवं इबादतगाहों आदि ईमारतों के रूप में दिखती है। मुगलकाल के स्थापत्य ने दैनंदिन जीवन के स्थापत्य को प्राय: प्रभावित नहीं किया। जन सामान्य के आवास परंपरागत दृष्टिकोण से निर्माण करने का अभ्यास रहा। किले, इबादतगाह, सुरंग महल आदि पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ध्यान से देखने पर यह भी समझ में आता है कि इस काल में जो किले और महल बने हैं उन पर निर्माण सामग्री और स्थापत्य को छोड़कर शेष स्वरूप भारतीय भवन निर्माण कला वाला ही रहा है। यथा- दिल्ली का किला, आगरा स्थित सिकंदरा तथा फतेहपुर सीकरी आदि-आदि। हां, यह अवश्य परिलक्षित होता है कि जो स्मारक इन्होंने अपने संबंधियों की यादगार में निर्मित करवाए, जरूर मुगल स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने प्रतीत होते है और स्थापत्य पर भी मुस्लिम कारीगरों की छाप दिखती है यथा- आगरा स्थित एतमाउद्दौला, सिकंदरा स्थित मरियम टांम्ब, दिल्ली स्थित सफदर जंग का मकबरा, हुमायुं का मकबरा आदि-आदि।

जब भी स्मार्ट शहर यानी बुद्धिमत्ता के साथ बनाए गए सुनियोजित शहर की बात की जाती है तो प्राचीन काल की कई नगरी हमारे ध्यान में आती हैं। अंग्रेजों के आने के बाद भी कई शहर सुनियोजित ढंग से बसाए गए और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भी इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्यकाल के स्मार्ट शहरों के बारे में बात कम ही होती है, जबकि वास्तव में वे शहर ही स्मार्ट सिटी की अवधारणा के सबसे करीब आते हैं। भारत में फतेहपुर सीकरी, पुडुचेरी और जयपुर आदि ऐसे ही शहर हैं। आगे हम इन शहरों के बारे में एक एक कर देखेंगे।

फतेहपुर सीकरी

सीकरी भारत में मध्यकाल का पहला सुनियोजित या स्मार्ट शहर था। इसकी बुनियाद 1571 में अरावली पर्वत श्रेणी के ऊपरी हिस्से में एक बड़ी झील के किनारे रखी गई थी। शहर को बसाने का काम बाबर के पौत्र अकबर ने किया, जिन्होंने अपनी राजधानी आगरा से हटाकर सीकरी बनाई और 13 साल तक यहीं से राज काज किया। वास्तव में यह मुगलों का पहला स्मार्ट शहर है। इसमें ढलवां पहाडियों पर तीन मुख्य परिसर बनाए गए। सबसे ऊपरी परिसर में जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। बीच के परिसर में शाही दरबार, रनिवास, शाही बाज़ार और मीना बाज़ार आदि बने। सबसे निचले परिसर में अनूप तालाब, पंचमहल, ख्वाबगाह बनाए गए। तीनों परिसर उत्तर से दक्षिण दिशा में इस तरह बनाए गए कि उनका मुंह पूर्व अथवा उत्तर की ओर ही है। तीनों सीध में इस तरह बनाए गए कि गर्मी से बचाने के लिए उनके बीच पर्याप्त जगह है। इसके साथ ही यहां इमारतें बनाने के लिए लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ, जो ठंडा रहता है। सीकरी की इमारतों में मुगल स्थापत्य से अधिक भारतीय स्थापत्य का प्रभाव दिखता है और छज्जों, झरोखों तथा छतरियों वाली कुछ इमारतें तो मंदिर जैसी दिखती हैं।

सीकरी में जल निकासी और जलापूर्ति का बेहद चौंकाने वाला और अद्भुत प्रबंध है। पहाड़ी के ऊपर बसे परिसरों और महलों में पानी की कमी न हो, इसके लिए सीकरी के दोनों ओर बावली बनाई गईं और बेहद उम्दा प्रणाली से पानी ऊपर तक भेजा गया। स्मार्ट शहर की अवधारणा के अनुसार इसमें सभी तबकों का खयाल रखा गया। शिल्प को बढ़ावा देने के लिए रेशम, ऊन और सूती कपड़ों, कालीन तथा दरी के लिए कारखाने खुलवाए गए।

सीकरी में जल निकासी और जलापूर्ति का बेहद चौंकाने वाला और अद्भुत प्रबंध है। पहाड़ी के ऊपर बसे परिसरों और महलों में पानी की कमी न हो, इसके लिए सीकरी के दोनों ओर बावली बनाई गईं और बेहद उम्दा प्रणाली से पानी ऊपर तक भेजा गया। स्मार्ट शहर की अवधारणा के अनुसार इसमें सभी तबकों का खयाल रखा गया। शिल्प को बढ़ावा देने के लिए रेशम, ऊन और सूती कपड़ों, कालीन तथा दरी के लिए कारखाने खुलवाए गए। सोने, चांदी, जेवरात, चमड़े, लकड़ी के शिल्पकारों के साथ ही इत्र बनाने के कारखाने भी सीकरी में खोले गए, जिससे पड़ोस के शहर आगरा के साथ यह व्यापार का केंद्र बना।

पुडुचेरी

सुदूर दक्षिण में पुडुचेरी मध्यकाल में दूसरा स्मार्ट भारतीय शहर है। इसे फ्रांसीसी उपनिवेश के प्रमुख शहर के तौर पर 1674 में बसाया गया था। इसे फ्रांस तथा भारत की स्थापत्य कला का मेल बताया जाता है। लेकिन वास्तव में इस शहर का मूल नक्शा फ्रांसीसियों से भी पहले हॉलैंड से आए डच व्यापारियों और शासकों ने तैयार किया, जो आज भी बरकरार है। इस शहर का नक्शा तैयार करने वाले डच वास्तुकार जैकब वर्बरगोम्स ने इसे आयताकार ब्लॉकों में बांटा, जिनके बीच में सीधी सड़कें थीं और ये सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई चौराहे बनाती थीं। चूंकि डच व्यापारी थे, इसलिए वे इस शहर को व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शहर में प्रत्येक व्यावसायिक समुदाय के रहने के क्षेत्र सुनिश्चित किए। शहर इतना सुनियोजित था कि प्रत्येक जाति और व्यवसाय की गलियां तय थीं यानी बुनकरों, व्यापारियों, किसानों, दस्तकारों और ब्राह्मणों की अलग-अलग गलियां थीं। इतना ही नहीं वहां श्वेत समुदाय और अश्वेत अर्थात भारतीय समुदाय के रहने के स्थान भी अलग-अलग थे।

जयपुर

गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर भी करीब 300 साल पहले बसाया गया स्मार्ट शहर है। इसकी बुनियाद 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने रखी थी। उनकी राजधानी आमेर में थी, लेकिन बहुत ऊंचाई पर बसे होने के कारण वहां आवागमन में परेशानी होती थी और पानी की किल्लत से जूझना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने 11 किलोमीटर दूर जयपुर को बसाया। वास्तव में जयपुर पूरी तरह भारतीय शैली वाला पहला ऐसा शहर है, जिसका बाकायदा नक्शा बनाया गया। शहर की डिजाइन का जिम्मा विद्वान बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य को सौंपा गया। भट्टाचार्य ने हिंदू रीति के अनुसार भवन निर्माण के नियम तय करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ 'शिल्प शास्त्र' के आधार पर इस शहर

का खाका तैयार किया। उन्होंने शहर को 9 आयताकार ब्लॉकों में बांटा, जिनमें 7 ब्लॉक सामान्य जनता के लिए और बाकी 2 ब्लॉक महल तथा प्रशासनिक इमारतों के लिए रखे गए। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे शहर को ऊंची दीवारों से घेरा गया और 7 प्रवेश द्वार बनाए गए। शिल्प शास्त्र और वास्तुकला के नियमों के अनुसार शहर में सड़कें और चौक बने। मुख्य सड़कों के अलावा प्रत्येक ब्लॉक में भी सड़कों का जाल बुन दिया गया। खास बात है कि उस समय भी जयपुर में प्रत्येक सड़क खूब चौड़ी बनाई गई थी ताकि भविष्य में भी आवागमन में दिक्कत न हो। विभिन्न प्रकार के बाज़ार भी जयपुर में बसाए गए। वास्तु का इतना अधिक ध्यान रखा गया है कि आज भी जयपुर की सभी सड़कों और बाज़ारों का रुख पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण है। दुनिया के शायद किसी भी शहर में बाज़ार इतने व्यवस्थित नहीं दिखेंगे, जितने जयपुर में हैं। यहां झालानियों का रास्ता, ठठेरों का रास्ता, खजाने वालों का रास्ता, हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाज़ार, त्रिपोलिया बाज़ार आदि पारंपरिक बाज़ारों का ही संकेत करते हैं, जो शहर को बसाते वक्त बनाए गए थे। ❑

संदर्भ

1. कौटिल्य अर्थशास्त्र, 2/1/4, चौखंबा प्रकाशन
2. कौ. अर्थशास्त्र, 2/1/5, चौखंबा प्रकाशन
3. वा. रा. बालकांड, 5/13, गीता प्रेस, गोरखपुर
4. वा. रा. अध्योध्याकांड, 100/53, गीता प्रेस, गोरखपुर
5. महा. सभापर्व, 31/74,38/30, गीता प्रेस, गोरखपुर
6. मनुस्मृति, 7/70
7. कौ. अर्थशास्त्र, दुर्गनिवेश: 2/4/3-1-2-3-9, पृ. -91-93, चौखंबा प्रकाशन
8. वा. रा.-सुंदरकांड, 19-23
9. हरिवंशपुराण, 58वां अध्याय, 45-50
10. नरायण सिंह समोता India as described by Megasthomas, Delhi 1978, पृ.-61-62
11. कौ. अर्थशास्त्र, 2/35/3, चौखंबा प्रकाशन

क्या आप जानते हैं?

ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सेवाएं

ओवर-द-टॉप (ओटीटी) उन एप्लिकेशनों तथा सेवाओं को कहते हैं, जो इंटरनेट पर उपलब्ध होती हैं और उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर सोशल नेटवर्क, सर्च इंजन, अमेच्यर वीडियो एग्रीगेशन, संगीत डाउनलोड साइट तथा मुफ्त गेमिंग डाउनलोड वेब साइट जैसी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराती हैं। वे पारंपरिक सेवा प्रदाता के विकल्प के रूप में कार्य करती हैं। ओटीटी प्रदाता दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के बुनियादी ढांचे का प्रयोग कर अपने ग्राहकों तक पहुंचते हैं और उन्हें उत्पाद तथा सेवाएं देते हैं। इस प्रकार वे केवल धन ही नहीं कमाते बल्कि टीएसपी द्वारा दी जाने वाली परंपरागत सेवाओं को कड़ी टक्कर भी देते हैं। ये एप्स ई-कॉमर्स साइटों और बैंक जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ भी मुकाबला करते हैं।

वे दिन बीत गए, जब केवल डेस्कटॉप अथवा लैपटॉप कंप्यूटर होते थे और उन्हें इंटरनेट से जोड़ा जाता था। आज ये एप्लिकेशन इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं और इंटरनेट से जुड़े विभिन्न उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, फैबलेट, ई-बुक्स और स्मार्ट टीवी पर इंटरनेट के माध्यम से किसी भी समय, कहीं से भी इनका ऑनलाइन प्रयोग किया जा सकता है।

ओटीटी में हाल के वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। फोन के मूल्य घटने और बाजार में अनगिनत प्रकार के फोन उपलब्ध होने तथा टीएसपी द्वारा एक्सेस नेटवर्क को बेहतर बनाए जाने के कारण स्मार्ट फोन की लगातार बढ़ती पैठ इस वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। सामग्री का डिजिटलीकरण बहुत सामान्य हो गया है, जिससे सूचना के संरक्षण और पुनरुत्पादन के स्तर में तथा उसके वितरण की लागत में कमी आई है, जिससे ऑनलाइन सामग्री की आपूर्ति में विस्फोटक वृद्धि देखी गई है। अपने नए कारोबार के विकास के लिए ये ओटीटी कंपनियां वर्तमान टीएसपी द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्रॉडबैंड नेटवर्कों का प्रयोग करती हैं। चूंकि इन ओटीटी एप्लिकेशनों ने ऑनलाइन सामग्री में वृद्धि कर दी है, इसलिए सूचना के बढ़े हुए यातायात को संभालने के लिए अब अधिक तेज ब्रॉडबैंड की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके लिए इन टीएसपी को नेटवर्क के उन्नयन में भारी निवेश करना होगा।

दुनिया भर में सरकारों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच ओटीटी सेवाओं के नियमन के संबंध में बहस जारी है। इस बहस को देखते हुए ट्राई ने ओवर-द-टॉप सेवाओं के लिए नियामकीय व्यवस्था पर परामर्श पत्र जारी किया है, सेवा प्रदाताओं, ओटीटी प्रदाताओं तथा विभिन्न हितधरकों के विचारों तथा (नेटवर्क न्यूट्रैलिटी समेत) संबंधित मुद्दों, नेटवर्क न्यूट्रैलिटी एवं (संचार एवं गैर-संचार) ओटीटी के नियमन पर गौर करेगा।

प्रस्तुति: वाटिका चंद्रा, उपसंपादक (योजना, अंग्रेजी) ईमेल: vchandra.iis2014@gmail.com

योजना
आगामी अंक

अक्टूबर 2015

स्किल इंडिया कार्यक्रम

सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी कदम

आर सी राजामणि

अब तक नयी सरकार की ओर से पेश किए गए दो बजटों से उसका आर्थिक और सामाजिक एजेंडा स्पष्ट होता है। सरकार अटल पेंशन योजना जैसी अपनी सर्वोत्कृष्ट योजनाओं के लिए भी संसाधन उपलब्ध कराएगी और उनके भिन्न-भिन्न रूपों का आरंभ किया जाएगा। किसी भी विकास कार्यक्रम के पर्याप्त और सतत परिणामों के लिए सामान्यतः एक लंबे और धैर्यपूर्ण परीक्षण की आवश्यकता होती है। सत्तारूढ़ होने के 15 महीने के बाद से सरकार का अभी तक का लेखा-जोखा काफी हद तक उत्साहजनक है और भविष्य में बेहतर परिणाम देने वाला दिखाई पड़ता है

मई 2014 से केंद्र में सत्तारूढ़ हुई नई सरकार ने सामाजिक कल्याण और समावेशी आर्थिक विकास के नवीन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है। खास तौर पर बालिकाओं, महिलाओं और बाल विकास के लिए बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और मूलभूत शिक्षा प्रदान करने की योजना है। इसमें सबसे बड़े अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समुदाय के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए विशेष योजना है।

सरकार ने समेकित बाल विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मनरेगा के लिए 40,882 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय खर्च के लिए संसद से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

अतिरिक्त निधि में से अधिकांश आईसीडीएस को जाएगा जो 8 करोड़ 50 लाख बच्चों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराती है। मुख्य स्वास्थ्य विभाग के बजट में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। जबकि एचआईवी/एड्स के बजट में नाममात्र की वृद्धि होगी। एचआईवी रोकथाम कार्यक्रम कई राज्यों में अनुदान के अभाव से ग्रस्त है।

सामाजिक सुरक्षा

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को मई में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया। अब तक 7 करोड़ 84 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकरण कराया है। वहीं 2 करोड़ 70 लाख प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और 4 करोड़ 69 लाख अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। वर्तमान तक मात्र 11 प्रतिशत जनसंख्या को ही पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की जा सकी है। जबकि केवल 20 प्रतिशत लोग बीमाकृत हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं के अंतर्गत लाकर स्थिति में सुधार करना चाहती है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत एक वर्ष में 16 करोड़ 73 लाख खाते खोले गए, जिसमें 19,990.52 करोड़ रुपये की राशि खातों में जमा कराई गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में शून्य जमा खातों की संख्या जो पहले 75 प्रतिशत थी वह गिरकर 52 प्रतिशत आ गई है। योजना के तहत खाताधारकों को 8 जुलाई 2015 तक 14 करोड़ 86 लाख रूपये के कार्ड प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा 10 जुलाई 2015 तक 114 दावे किए गए जिसमें से 54 का अभी तक निपटारा किया जा चुका है। पेंशन योजना के अंतर्गत 4 लाख 69 हजार लोगों ने पेंशन की मांग की, जिसमें से 3 लाख 48 हजार ने स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त कर ली है। योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 14 करोड़ 91 लाख की राशि जमा की गई है।

शिक्षा

शिक्षा में उल्लेखनीय कदमों में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृति के प्रावधान और उच्च शिक्षा के संस्थानों को गांवों के साथ जोड़ना शामिल है। नए कदमों की महत्वपूर्ण विशेषता है सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक उपकरणों के सर्वोतम उपयोग की कोशिश के लिए ध्यान केंद्रित करना। उदाहरण के लिए विभिन्न विषयों और प्रसंगों पर किताबों और ई-कंटेंट के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की परियोजना और दूसरा एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करना जिसके माध्यम से आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षक मुफ्त ऑनलाइन कोर्स प्रदान करें।

लेखक द स्टेट्समैन में संपादकीय सलाहकार एवं स्वतंत्र पत्रकार हैं। ईमेल: rajamanirc@gmail.com

सरकार ने 'सक्षम' नाम से एक योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में पूर्वस्नातक स्तर के कोर्स और डिप्लोमा करने हेतु प्रति वर्ष 30,000 रूपये की छात्रवृति प्रदान की जाती है।

बालिकाओं के लिए 'उड़ान' नाम की विशेष योजना, परामर्श और छात्रवृति की योजना है। जिससे प्रतिभाशाली बालिकाओं को आसानी से स्कूल शिक्षा से तकनीकी शिक्षा तक ले जाया जा सके। इसका लक्ष्य वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर सभी को मुफ्त ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराकर गणित और विज्ञान के शिक्षण व अधिगम को समृद्ध करना एवं परिवर्धित करना है।

हाल ही में मंजूर हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) शिक्षाशास्त्र के बेहतर प्रशिक्षित अनुदेशक, पाठ्यक्रम में सुधार पर केंद्रित और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली सर्वोत्कृष्ट योजना है। प्रशिक्षण में सरल कौशल, व्यक्तिगत तैयारी और व्यवहारवादी परिवर्तन शामिल हैं। कौशल और उद्योग उपक्रम विकास की राष्ट्रीय नीति भी इस दिशा में उठाए गए कदमों के सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाली है। यह नीति विकास को बढ़ावा देने और गुणवतापूर्ण श्रमशक्ति तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश की आधारशिला रखेगी। इसने वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

जिन युवाओं के पास विद्यालय छोड़ने का औपचारिक प्रमाणपत्र नहीं है उनको बेहतर रोजगार प्रदान करने हेतु अल्पसंख्यक युवाओं को सक्षम बनाने वाली समेकित शिक्षा और आजीविका योजना 'नई मंजिल' का शुभारंभ इसी वर्ष किया जाएगा। इससे आगे बढ़कर पारसियों की सभ्यता और संस्कृति के प्रदर्शन के लिए सरकार 2015-16 में एक प्रदर्शनी, 'दि एवरलास्टिंग फ्लेम' को समर्थन देगी।

मेक इन इंडिया

'मेक इन इंडिया' अभियान देश में 'प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद' को प्रोत्साहन देने वाला है क्योंकि प्रत्येक राज्य बेहतरीन विनिर्माण सुविधाओं की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए और विनिर्माण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार सुदूर उत्तर-पूर्वी राज्य सिक्किम में इसके जैविक उत्पादों पर आधारित नीति बनाने में व्यस्त है जिससे डिब्बाबंद जैविक उत्पादों का उत्पादन किया जा सके।

कारोबार में सुविधा

सरकार ने व्यापक आर्थिक सुधारों के ढेर सारे कदम उठाए हैं। कैबिनेट के महत्व की पुनर्स्थापना, योजना आयोग को भंग करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन, निम्न प्रतिलाभ की तेल विपणन कंपनियों से मुकाबला करने के लिए डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करना, खाद्य कीमतों को शांत करने के लिए प्रचुर खाद्य भंडारों को उपलब्ध कराना, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाना व रेल एवं सुरक्षा क्षेत्र को एफडीआई के लिए खोलना, कोयला खदानों की नीलामी और स्पेक्ट्रम आवंटन की नीलामी में पारदर्शी प्रणाली अपनाना महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल हैं।

नेशनल इंफ्रास्ट्रकचर फंड का निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निधि के केंद्रीय संसाधनों का उपयोग या इसकी तुलना में बाज़ार से निधि ऋण लेना और इनको आधारभूत ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए असरदार तरीके से इस्तेमाल करना शामिल है।

सरकार ने व्यापक आर्थिक सुधारों के ढेर सारे कदम उठाए हैं। कैबिनेट के महत्व की पुनर्स्थापना, योजना आयोग को भंग करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन, निम्न प्रतिलाभ की तेल विपणन कंपनियों से मुकाबला करने के लिए डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करना, कोयला खदानों की नीलामी और स्पेक्ट्रम आवंटन की नीलामी में पारदर्शी प्रणाली अपनाना महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल हैं।

सरकार ने एनएचडीपी फेस 6 के अंतर्गत डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) प्रणाली के तहत 16680 करोड़ के अनुमानित खर्च से लगभग 1000 किमी के एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना को अनुमोदन दिया है। परिवहन सघनता और वाणिज्य संभावनाओं को देखते हुए प्रयोजना को प्राथमिकता दी जाएगी।

वर्ष 2015 के केंद्रीय बजट में भी भारत में सुगमता से व्यापार करने के कदमों की घोषणा की गई। बजट में एक सुधार नियामक कानून पेश करने का प्रस्ताव रखा गया। जो आधारभूत ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों को सशक्तता के निकट लेकर आएगा। इससे बंदरगाह, बिजली, सड़क और एयरपोर्ट जैसे कई तरह के कारोबार करने वाली आधारभूत ढांचे वाली कंपनियों को लाभ होगा।

बजट ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय निगमों की प्रक्रियाओं को पहले से सरल बना दिया है। विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेशों की विशिष्टताओं को पहचानकर ऐसा किया गया, खासकर निवेश श्रेणी के अंतर्गत आने वाले विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के संबंध मे ऐसा किया गया।

शासन की व्यवहारिक पद्धति से 70 अरब डॉलर से ज्यादा के निवेश वाले 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट का शीघ्रता से निपटारा सुनिश्चित हुआ है। इसने 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट की शीघ्र अनुमोदन में सहायता की है जिसमें 70 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के निवेश का अनुमान है।

बिजली की मांग को पूरा कर पाना एक बहुत बड़ा कार्य है क्योंकि न केवल औद्योगिक और कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए, बल्कि बेहतर होते जीवन स्तर और 30 करोड़ से अधिक संख्या वाले व बढ़ते हुए मध्यम वर्ग घरेलू उपभोग के लिए ज्यादा बिजली की आवश्यकता होगी। सरकार आगामी पांच वर्षों में आधारभूत ढांचे के विकास में 10 खरब डालर खर्च करेगी। ऐसे में उम्मीद है कि ऊर्जा क्षेत्र में कम से 300 अरब खर्च करे।

सरकार ने वर्ष 2019 तक देशभर में अनवरत दिन बिजली उपलब्ध कराने की व्यापक योजना को आरंभ किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश में 6 लाख गांवों में से 1 लाख 25 हजार अन्य गांव भी ग्रिड से जुड़ जाएंगे। ये 1 लाख 25 हजार गांव अभी तक ग्रिड से जुड़े हुए नहीं हैं।

थर्मल पॉवर, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा और अन्य ग्रीन ऊर्जा उत्पादन में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। बिजली के संचार और वितरण को सशक्त करने, फीडरों को अलग करने और बिजली को मापकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।

उत्तर-पूर्वी ऊर्जा व्यवस्था में सुधार की योजना और उत्तर-पूर्वी राज्यों में संचार व वितरण को सशक्त करने की समग्र योजना को अनुमोदन देकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

निःसंदेह भारत, विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उम्मीद है कि वर्ष 2020 तक देश विश्वभर में विनिर्माण के लिए सबसे पसंदीदा 3 गंतव्यों और सबसे ज्यादा तेजी से विकसित होने वाली 3 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो जाएगा। सरकार का योजनाबद्ध तरीके से तैयार एजेंडा सचमुच इस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करेगा। ❑

स्मार्ट सिटी: अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण

शिवानंद द्विवेदी

दुनिया में शहर ऐसे मिल जाएंगे जो तकनीक का उपभोग तो कर रहे हैं लेकिन तमाम बुनियादी सावधानियों को अमल नहीं ला पा रहे। स्मार्ट सिटी की वर्तमान अवधारणा का आशय महज विकास के अंधाउत्साह से नहीं बल्कि प्रकृति और समाज के बीच संतुलन का है। तकनीक का उपयोग जितना सुविधा-संपन्न समाज के लिए किया जा रहा है अगर उतना ही प्राकृतिक जवाबदेही के साथ भी किया जाए तो हम जिस बसावट के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे वो स्वतः स्मार्ट होगा। भारत भी इस दिशा में दुनिया के तमाम देशों से सीख लेकर, तकनीक लेकर और विकास की समझ लेकर स्मार्ट सिटी की योजना की तरफ आगे बढ़ने को तैयार दिख रहा है। इसमें कोई शक नही कि भारत सक्षम भी है और यहां संभावना भी है

बसावट की बुनियाद पर अगर किसी भू-भाग का अध्ययन करें तो मूलतया दो रूप सामने आते हैं, गांव एवं शहर। भौगोलिक मानदंडों पर गांवों की बसावट का स्वरूप परंपरागत है जबकि शहर की अवधारणा नगरीकरण से होते हुए विकास के क्रम में समय और समाज की मांग के अनुसार बदलती रही है। दुनिया के लगभग हर देश में समाज की बसावट का प्रारंभिक स्वरूप गांव जैसा ही रहा होगा जो बाद में समाज की जरूरतों के अनुरूप नगर अथवा शहर में तब्दील हुआ होगा। भारत ने भी समय के साथ-साथ इस परिवर्तन को देखा है। भारत में भी शहरों का विकास तेजी से हुआ है और हो भी रहा है। बीसवीं सदी में जब तकनीक और विज्ञान ने तरक्की की तो शहरीकरण के स्वरूप में भी बदलाव आया। परिणामस्वरूप अब इक्कसवीं सदी के शुरुआत में बात केवल 'शहर' तक नहीं सिमटी है बल्कि अब बात 'स्मार्ट शहरों' की होने लगी है।

सवाल है कि स्मार्ट सिटी होने का मानदंड दुनिया ने क्या तय किया है और क्या वाकई इन मानदंडों पर किसी शहर का विकास होना हर दृष्टिकोण से उचित है? इसमें कोई शक नहीं कि तेजी से शहर तो बस जाते हैं लेकिन पर्यावरण, मानव जीवन का स्तर, रहन-सहन, आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं कहीं शहरीकरण के सिमटते सामाजिक दायित्वबोध में पीछे छूट जाती हैं। कहीं न कहीं इन तमाम बिंदुओं का ख्याल रखते हुए जिस शहर का निर्माण किया जाए वही स्मार्ट शहर कहा जा सकता है। दुनिया के कई ऐसे शहर है जो इन मानदंडों को न सिर्फ पूरा करते हैं बल्कि खुद किसी खास प्रयोग की सफलता के लिए जाने भी जाते हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में बसाए गए इन कुछ शहरों को उदाहरण के तौर पर रखकर इस बात का मूल्यांकन किया जा सकता है कि स्मार्ट सिटी हो तो कैसा हो?

अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात दौरा किया था। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है 'मसदर'। मसदर की गिनती दुनिया के प्रमुख स्मार्ट शहरों में की जाती है। मसदर दुनिया का पहला 'जीरो-कार्बन' शहर है। जीरो-कार्बन शहर का आशय उस बसावट से है जिस शहर अथवा बसावट में यातायात से लेकर घरेलू रसोई तक में कार्बन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हो और सुविधाओं के अन्य विकल्पों को विकसित कर लिया गया हो। इस लिहाज से देखा जाए तो मसदर तेजी से जीरो-कार्बन शहर के रूप में विकसित हुआ है। मसदर में कार्बन उगलने वाली कार और गाड़ियां नहीं हैं। इस शहर में न तो कूड़ा है और न ही किसी तरह का धुआं। यहां बिना ड्राइवर की गाड़ियों में सैर की जा सकती है। इस शहर में ऊर्जा सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ली जा रही है और इसके लिए 54 एकड़ में 88 हजार सौर पैनल लगाए गए हैं। पानी एवं घरेलू सुविधाओं के लिहाज से भी मसदर ने कई बेहतरीन प्रयोग किए हैं। मसदर को बिजली स्विच एवं घरेलू पानी सप्लाई को भी सेंसर्स तकनीक पर विकसित करने की दिशा में प्रयास किया गया है। प्राकृतिक हवाओं को कैसे ठंडी

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं विकास से जुड़े मुद्दों पर सतत् लेखन। देश के दर्जनों राष्ट्रीय समाचार-पत्रों के लिए लेखन। राजनीतिक-शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई। ईमेलः saharkavi111@gmail.com

हवा के रूप में घरों तक पहुंचाया जाए इसका भी ख्याल विंड टॉवर के रूप में विकसित करके रखा गया है। प्रधानमंत्री ने वहां प्राइवेट रैपिड ट्रांजिट (पीआरटी) व्यवस्था को देखते हुए कार्बन-मुक्त कार का सफर भी किया। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण एवं रहन-सहन के लिहाज से मसदर के रूप में एक स्मार्ट सिटी का निर्माण किया है।

स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे शहरों की सूची में एक महत्वपूर्ण नाम दक्षिण कोरिया का सांगडो शहर है। इसे आधुनिक विश्व का पहला स्मार्ट शहर भी माना जाता है। आज से ठीक एक दशक पहले 2005 में समुद्री तट पर इस शहर को बसाने का काम शुरू हुआ था। इस शहर को बसाने का कुल बजट लगभग 35 बिलियन डॉलर आंका गया था। इस शहर की विशेषता ये है कि इस पूरे शहर को एक सूचना प्रणाली से नियंत्रित करने और जोड़कर रखने की दिशा में विकसित किया गया है। यही वजह है कि से इसे बाद में 'बक्से में बंद शहर' भी कहा जाने लगा। सॉन्गडो में सभी चीजों में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा हुआ है। मसलन अगर देखा जाए तो स्वचालित सीढ़ियां, यानी एस्केलेटर, आदि सुविधा संसाधन तभी चलेंगे जब उन पर कोई खड़ा होगा। सभी घरों में टेलिप्रेजेंस सिस्टम लगाया गया है। तकनीक और सूचना प्रणाली के जरिए ही घर के ताले तक नियंत्रित होंगे। घर को गर्म रखने के लिए हीटिंग प्रणाली आदि सभी पर ई-नेटवर्क के जरिए कंट्रोल रखा जा सकता है। यहां तक की स्कूल, अस्पताल और दूसरे सरकारी दफ्तर भी नेटवर्क पर हैं। तकनीक की दृष्टि से ये शहर एक नजीर है। इस शहर को तकनीक सिस्को दे रही है और ये विकास के अपने अंतिम दौर में है। ऐसा अनुमान जताया गया है कि यहां 65,000 लोग रह रहे हैं और 3,00,000 लोग अलग-अलग वजहों से इस शहर से जुड़े हुए हैं।

स्पेन का बार्सिलोना दुनिया के उन शहरों में शुमार हैं जो स्मार्ट सिटी मानदंडों को पूरा करते हैं। बार्सिलोना इस लिहाज से खास है क्योंकि वहां तकनीक को हर स्तर पर उपयोग करने की दिशा में सफल प्रयोग किया जा रहा है। बार्सिलोना में कूड़ा उठाने से लगाए बसों के रूट आदि को सेंसर तकनीक से जोड़ने की दिशा में पहल हो चुकी है। बार्सिलोना को लेकर यह दावा भी किया जाता है कि यह दुनिया का सबसे आगे बढ़ चुका स्मार्ट शहर है।

स्मार्ट शहरों की अगर बात हो तो ब्राजील के चर्चित शहर रियो डे जेनेरो का नाम जरूर आता है। यह शहर आगामी 2016 में ओलंपिक की मेजबानी भी करने वाला है। ओलंपिक के लिहाज से इस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने की तैयारी काफी समय से चल रही है। इस दिशा में काम बढ़ाते हुए वहां के कॉर्पोरेट एवं सरकार ने शहर की तीस एजेंसियों को एक नेटवर्क पर जोड़ने की दिशा में अनोखा कदम उठाया है जिससे किसी भी स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। सूचना एवं प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए आधुनिक प्रणाली तैयार की है एवं मौसम और ट्रैफिक आदि के लिए विशेष प्रकार के तकनीकी विकल्प विकसित किए गए हैं। हालांकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि शहर को विकसित करने की दिशा में आम लोगों का सहयोग एवं सहभागिता नहीं ली जा रही है। इस शहर के आम लोग भी आवासीय विकास की दिशा में आदर्श रिहायश के तमाम विकल्पों पर काम कर चुके हैं। घरों के डिजाइन और उन्हें बनाने के आसान तरीके इंटरनेट पर उपलब्ध कराए गए और लोगों ने इस काम में भरपूर सहयोग किया। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ब्राजील का यह शहर सरकार, कॉर्पोरेट एवं जनभागीदारी के आपसी सामंजस्य से स्थापित हो रहा एक बेहतरीन शहर है जहां उन तमाम बिंदुओं गौर किया गया है जो एक स्मार्ट सिटी के मूल मानदंड में जरूरी हैं।

स्पेन का बार्सिलोना दुनिया के उन शहरों में शुमार हैं जो स्मार्ट सिटी मानदंडों को पूरा करते हैं। बार्सिलोना इस लिहाज से खास है क्योंकि वहां तकनीक को हर स्तर पर उपयोग करने की दिशा में सफल प्रयोग किया जा रहा है। बार्सिलोना में कूड़ा उठाने से लगाए बसों के रूट आदि को सेंसर तकनीक से जोड़ने की दिशा में पहल हो चुकी है। बार्सिलोना को लेकर यह दावा भी किया जाता है कि यह दुनिया का सबसे आगे बढ़ चुका स्मार्ट शहर है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना केवल उन्हीं शहरों तक सीमित हो सकती है जो नए बसाए जा रहे हैं इस मामले में फ्रांस के चर्चित शहर पेरिस को नजीर के तौर पर रखा जा सकता है।

पेरिस एक पुराना शहर है जो परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव को न सिर्फ स्वीकार करता रहा है बल्कि खुद को विकसित भी करता रहा है। यही वजह है कि इक्कसवीं सदी में प्रमुख पेरिस एक पर्यटन का शहर है लेकिन यह 1853 तक एक बेहद गंदा शहर होता था लेकिन 1853 में बेरन हासमन ने पेरिस के उद्धार की दिशा में बड़ा काम किया। सड़कें सुधारी गईं, सुदूर क्षेत्रों से इसे जोड़ा गया और पेरिस को सड़कों के क्षेत्र में समृद्ध बनाया गया। आज पेरिस स्मार्ट सिटी के मानदंडों पर भी खुद को साबित करने की दिशा में उसी तरह बढ़ चुका है जिस तरह 1853 में तत्कालीन जरूरतों के अनुरूप खुद को बदलने के लिए बढ़ा था।

दुनिया के लगभग हर देश में समाज की बसावट का प्रारंभिक स्वरूप गांव जैसा ही रहा होगा जो बाद में समाज की जरूरतों के अनुरूप नगर अथवा शहर में तब्दील हुआ होगा। भारत ने भी समय के साथ-साथ इस परिवर्तन को देखा है। भारत में भी शहरों का विकास तेजी से हुआ है और हो भी रहा है। बीसवीं सदी में जब तकनीक और विज्ञान ने तरक्की की तो शहरीकरण के स्वरूप में भी बदलाव आया। परिणामस्वरूप अब इक्कसवीं सदी के शुरुआत में बात केवल 'शहर' तक नहीं सिमटी है बल्कि अब बात 'स्मार्ट शहरों' की होने लगी है।

स्मार्ट शहरों की चर्चा हो तो स्विट्जरलैंड का एक शहर ज्युरिख भी उदाहरण के तौर पर रखा जा सकता है। इस शहर की खासियत ये है कि यह शहर देहात क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तकनीक मुश्किल नहीं है। बिना लेट-लतीफ के तकनीक संचालित यातायात इस शहर को स्मार्ट बनाने के लिए पर्याप्त है। वैसे तो अपने अनोखे प्रयोग के लिए जाने जाने वाले कई शहर हैं, मगर ऐसा ही अनूठा एक शहर है डेनमार्क का कोपनहेगन। इस शहर की खासियत है यह शहर हरियाली को हर शर्त पर बचा पाने में कामयाब रहा है। सबसे बड़ा प्रयोग इस दिशा में यह रहा कि कोपनहेगन ने

यातायात के लिए साईकिल को तरजीह दी और पर्यावरण को बचाने के लिए इस जरूरत को स्वीकार किया। आज भी कोपनहेगन में लोग साईकिल को ही अपने शहरीय कार्यों के लिए उपयोग में लाते हैं। अपनी हरियाली के लिए यह शहर दुनिया में नजीर है और खुद को स्मार्ट सिटी के तौर पर स्थापित भी करता है।

चूंकि विविधताओं से परिपूर्ण इस विश्व में जब स्मार्ट सिटी पर चर्चा हो तो स्मार्ट सिटी को भी विविध दृष्टिकोणों से ही देखना उचित होगा। विविध नजरिए से जब हम इस अवधारणा का मूल्यांकन करेंगे तो एक बेहतरीन लक्ष्य की सिद्धि हो सकती है और स्मार्ट सिटी बनाने की परिकल्पना अपने परंपरागत मूल्यों के साथ मूर्त रूप ले सकती है। हालांकि तकनीक के सहारे बसावट को सजाने और संवारने का यह चलन केवल बड़े और खर्चीले प्रोजेक्ट वाले शहरों तक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ग्राम्य जीवन जी रहे समुदायों में भी तकनीकी विकास के साथ अनोखा उदाहरण रखने वालों के उदाहरण दुनिया में मिलते हैं। इजरायल में ग्राम्य जीवन जीने की प्रणाली चलन में है जिसे किबुत्ज़ नाम से जाना जाता है। मूलतया साझा कृषि एवं अन्न उपजाने वाला यह संगठित ग्राम्य जीवन भी अब तकनीक एवं सुविधाओं के लिहाज से अपने समुदाय को विकसित कर रहा है। किबुत्ज़ अंतर्गत ग्राम्य जीवन में भी सौर ऊर्जा के अलावा खेती के अत्याधुनिक तौर-तरीकों पर वहां के लोग बेहतर काम कर रहे हैं। वहां घरों के निर्माण से लेकर रसोई तक में सौर ऊर्जा का सहज उपयोग करने की तकनीकी कोशिश सफलतापूर्वक काम कर रही है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से मिट्टी के बने घरों को पत्तों से ढंककर फिर सोलर ऊर्जा के उपकरण का इस्तेमाल की तकनीक का किबुत्ज़ के लोग बेहतर उपयोग कर रहे हैं।

उपरोक्त तथ्यों पर अगर गौर करें तो यह कहने में किसी को भी दिक्कत नही होनी चाहिए कि अब सामाजिक बसावट में तकनीक का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। तकनीक और उद्योग आश्रित समाज के सामने यह बड़ी चुनौती है कि तकनीक का उपभोग करने की बजाए उपयोग कैसे करें। चूंकि जब हम बदलते तकनीकी दौर में विकास के आधुनिक उपकरणों को उपभोग का माध्यम बना लेते हैं तो प्रकृति से जुड़ी कई ऐसी सावधानियां हाशिये पर चली जाती हैं, जिनका ख्याल नहीं रखना समाज और बनावट एवं बसावट दोनों के लिए खतरनाक होगा।

इस लिहाज से भी दुनिया के शहर ऐसे मिल जाएंगे जो तकनीक का उपभोग तो कर रहे हैं लेकिन तमाम बुनियादी सावधानियों को अमल नहीं ला पा रहे। स्मार्ट सिटी की वर्तमान अवधारणा का आशय महज विकास के अंधाउत्साह से नहीं बल्कि प्रकृति और समाज के बीच संतुलन से है। तकनीकी का उपयोग जितना सुविधा-संपन्न समाज के लिए किया जा रहा है अगर उतना ही प्राकृतिक जवाबदेही के साथ भी किया जाए तो हम जिस बसावट के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे वो स्वत: स्मार्ट होगा। भारत भी इस दिशा में दुनिया के तमाम देशों से सीख लेकर, तकनीक लेकर और विकास की समझ लेकर स्मार्ट सिटी की योजना की तरफ आगे बढ़ने को तैयार दिख रहा है। इसमें कोई शक नही कि भारत सक्षम भी है और यहां संभावना भी है। स्मार्ट सिटी की बुनियाद अगर भारत में पड़ती है तो भारत में कई ऐसे नगर हैं जो भविष्य के स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित हो सकते हैं। ❑

CHRONICLE IAS ACADEMY

Congratulation

to our students selected in CSE 2014

11 IN TOP 100

Rank 9

Rank 14

AIR 17, 45, 52, 55, 74, 87, 95, 99 & Many Others...

TOTAL SELECTIONS 175+

Subject to internal audit*

आईएएस 2016

नवीन बैच

सिविल सेवा परीक्षा

फाउन्डेशन बैच – 2016

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

Admission Open

*Limited Seats

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा कार्यक्रम 2015

सामान्य अध्ययन 2015 गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम — 7th Sept

सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा का सह-संबंधता एवं अनुप्रयोग

मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज — 20th Sept

निबन्ध — 25th Sept

वैकल्पिक विषय

■ इतिहास ■ समाज शास्त्र

योजना के पाठकों के लिए 5% की विशेष छूट

कूपन वैधता 1 सितंबर 2015

नामांकन के समय इस कूपन को साथ लाएं या 25000/- रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ इस कूपन को भेजें।

Civil Services CHRONICLE

25yrs of Guiding Success

NORTH CAMPUS (DELHI CENTRE)

2520, Hudson Lane, Vijay Nagar Chowk,

Delhi-9 (Near GTB Metro Station)

SMS: "CAMPUS YE" to 56677 Call: 8800495544

For Online Registration : visit : http://www.ias100.in/payment1.php

Visit : www.chronicleias.com

YH-139/2015

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

भारत सरकार के ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालयों की बिहार में पहलें

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

- बिहार राज्य को वर्ष 2014-15 के दौरान 959.68 करोड़ रुपये और वर्ष 2015-16 में 1024.12 करोड़ रुपये रिलीज किए गए।
- कृषि, मृदा एवं जल संरक्षण और संबंधित कार्यकलापों पर जोर देते हुए राज्य में 5 लाख कार्य शुरू किए गए।
- वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य में 83.6 लाख श्रम दिवसों का सृजन हुआ (अनुसूचित जातियों के लिए 24.79% श्रम दिवस और महिलाओं के लिए 42.9% श्रम दिवस)।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

- बिहार राज्य को वर्ष 2014-15 में 1034.88 करोड़ रुपये रिलीज किए गए और वर्ष 2015-16 में 1032.03 करोड़ रुपये आबंटित किए गए।
- वर्ष 2014-15 और 2015-16 में बिहार राज्य को इंदिरा आवास योजना के 5.60 लाख मकान उपलब्ध कराए गए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

- बिहार राज्य को वर्ष 2015-16 में 2280 करोड़ रू. का आवंटन किया गया जो कि पिछले वर्ष के आबंटन से 47% और वर्ष 2013-14 के आबंटन से 160% अधिक है।
- वर्ष 2014-15 और 2015-16 में राज्य में कुल 4697.42 कि.मी. लंबी पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण किया गया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

- वर्ष 2014-15 और 2015-16 में 53 लाख लाभार्थियों को कवर करते हुए बिहार राज्य को 918.92 करोड़ रुपये रिलीज किए गए।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

- बिहार की 168 ग्राम पंचायतें वर्ष 2019 तक आदर्श ग्राम बन जाएंगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

- वर्ष 2014-15 के दौरान, 492670 परिवारों को कवर करते हुए लगभग 41245 स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को एसआरएलएम द्वारा सहायता दी गई और 1718 ग्राम संगठनों (वीओ) को बढ़ावा दिया गया।
- 16689 स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) ने परिक्रामी निधि (आरएफ) प्राप्त की और 25.01 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

भूमि संसाधन

- बिहार राज्य में समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत 6.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए 840.93 करोड़ रुपये के आवंटन से अब तक 123 परियोजनाओं को मंजूर किया गया।
- राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भू-अभिलेखों और राजस्व सर्वे मानचित्रों के कम्प्यूटरीकरण के लिए बिहार राज्य को 77.32 करोड़ रुपये रिलीज किए गए।

पंचायती राज

- 14वें वित्त आयोग के अनुसार, बिहार की 8971 पंचायतों को वर्ष 2015-16 में 2269 करोड़ रुपये तथा 5 वर्षों (2015-2016 से 2019-2020) में 21000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

- वर्ष 2014-15 और 2015-16 की पहली छमाही के दौरान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु बिहार राज्य को 473.07 करोड़ रुपये रिलीज किए गए। बिहार राज्य में अब तक 12236 ग्रामीण बसावटों को लाभान्वित किया गया है और वर्ष 2015-16 के दौरान 5480 अन्य ग्रामीण बसावटों को लाभान्वित किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- अक्टूबर, 2019 तक देश को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त करने के लिए, भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।
- बिहार राज्य को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण में परिवारों को सहायता प्रदान करने और साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं शुरू करने के लिए एसबीएम(जी) के तहत केंद्रीय अंश के रूप में 361.22 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।
- बिहार में 26 मई, 2014 से 04 अगस्त, 2015 तक 203247 वैयक्तिक शौचालयों का निर्माण कराया गया।

pmindia.gov.in पर प्रधानमंत्री जी से संपर्क किया जा सकता है वेबसाइटः www.rural.nic.in फेसबुकः www.facebook.com/IndiaRuralDev MyGov.in पर अपनी सलाह, विचार और राय भेजें।

davp 35101/13/0011/1516

YH-150/2015

प्रकाशक व मुद्रकः डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादकः ऋतेश पाठक

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2015-17
Reg.No. D.L.-05/3231/2015-17 at RMS, Delhi
23 अगस्त, 2015 को प्रकाशित • 29-30 अगस्त, 2015 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2015-17
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

उपकार बैंक

Just Released

नवीन पाठ्यक्रमानुसार

प्रोबेशनरी ऑफीसर्स/
मैनेजमेंट ट्रेनीज

IBPS
PO/MT

सम्मिलित लिखित प्रारम्भिक परीक्षा
(मॉडल प्रश्न-पत्र हल सहित)

अंग्रेजी भाषा
तर्कशक्ति
संख्यात्मक अभियोग्यता

आई.बी.पी.एस.
द्वारा आयोजित

Code 2371 ₹ 195.00

Code 2372 ₹ 150.00

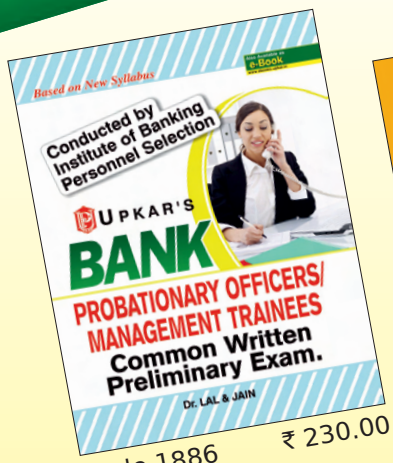

Code 1886 ₹ 230.00

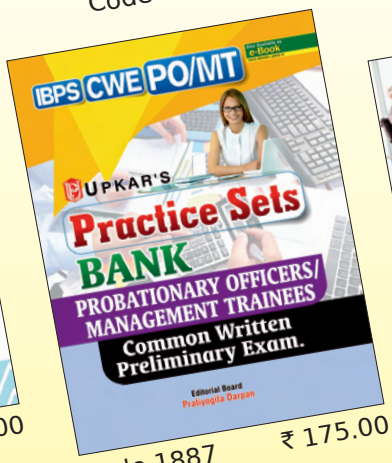

Code 1887 ₹ 175.00

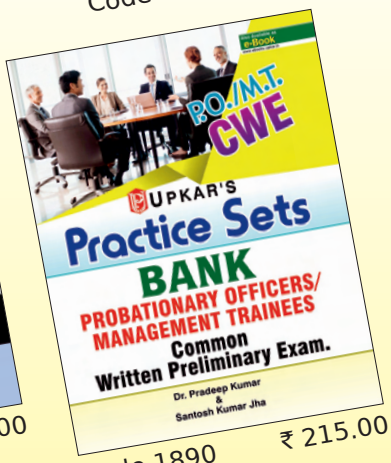

Code 1890 ₹ 215.00

उपकार प्रकाशन (An ISO 9001:2000 Company) | 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 66753330 • पटना 2673340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 7060421008

YH-131/2015